Uncorrected/ Not for Publication-06.08.2010

KSK/DS/11.00/1A

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

***

प्रश्न संख्या -181

प्रो. अलका क्षत्रिय: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या यह सच है कि देश के गरीब और हाशिये पर खड़े लोगों को आर्थिक विकास का लाभ मिल सके और देश की बढ़ती आबादी को भोजन मिल सके, इसके लिए सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लाना चाहती है? अगर हाँ, तो सरकार की खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ किसको देने की मंशा है? क्या मौजूदा सालाना दो प्रतिशत के कृषि उत्पादन के ग्रोथ रेट से यह संभव है? क्या सरकार ने इसका कोई आकलन किया है?

श्री शरद पवार: महामहिम राष्ट्रपति जी की पार्लियामेंट में जो स्पीच हुई थी, उसमें सरकार की नीति साफ बतलायी गयी थी। स्पीच के मुताबिक यह बात सदन के सामने रखी गयी थी कि देश की जो below poverty line पॉपुलेशन है, उसे wheat and rice तीन रुपये किलो के हिसाब से 25 किलो तक देने की नीति पर यह सरकार अमल करेगी। सरकार की thinking इस लाइन पर जाने की है, मगर सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह 25 किलो होगा, 30 किलो होगा या फिर 35 किलो होगा। इस पर राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति नहीं है। सरकार यह करना चाहती है, वह बिल लाना चाहती है और इसके बारे में राज्य सरकार और बाकी संगठनों के साथ सलाह-मशविरा करने की प्रक्रिया चल रही है।

प्रो. अलका क्षत्रिय: सर, मैंने पूछा था कि क्या मौजूदा ग्रोथ रेट के आधार पर यह संभव है, उसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न यह पूछना चाहती हूँ कि योजना आयोग के अनुमान के अनुसार, अनाज से लदे ट्रकों से करीब दो फीसदी अनाज तय

स्थानों तक पहुँचने से पहले गायब हो जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार कानून का उल्लंघन करने वालों और घोटाले करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक सुविधाओं के क्रियान्वयन के प्रति जवाबदेही तय करने का प्रावधान इस विधेयक में रखना चाहती है या नहीं? इसके साथ ही, लक्षित परिवार तक पहुँचने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनायी है? उन्हें सब्सिडी देने का जो प्रावधान है, क्या उसमें कोई फेरबदल करने का भी विचार है?

श्री शरद पवार: जहाँ तक पहले सवाल का संबंध है, भारत सरकार ने दोनों सदनों के सदस्यों के सामने जो commitment की थी, उस पर अमल करने के लिए जितने अनाज की आवश्यकता है, उतनी उपलब्धि अपने देश में आज भी है और यह रहेगी, यह हमारा विश्वास है, इसमें कमी नहीं आएगी। जहाँ तक बंटवारे की बात है, इस बारे में एक बात ध्यान में रखनी होगी कि Public Distribution System में कुछ भारत सरकार की जिम्मेदारी है और कुछ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार की एक जिम्मेदारी किसानों को ठीक तरह से अनाज की कीमत देना, उनसे अनाज खरीदना और प्लानिंग कमीशन की जो सिफारिश है, उसके आधार पर इसका आवंटन करना है। तो procurement and allocation to the states, यहाँ तक भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभायेगी।

जहाँ तक खेत के बाद परिवार के घर में अनाज पहुँचाने की जिम्मेदारी की बात है, इसका पूरा बंदोबस्त राज्य सरकार को करना पड़ता है और इसमें जो कुछ गलत काम होते हैं, उसकी शिकायत जाती है। इसे दुरुस्त करने के लिए हमने देश के सभी खाद्य मंत्रियों और देश के सभी खाद्य सचिवों के साथ दो-तीन बार बैठकर सुझाव दिए हैं और हम यह अपेक्षा करते हैं कि इस पर वे अमल करेंगे और ऐसी समस्या को कम करने के लिए भारत सरकार को सहयोग देंगे।

(1बी/एनबी पर आगे)

NB/SK/1B/11.05

श्री ब्रजेश पाठक : सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस गंभीर प्रश्न पर सप्लीमेंटरी पूछने का मौका दिया। देश में जितने गरीब लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, उनको भोजन मिलने के हक का जो सवाल है, उसके तहत इस देश में BPL सूची बनी, लेकिन जो सूची बनी, वह आधी-अधूरी थी। इसलिए केन्द्र सरकार ने इसके बारे में विचार करने के लिए सक्सेना समिति और तेंदुलकर समित का गठन किया और उन्होंने पाया कि हिंदुस्तान में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत से लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, जिनको दोनों समय का भोजन नहीं मिल रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जो 1.06 करोड़ लोगों की BPL की सूची है, क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार के इस अनुरोध पर विचार करेंगे कि जो गरीब लोग इस सूची में शामिल नहीं हैं, उनको भी इस सूची में शामिल किया जाए?

श्री शरद पवार : सभापति जी, BPL, AAY & APL की सूची बनाने की जिम्मेदारी प्लानिंग कमीशन को दी गई थी। एक साल पहले देश के चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में कई राज्यों ने यह डिमांड की थी कि इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है, इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, जिस पर भारत सरकार ने विचार किया और प्लानिंग कमीशन को यह जिम्मेदारी सौंप दी। प्लानिंग कमीशन की तरफ से मुझे बताया गया है कि तेंदुलकर समिति की जो recommendations हैं, उनके आधार पर एक महीने में नयी सूची बनाई जाएगी और हर राज्य में कितने लोग BPL में आएंगे, AAY में आएंगे, APL में आएंगे, यह संख्या हर राज्य को बताई जाएगी । मैं इतना ही भरोसा दिलाना चाहता हूं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो या कोई भी राज्य हो, प्लानिंग कमीशन पुरानी सूची में सुधार करके जो अंतिम फिगर्स हमारे पास देगा, जो नए आंकड़े देगा, उनको मद्देनज़र रखते हुए, भारत सरकार उनके लिए

आवंटन की जिम्मेदारी लेगी और प्लानिंग कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य सरकारों को अनाज देने का प्रबंध करेगी।

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, the World Food Summit held in 1996, known as Rome Declaration on World Food Security, passed a resolution that "We the heads of the State and Government...reaffirm the right of everyone to have physical and economic access to safe and nutritious food, consistent with the right of adequate food and the fundamental right of everyone to be free from hunger". India is one of the signatories to this Declaration. I would like to know, through you, Sir, when is the Government of India going to ratify this through an Act and provide safe food to each and every Indian, whether he is a poor or a middle class person or a person living above poverty line at affordable prices?

SHRI SHARAD PAWAR: If he recollects the statement of the hon. President in the last Parliamentary Session, the hon. President said 'food for all and at special rates for those who are below poverty line'. So, the Government of India's total approach is to take the responsibility of food for all, and special precaution will be taken for the section which is vulnerable.

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिस बात का उल्लेख किया था, क्या देश के तीन-चौथाई जिलों में 3 रुपए प्रति किलो के मूल्य पर 35 किलो अनाज देने के बारे में केन्द्र सरकार विचार कर रही है? चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपनी सिफारिश की हो या न की हो, लेकिन क्या माननीय मंत्री जी इस पर निर्णय लेने की स्थिति में हैं? आपने बताया कि प्लानिंग कमीशन से BPL और APL के बारे में जानकारी ली जा रही है।

(1C/VNK पर क्रमशः)

(Q.NO. 181 - contd.)

श्री मोती लाल वोरा (क्रमागत): माननीय सभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनाज का भंडार काफी है और अनाज के गोदामों में अनाज सड़ रहा है। जब अनाज की कमी नहीं है, तो सरकार का जो निर्णय है कि देश के तीन चौथाई जिले में लोगों को 25 किलो अनाज 3 रुपए प्रति किलो की दर से देंगे, उस पर सरकार अमल करने की दिशा कब तक विचार करेगी?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, it is the desire of the Government of India to introduce the scheme, if possible, with effect from 2nd October 2010.

(Ends)

प्रश्न संख्या : 182

श्री नंद कुमार सायः माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया है कि राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कायिक निधि वाली योजना को ब्याज दर में कमी होने के कारण समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है और उसके प्रत्येक वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वार्षिक बजट का प्रावधान किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चूंकि वार्षिक आवश्यकता छात्रों की संख्या पर निर्भर करेगी, इसलिए इसके लिए छात्रों का चयन कैसा किया जाएगा, कब किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी, जिसके आधार पर आप प्रत्येक वर्ष बजट का प्रावधान कर सकेंगे?

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I thank the hon. Member for this question. मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह जो process है, यह तो already तय है। तय इसलिए है, क्योंकि यह स्कीम already लागू है। इसमें जो परिवर्तन हुआ है, वह केवल यह हुआ है कि पहले हमने सोचा था कि अगर हम तीन साल में 3000 करोड़ का corpus create करते हैं, जिनमें पहला tranche 750 करोड़ का था, फिर 1500 करोड़ हो जाता और इस तरह से तीन साल में 3000 करोड़ हो जाता, अगर उसमें हमें 8 परसेंट ब्याज मिलता, तो उस ब्याज के द्वारा हम इस स्कीम को चला सकते थे, लेकिन हमने देखा कि जब हमने 750 करोड़ देकर corpus create किया, तो उसके तुरंत बाद ब्याज दर 9 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत पर आ गया। इसके बाद हमने सोचा कि अब हम ब्याज के द्वारा तो इस स्कीम को चला नहीं सकते हैं, इसलिए फैसला किया कि जो deposit है, उसको रद्द कर देते हैं और हमने उसको अभी 2010 में रद्द कर दिया। इसमें सालाना एलोकेशन होगा। सालाना एलोकेशन के द्वारा जितने भी छात्र Means-cum-Merit Scholarship इम्तिहान के द्वारा आएंगे, उनको ये scholarship दिए

जाएंगे, लेकिन यह स्कीम लागू करने के बाद स्टेट्स के द्वारा उतने बच्चे नहीं आए, जितने को कि इस स्कीम के द्वारा फायदा हो सकता था।

श्री नंद कुमार सायः सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। यद्यपि प्रदेश के द्वारा छात्रों का चयन होता है, लेकिन इस स्कीम के तहत ऐसी कोई योजना है कि उसी परिवार के छात्र का इसके तहत चयन होगा, जिस परिवार की वार्षिक आमदनी 1,50,000 रुपए है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ लचीलापन रखा जाए, ताकि छात्रों का चयन किया जा सके। आपने 2008-09 ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः कृपया एक सवाल पूछिए।

श्री नंद कुमार सायः महोदय, यह उसी से जुड़ा हुआ है। 2008-09 में 33 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के कक्षा IX के चुनिंदा छात्रों हेतु 54,564 छात्रवृत्तियां और 2009-10 हेतु 24,521 छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने की जानकारी दी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि आपने ये जो छात्रवृत्तियां स्वीकृत की हैं, इनमें छत्तीसगढ़ के कितने हैं और जनजाति वर्ग के कितने हैं?

(1d/MP पर आगे)

MP-MKS/1D/11.15

श्री कपिल सिब्बल : सर, जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, अगस्त, 2008 में 1,346 students ने इसमें इम्तिहान दिया और 115 को स्कॉलरशिप मिली, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए हमने जो मापदंड रखा है, उस मापदंड को वे तय नहीं कर पाए। उसके बाद नवंबर, 2008 में 337 students appear हुए, जिनमें से 67 को स्कॉलरशिप मिली। नवंबर, 2009 में 5,833 appear हुए, जिनमें से 2008 को स्कॉलरशिप मिली, तो यह स्थिति है। जहां तक इस स्कीम का सवाल है, इस स्कीम में मापदंड यह है कि आपको 40 परसेंट नंबर लेने होंगे in your class IX, फिर एक इम्तिहान में बैठना होगा SAT and MAT में, यह सब स्कीम में

लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप class X में जाओगे, तो एक इम्तिहान और होगा, उसमें आपको 55 परसेंट नंबर लेने होंगे। SCs/STs को थोड़े कम नंबर लेने होंगे, तो ....(व्यवधान)...

श्री नंद कुमार साय : वही मैं जानना चाहता था कि एस.सी./एस.टी. को ....

MR. CHAIRMAN: No discussion now. Thank you.

श्री कपिल सिब्बल : वह तो सब मापदंड के द्वारा ही होता है।

DR. JANARDHAN WAGHMARE: I would like to ask a question from the hon. Minister, through you, Sir, whether the Government has any proposal to give scholarships to students belonging to the weaker sections irrespective of their caste, not on merit basis, but because of their poor conditions; and whether the Government has any affirmative action plan to help the poor people.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, this is a question which is much wider than the issue that is before the House pursuing the question that is being asked. There are several schemes of the Government of India where we are, actually, targeting our women from weaker sections; there are several schemes of the Government of India where we target Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There is no such scheme which targets all the poor in this country. There is no such scheme of the Government of India. Therefore, this particular question is much larger. The issue that you have raised is much larger than the question that needs to be answered.

MR. CHAIRMAN: Shri Mohapatra.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, the Minister knows the reasons for which a corpus of Rs.3000 crores which was envisaged, which would have, even on a low interest rate, brought in 2.5 crores of rupees annually for the scholarship as interest, was formed. Why was it whittled down to Rs.1000 crores and why, even with a Rs.90-crore allocation for the current year, is the number of scholarships coming down? The number of States is also coming down, as per your reply, from 33 to 27. And the number of scholarships has come down to almost 55 per cent. Is it because of inadequacy of the scholarships that the students are not applying or is it because of some criteria which are found to be too difficult considering the quantum of scholarships?

SHRI KAPIL SIBAL: It can be neither, Sir. It is not because of the inadequacy of the scholarships. Take, for example, a State like Madhya Pradesh. In the year 2008, 18,000 appeared, and in November, 2009, only 5,662 appeared. So, it is not because of the fact that the numbers are going down. Why? If 18,000 could appear the previous year, why should they come down to 5,000? So, this is inexplicable. Probably, one of the reasons could be that the States are not reaching the schemes to the districts so that schools in districts know that there is a scholarship available. That could be one thing. There could be another thing. Maybe, their States could have other schemes which may be better than these schemes; so, the children are going to those schools; I do not know. But these are very strange figures of States which have done well in the first year, but the numbers are going down now. So, I think, it lies with the States to find out as to

why that is happening. As far as their criterion is concerned, if 18,000 could appear the earlier year, why should a less number of students appear this year? There is no problem relating to the criteria as well.

And as far as Orissa is concerned, no proposal has been received from Orissa so far. It is very strange that there is a scheme offered and the State does not send a proposal.

श्री मोहम्मद अदीब : सभापति महोदय, मैं मिनिस्टर साहब के जवाब से समझ नहीं पाया, यह उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि corpus खत्म करके yearly basis पर mark किया कि इतना payment दिया जाएगा, लेकिन अभी मंत्री जी ने यह कहा कि जितनी स्कॉलरशिप है, उतने बच्चे नहीं हैं।

(1E/SC पर क्रमशः)

श्री मोहम्मद अदीब (क्रमागत) : यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही। इस मुल्क में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो गरीब भी हैं और जिनमें सलाहियत भी है। मुझे लगता है कि हमारी मिनिस्टरी बच्चों तक communicate नहीं कर पा रही कि ये-ये सुविधाएं सरकार दे रही है। सर, अंग्रेजी अखबार को बहुत से गांवों में गरीब बच्चे नहीं पढ़ते हैं इसलिए अगर हुकुमत यह कोशिश करे कि regional अखबारों में, छोटे अखबारों में, उर्दू के, हिन्दी के अखबारों में या अन्य छोटी-छोटी languages के अखबारों में अगर स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताया जाए तो मुझे यकीन है कि जितना पैसा आपने allocate किया है, वह भी कम पड़ जाएगा। क्या आप इस बारे में कुछ करेंगे?

جناب محمد ادیب : سبھا پتی مہودے، میں منسٹر صاحب کے جواب سے سمجھہ نہیں پایا، یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ corpus ختم کرکے yearly basis پر مارک کیا کہ اتنا payment دیا جائے گا، لیکن ابھی منتری جی نے یہ کہا ہے جتنی اسکالرشپ ہے، اتنے بچے نہیں ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھہ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس ملک میں کروڑوں بچّے ایسے ہیں جو غریب بھی ہیں جن میں صلاحیت بھی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری منسٹری بچوں تک کمیونکیٹ نہیں کر پا رہی کہ یہ-یہ سویدھائیں سرکار دے رہی ہے۔ سر، انگریزی اخبار کو بہت سے گاؤں میں غریب بچے نہیں پڑھتے ہیں اس لئے اگر حکومت یہ کوشش کرے کہ ریجنل اخباروں میں، چھوٹے اخباروں میں، اردو کے، ہندی کے اخباروں میں یا دیگر چھوٹی چھوٹی لینگویجس کے اخباروں میں اگر اسکالرشپ اسکیم کے بارے میں بتایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ جتنا پیسہ آپ نے ایکوکیٹ کیا ہے، وہ بھی کم پڑ جائے گا۔ کیا آپ اس بارے میں کچھہ کریں گے؟

श्री कपिल सिब्बल : सर, माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। हम भी चाहते हैं कि जो प्रदेश हैं, वे इस स्कीम को लागू करने के लिए लोकल न्यूज़ पेपर्स में विज्ञापन दें और हर डिस्ट्रिक्ट तक इसे पहुंचाएं तभी बच्चों को पता चलेगा कि ऐसी स्कीम लागू है जिसमें उन्हें पांच सौ रुपए महीना और 6 हज़ार सालाना मिल सकता है। हम स्टेट्स से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको आगे बढ़ाएं।

(समाप्त)

SHRI V. HANUMANTHA RAO: Sir, in his reply, price fixation has not taken into consideration the production of ethanol and the production of electricity from molasses.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, the formula has been changed. Sir, certain factors are taken into consideration when we decide the price, that is, cost of production of sugarcane, returns to the growers from alternative crops, general change in prices of agricultural commodities, availability of sugarcane to the consumer at fair price, price at which sugar produced from sugarcane is sold by the sugar factories, recovery of sugar from sugarcane and realisation made from sale of by-products like molasses, bagasse, etc. and their important value. So, the hon. Member is asking this question. Sir, that particular aspect has been kept in mind and price has been fixed on the basis of that.

SHRI V. HANUMANTHA RAO: What made the Government to take up the issue for consideration, firstly, PDS sugar be procured from the open market and secondly, sugar be removed from the purview of the Essential Commodities Act? Sir, both these issues will disarm the State Governments and it will be an anti-people proposal.

SHRI SHARAD PAWAR: It's not a Government decision. This is a demand from ISMA, the Indian Sugar Mill Association and the National Federation of Cooperative Sugar Factories. They have given a memorandum. In that memorandum, these are the demands which have been put forward before the Government. The Government has not taken any final view. We will definitely

consult the State Governments. We will see the crop conditions; we will see the overall sugarcane and sugar availability in the country; we will see the prices for consumers and producers in the country; and, then, we will apply our mind.

SHRI M.V. MYSURA REDDY: Sir, sugar is procured for the PDS. Manufacturers of aerated drinks, sweets and confectioners are also consuming it. Sir, through you, I am seeking a clarification from the Minister about the average percentage of sugar consumption by various consumers.

SHRI SHARAD PAWAR: Generally, about 65 per cent sugar which has been produced in this country is used by this type of organised sector and rest of it by public at large.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सभापति महोदय, चीनी मिल मालिकों और गन्ने के किसानों का रिश्ता घोड़े और घास जैसा है। मिल मालिक चाहता है कि उसे सस्ते से सस्ता गन्ना मिले, उसकी लागत कम से कम आए और उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। दूसरी ओर इस देश में किसान इस बात से परेशान है कि उसको अपने गन्ने की वाजिब और लाभकारी कीमत नहीं मिल पाती।

(1एफ-एमसीएम पर क्रमश:)

-VKK-TMV-MCM/1F/11.25

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (**क्रमागत**) : अब यहां जो मांग की गई है, जो आज सवाल है जिसमें पूछा गया है कि चीनी मिल मालिकों ने मिलकर के सरकार से यह मांग की है कि गन्ने की कीमत इस आधार पर तय की जाए कि चीनी बेचने परउनको मार्केट से कितना मुनाफा मिल रहा है। तो उनके मुनाफे के आधार पर गन्ने की कीमत तय करने की उन्होंने मांग की है। श्रीमन, यह कुछ ऐसी बात है जैसे पहले तो घोड़े के नाप की जीन खरीदी जाती थी, अब जीन की नाप का

घोड़ा तलाशने की बात की जा रही है। तो जीन की नाप का घोड़ा तलाशने के लिए सरकार से मांग की गई है।

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : श्रीमन, मेरा प्रश्न केवल यह है कि सालों से किसान गन्ने के लिए यह मांग करता आ रहा है कि जिन पैरामीटर के आधार पर सी0ए0सी0पी0 द्वारा उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन केलकुलेट की जाती है, वह पैरामीटर बहुत पुराने हो चुके हैं, बेईमानी हो चुके हैं और अब नए संदर्भ में नए पैरामीटर बनने चाहिए जो उसका वास्तविक मूल्य आकलन कर सकें कि गन्ने की कितनी उत्पादन लागत आ रही है। इस पैरामीटर को बदलने के लिए और गन्ने के वास्तविक उत्पादन की लागत की कीमत को एसेस् करने के लिए, आकलन करने के लिए क्या सरकार कोई विशेष कदम उठा रही है? अगर हां, तो क्या और कब तक उसे पूरा कर लिया जाएगा?

श्री शरद पवार : कीमत तय करने के लिए जो आज तक का क्राइटेरिया था, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, इस तरह की मांग सदन के सामने भी थी और बाहर किसानों की तरफ से भी थी। इसको भारत सरकार ने स्वीकार किया, Sugarcane (Control) Order, 1966 में 22nd October, 2009 में एक नया क्लॉज डालकर इसमें fair remunerative price किस तरह से देनी चाहिए.....(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यह सब तो जवाब में लिखा हुआ है।

श्री सभापति : आप पहले सुन लीजिए।

श्री शरद पवार : किस तरह से देनी चाहिए, इस तरह की कार्रवाई सरकार ने इससे पहले ही की है। मैंने इससे पहले जो बतलाया कि इसका जो क्राइटेरिया किया है, वह क्राइटेरिया साफ है। भले ही चीनी मिलों ने मांग की होगी या और किसी ने मांग की होगी, मगर किसानों को उचित कीमत मिलने के इश्यु पर भारत सरकार कम्प्रोमाइज नहीं करेगी, system dilute नहीं

करेगी और एक साल पहले ही इसमें जो सुधार किया है, इस पर पूरी तरह से अमल करने का प्रयास करेगी।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : श्रीमन, हमको आपका संरक्षण चाहिए।

MR. CHAIRMAN: No supplementary on supplementary, please.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : श्रीमन, ऐसा है कि अगर हमारे प्रश्न का जवाब आ जाए, वह जो भी जवाब दें.....(व्यवधान)

श्री सभापति : देखिए, आप क्लेरिफिकेशन मंत्री जी से अलग ले लीजिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्लेरिफिकेशन नहीं, श्रीमन, यह तो आपको भी देखना होगा कि आखिर हमारे साथ न्याय हो।.....(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: We can't have a discussion here.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : जो पैरामीटर सी0ए0सी0पी0 के हैं उनको बदलने के लिए सरकार क्या कोई कार्रवाई कर रही है? यदि हां, तो कब तक? इस मसले पर मंत्री जी कुछ तो कहें।.....(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : सर,यह सही है, इस पर अलग से चर्चा करा दीजिए।

श्री सभापति : आप उसका नोटिस दीजिए।

श्री वीर पाल सिंह यादव : माननीय चतुर्वेदी जी ने जो पूछा है उसी से मिलता-जुलता सवाल मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। चीनी उद्योग के मालिकों को लाभकारी मूल्य देने का आपने कानून पास कर दिया और पिछले दिनों उसका अध्यादेश जारी हो गया। हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि पहले से किसानों से वायदा किया जा रहा था कि गन्ने पर किसानों की जो लागत आती है उसका लाभकारी मूल्य सरकार तय करेगी और मिल मालिकों को एक तरह से मजबूर करेगी उतना मूल्य देने के लिए। तो क्या चीनी मिल मालिक अपनी चीनी का

लाभकारी मूल्य तय करके देंगे या किसान के गन्ने का लाभकारी मूल्य तय करके देंगे, यह माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें?

श्री शरद पवार : किसानों के गन्ने की कीमत तय करने का अधिकार चीनी मिलों को नहीं दिया है। इसके लिए एक independent organisation CACP है। CACP इसकी कीमत तय करेगी। मैंने जो कहा कि 2009 और 2010 में जो बदलाव किया, इस बदलाव से 2009-2010.....

(1g/GS पर क्रमशः)

VK-GS/1G/11.30

SHRI SHARAD PAWAR (CONTD): In 2009-10, the FRP which was given to the farmers, was 51 per cent higher than the SMP which was paid in 2008-09; it was Rs. 28.8 per quintal higher than the SMP earlier fixed at Rs. 107.76. When we changed the system, farmers started getting better price. Last year was one of the years when sugarcane farmers got excellent price throughout India.

(Ends)

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, माननीय मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है, उसको मैंने पढ़ा है और वह बहुत ही विस्तार में है। सरकार ने काफी कुछ farmers के लिए किया है और करने जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो कुछ यहां पर टेक्नोलॉजी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है, क्या इसके लिए इन्होंने कोई मानिटरिंग कमेटी बनाई हुई है ? जो सरकार के farmers के लिए प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में क्या मंत्रालय ने स्टेटों से फिगर्स मंगवाई हैं ? कितनी धनराशि ग्राम पंचायतों को दी गई है और उससे कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है या सिर्फ यह पेपर्स में ही हो रहा है, यह मैं जानना चाहती हूं?

PROF. K.V. THOMAS: Sir, the question was, "Whether the National Commission on Farmers (NCF) has recommended training of Panchayat Members..." In the reply, I have said that on the basis of the recommendation of the National Commission on Farmers recommendation as well as the Draft Policy, we are helping the Panchayats so that the agricultural activities can be augmented through the Panchayats.

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, मैं सेकेंड सप्लीमेंट्री बाद में पूछूंगी। अभी मंत्री जी ने मेरे पहले सवाल का ही उत्तर नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछ रही हूं कि जो इन्होंने स्कीमें चलाई हैं, उनके बारे में क्या स्टेटों से फीड बैक आया है ? इनकी स्कीमों से कितने लोगों को फायदा हुआ है, कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है ? सर, मेरे पहले सवाल का ही जवाब नहीं आया है। सर, मैं सेकेंड सवाल बाद में पूछूंगी। सर, यह तो कोई बात नहीं हुई कि मंत्री जी जवाब ही नहीं देते हैं। इतना इन्होंने बताया है।...(व्यवधान).... हमने यह पूछा है, इसलिए मैं यह जानना चाहती हूं कि ...(व्यवधान)....

श्री राजीव प्रताप रूडी : यही बात मैं उस दिन कह रहा था कि मंत्री जी जवाब नहीं देते हैं।...(व्यवधान)....

(Q.NO. 184 - contd.)

श्री सभापति : अगर आपको सेटिसफेक्टरी जवाब नहीं मिलता है, तो आप उसके लिए नोटिस दीजिए। ...(व्यवधान)....

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, यह तो ठीक है।...(व्यवधान).... मंत्री जी, जवाब तो दें। इनको जो रिटन में दिया जाता है, उसको ही यहां पढ़ देते हैं, जो मैं पूछ रही हूं, उसका जवाब मंत्री जी नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान)....

MR. CHAIRMAN: Please do clarify the position.

PROF. K.V. THOMAS: Sir, I have got the details of the number of persons in the Panchayat institutions which have been trained. I have got a detailed list. I will pass it on to the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: The information is there. It will be made available to you.

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, मेरा सेकेंड सप्लीमेंट्र क्वेश्चन है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सरकार एनसीएफ के माध्यम से सहायता दे रही है। मैं यह जानना चाहती हूं कि आप किस प्रकार की सहायता दे रहे हैं ? क्या ग्राम पंचायतों को सरकार यहां से आर्थिक तौर पर सहायता दे रही है, और अगर दे रही है, तो कितनी सहायता दे रही है ? क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना और बैकवर्ड क्षेत्र के प्लान के के बारे में बताया है, लेकिन यह उससे भी पूरा होने वाला नहीं है ? क्या ये और भी आर्थिक सहायता ग्राम पंचायतों को देने वाले हैं ?

PROF. K.V. THOMAS: Sir, according to this policy, one woman and one man is selected by each Panchayat with the help of agricultural/animal sciences universities. We also give financial assistance under various schemes, like the

RGSY so that the State Governments can help in strengthening agriculture activities through the Panchayats.

DR. K.P.RAMALINGAM: Sir, the Minister's reply says that in every Panchayat one woman and one man is going to be selected as Farm Science Manager. This is not enough. Of course, every Panchayat has more than three or four villages.

(Contd. By 1H)

1h/11.35/asc-ks

SHRI K. V. RAMALINGAM (contd.): At least, five farm science managers should be trained in each village. Sir, the nation is very much in need of mechanization of our agriculture. May I know from the hon. Minister whether the farm science managers are going to give training in modern farm equipments for ploughing, seeding, weeding and harvesting. Also, I want to know from the hon. Minister...

MR. CHAIRMAN: Only one question please.

SHRI K. V. RAMALINGAM: ... whether there is any programme for giving training for the manufacture of value-added agricultural products. Are you going to give any stipend to these farm science managers?

PROF. K. V. THOMAS: Sir, the modified scheme of support to State Extension Programmes for extension reform schemes provides one farmer front for every two census villages to facilitate farmer to farmer extension service. The involvement of Panchayat institutions at various levels such as selection of beneficiaries, identification of farmer fronts, selection of farmer teachers for farmer field schools is an integral part of the support to State Extension Programmes.

(Q.NO. 184 - contd.)

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी पूछे गए सवाल का जो जवाब दिया है, उसको देखकर मुझे लगता है कि मंत्री जी ने या तो पूरी तैयारी नहीं की है या फिर वे सवाल का वास्तविक जवाब देने से हिचक रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक पंचायत में एक स्त्री और एक पुरुष को मैनेजर की नियुक्ति के लिए, प्रशिक्षित करने के बारे में सरकार ने सोचा है, विचार किया है या निर्णय किया है। माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी होगी कि एक न्याय पंचायत में एवरेज चालीस से पचास हजार लोगों की जनसंख्या होती है। इस चालीस से पचास हजार लोगों की जनसंख्या के लिए एक स्त्री और एक पुरुष को आपने मैनेजर के रूप में या प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया है, मैं जानना चाहता हूं कि आपने पूरे देश में कितनी पंचायतें तय की हैं और उन पंचायतों में अभी तक कितने शिक्षण के कार्यक्रम हुए हैं?

PROF. K. V. THOMAS: Sir, I have got the State-wise details. For example, if you take Andhra Pradesh, the number of persons trained in 2007-08 is 2,42,611; in 2008-09, it is 1,56,851; in 2009-2010, it is...

MR. CHAIRMAN: Could this information be made available to hon. Members?

PROF. K. V. THOMAS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Shri Ishwar Singh.

श्री ईश्वर सिंह : चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय किसान आयोग ने पंचायत के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण की सिफारिश की है, उनको ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया है, जो एकीकृत नाशीकीट प्रबंधन, एकीकृत पोषक-पदार्थ आपूर्ति और वैज्ञानिक जन-प्रबंधन का है। पंचायत के सदस्य यहां से प्रशिक्षित होकर अपने गांवों में कृषि विज्ञान से संबंधित सेवाएं देंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो भूमिहीन लोग हैं और विशेषकर

अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, क्या उन लोगों कों इसमें पहल दी जाएगी? वे लोग ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि वे साधनहीन लोग हैं। क्या सरकार ऐसा विश्वास रखती है कि उनको पहल दी जाए?

PROF. K. V. THOMAS: Sir, these are all under consideration. Actually, it is the State Governments which are implementing this policy. We have already given these proposals to the State Governments.

(Ends)

SHRI A. ELAVARASAN: Sir, my first supplementary question is that a large number of schools are running with only a single teacher in the country. For example, in Aimoor, a place in Nagapattinam district of Tamil Nadu, there is a secondary school with 500 students but for a very long time the school has been functioning only with one teacher against 11 sanctioned posts of teachers. So, I want to know whether the Government will instruct the State Governments to identify single-teacher schools and take steps to put some teachers from other schools in the other areas in such schools. Also, what steps have been taken by the Government to put a minimum number of teachers for every forty students in schools?

(followed by 1j/kgg)

kgg/lt/1j/11.40

SHRI KAPIL SIBAL: I thank the hon. Member for this question. But, I must say that I do not think that we in the Government of India now want to follow the fashion of instructing State Governments. I think, this is a collaborative exercise between the Government of India and the various States of this country; I think, it is a great national opportunity. If the States and the Government of India work together, we can really transform this country. There is a shortage of 1.2 million teachers in this country. On the one hand we are saying that there is no employment; but, on the other hand, there is a shortage of 1.2 million teachers. That space is vacant, it is open. Why do not the States recruit teachers through their various recruitment policies? We have seen the total backlog is 1.2 million

but there are some States where the backlog is enormous and for years! Take for example Bihar, 2,60,841 is the total sanctioned posts and the backlog is 1,00,696. (Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Mr. Chairman, Sir, the State Government has already started the process. (Interruptions) This backlog is of fifty years and the State Government has already started the process. Why are you specifically mentioning Bihar? (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: What is the point of argument? Please allow Question Hour to proceed.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: We should make it clear that this backlog is for 50 years. (Interruptions) You must talk about this backlog which is for 50 years. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Will you allow the hon. Minister to answer the question? (Interruptions)

श्री रामविलास पासवान : सभापति जी, बोल कौन रहा है..(व्यवधान)..एन.के.सिंह जी, जरा सुनिए..(व्यवधान)..

श्री राजनीति प्रसाद : आप लोग बैठिए..(व्यवधान)..जवाब देने दीजिए..(व्यवधान)..

SHRI S.S. AHLUWALIA: You can give us the figures of 2000-onwards. (Interruptions)

श्री राजीव प्रसाद रूडी : बैकलॉग बताएं..(व्यवधान)..

श्री कपिल सिब्बल : आपको संतुष्टि मिले, इसके लिए मैं राजस्थान के भी आंकड़े दे सकता हूं, इससे आप खुश हो जाएंगे..(व्यवधान)..मेरा यह कोई..(व्यवधान)..

(Q.NO. 185 - contd.)

श्री सभापति : देखिए, please maintain silence. (Interruptions)

श्री राजीव प्रसाद रूडी : बताइए कितने वर्षों से है..(व्यवधान)..

SHRI KAPIL SIBAL: I am giving you. (Interruptions) I am only giving expression to the prevailing situation throughout the country. Now, what is required is that the State Governments should start re-putting the recruitment processes in place, making sure that the recruitment is done so that the availability of teachers in each school is improved; these are the overall figures. As has been rightly pointed out by the hon. Member, you may have a total recruitment policy through which there are enough teachers for schools but in some States in some schools there is only one teacher like what he has pointed out in Tamil Nadu. We are telling the State Governments, redeploy your teachers. Even the political parties have to be careful because what happens is, teachers come to us, 'Please transfer me because my family is there.' We must be clear. We should be open and honest to the people of this country. Hearing them, we then recommend these transfers. The result is, in some schools, there are more teachers than required. In some schools, there are not enough teachers. So, let us introspect. This is not the question of blaming people. Let us introspect. (Interruptions)

श्री भगत सिंह कोश्यारी : सर, ट्रांसफर से क्या मतलब है..(व्यवधान)..आप ट्रांसफर की बात कर रहे हैं..(व्यवधान)..एम्प्लोएमेंट के बारे में बात हो रही है..(व्यवधान)..आप उसकी बात कीजिए..(व्यवधान)..

श्री सभापति : आप नोटिस दीजिए..(व्यवधान).. Can we have a discussion on this?

(Q.NO. 185 - contd.)

SHRI KAPIL SIBAL: This is not adversarial. (Interruptions)

श्री एस.एस.अहलुवालिया : सर,वे गलत बोल रहे हैं..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: All right, agreed. Let us have this discussion. Now, the second supplementary question.

SHRI KAPIL SIBAL: Yes, it is not adversarial. We are talking to Tamil Nadu and all States to make sure that re-deployment is done and there are right and adequate number of teachers for each school. (Interruptions)

SHRI A. ELAVARASAN: I would like to know whether the Government initiate action to undertake campus interviews through State Governments at Government B.Ed. colleges to combat the problem of shortage because a number of students are coming out every year after successfully completing the teacher training courses. If so, the details thereof. If not, the alternative planning proposed by the Government.

(Followed by tdb/1k)

TDB-LP/1K/11.45

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, in fact, I have had a personal meeting with almost every Education Minister of every State. And, we have looked at each State, and the problems that are confronting each State. Remember, this is going to be a collaborative exercise; this is not an accusatory forum. We need to actually talk to the State Governments. The State Governments have problems. Sometimes they want to recruit teachers, there is a court case, and there is a stay on recruitment.

Now, the big problem that we are facing is that there are not enough students going into B.Ed. There are not enough institutes for training teachers.

SHRI S.S. AHLUWALIA: It is because there is no job opportunity.

SHRI KAPIL SIBAL: Job opportunities are there. We have shown you.

SHRI S.S. AHLUWALIA: No, no. (Interruptions)

SHRI KAPIL SIBAL: The job opportunities are there. Therefore, States need to open more B.Ed colleges; States need to open more M.Ed. colleges. States need to open more programmes. Therefore, once that is done, you will have enough recruitment because there is a vacuum. (Interruptions) And that vacuum will have to be... (Interruptions) Therefore, we are requesting the State Governments to open those educational institutions. (Interruptions)

SHRI A. ELAVARASAN: What is the main reason?

MR. CHAIRMAN: Please resume your place. You have put your supplementary. (Interruptions) Shri Shantaram Laxman Naik.

श्री भगत सिंह कोश्यारी : सर, बहुत सारे बी.एड. हैं..(व्यवधान)..लगभग दस हजार बी.एड. हैं..(व्यवधान)..क्या आप उनको नौकरी दिलाइएगा..(व्यवधान)..इतने सारे बी.एड. खाली पड़े हैं..(व्यवधान)..

श्री सभापति : देखिए, ..(व्यवधान).. One minute, please. I think, if there are disputes about official statistics, the only way to counter it is by giving what may be better statistics. But Question Hour is not the time for this kind of a dispute.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Wrong statistics should not be given.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: These statistics are fabricated statistics. (Interruptions) These are fabricated statistics. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Are you suggesting that official statistics of this country are fabricated statistics? (Interruptions) I think, there have been Members from all sides of the House who have been responsible Ministers of the Government. (Interruptions)

श्री रामविलास पासवान : सर, बिहार इस सदन से बाहर है..(व्यवधान)..बिहार का नाम आने के बाद ही ये तिलमिला जाते हैं..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Mr. Shantaram Laxman Naik. (Interruptions)

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, along with the recruitment of teachers, which will now be done in connection with the Right to Education Act, training of teachers is very important. In most of the States, some institutions take initiative, and various institutions are clubbed together for the purpose of giving training. In that training, Sir, what is taught is, only teaching methods. Apart from teaching methods, nothing else is being taught or trained for teachers. I would like to inform that no teacher, hardly any teacher knows about the Education Policy of 1986, as amended in 1991. Will the hon. Minister advise the State Governments that whenever training programmes are held, the teachers should be trained and they should be taught about the essential features of our Education Policy?

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Chairman, Sir, in fact, the essential features of the Education Policy are taught in these educational institutions. It is not correct to say that they are not taught. In fact, the standards are laid down by the NCTE,

and, therefore, it is not correct to say that they are not taught this. Everybody is aware of the Education Policy. The real problem is the attractiveness of the profession. That is the real problem. States need to give more incentives to the teaching community, and all of us need to respect the teacher much more. We don't give enough respect to the teacher. We need to improve their conditions of service at the level of the State; we need to give them more promotional opportunities; we need to give them housing facilities; we need to give them insurance facilities; we need to make the profession attractive. In many other parts of the world, the best minds go into teaching. How is it that that does not happen in India? The fault lies with us.

SHRI SITARAM YECHURY: Finances. Money is the problem.

SHRI KAPIL SIBAL: We need to get together to make sure that enough people go into the teaching profession. In fact, we do an in-service training of teachers for twenty days annually under the Sarva Shiksha Abhiyan, and the pedagogy content is provided by us. So, this is not correct to say that they are not aware of the Education Policy.

SHRI BHARATKUMAR RAUT: Sir, the situation is very intriguing. On the one hand, the hon. Minister is saying that there is a paucity of teachers all over India; on the other hand, there is unemployment among teachers.

(Contd. by 1l-kls)

(Q.NO. 185 - contd.)

KLS/1L-11.50

SHRI BHARATKUMAR RAUT (CONTD): There are many teachers, at least, in my State, in my city where they have to work on hourly basis not on regular basis. They have to sign one amount and take another amount. They have to pay to managements. The moot question is, you are throwing the ball in the court of the State Governments that they have to employ. In most of the State Governments, I would say, the school education is far below on the priority list. State Governments say 85 per cent or more budgets go towards the salaries of the teachers. So, where does the development happen?

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary?

SHRI BHARATKUMAR RAUT: My question to the hon. Minister is: will the Union Government ask the State Governments to put education on a higher priority list and give more grant-in-aid for the school education? Thank you.

SHRI KAPIL SIBAL: Certainly, we are very happy if the State Governments put education on a higher priority list. We would want State Governments to spend more money on it. In fact, if you look at the financial expenditure, the Government of India's expenditure on education has gone up over the years and the State's expenditure on education has gone down. That is the reality. We would like State Governments to spend more money on education. At the same time, if you really look at it, now under the RTE of the total budget of Rs.2,31,000 crores, almost 68 per cent, if you really work out the figure, comes from the Central Government.

On the one hand, the State Governments say that education is a State Subject, on the other hand, State Governments say give us 100 per cent. Now, you cannot have it both ways. It is a collaborative exercise. Please. This is a great national opportunity. I request hon. Members in the Rajya Sabha to request their State Governments, please don't recruit teachers from Class-X, as some of you are doing. Bring quality into the system. Please put education as the topmost priority of the agenda of your particular State.

DR. (SHRIMATI) KAPILA VATSYAYAN: Would the Minster like to throw some light on the recruitment rules for these teachers? Are they standard for all India? Do they accommodate regional variations and diversity of this country? Is there a case for looking into the pedagogy of NCTE itself?

SHRI KAPIL SIBAL: As far as the recruitment policies of teachers in various States are concerned, each State decides on its own on its recruitment policy. The Government of India has no role to play in the recruitment policy of teachers. Each State Government decides on the conditions of service, the salary that is to be paid and how teachers are to be recruited. That is why the part of the problem is that backlogs over the years have not been filled up. When it comes to Sarva Shiksha Abhiyan, the money is given by the Central Government, those posts are filled up. When it comes to the States' own expenditure, money comes from their own exchequer, they are not filled up. This is part of the problem. Therefore, it has to be part of the priority within the State Government. As far as pedagogy is concerned, that is already decided by the NCERT. We request that the NCERT

books should be adopted by various State Boards and most of time, in fact, the syllabus is based on the NCERT. So, that is really not an issue.

MR. CHAIRMAN: Question No.186. ...(Interruptions).. Please. ...(Interruptions)..

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I should also be given a chance. ...(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: I can take only three supplementary questions. ...(Interruptions).. Can we get on with the next question? I cannot give you another chance. ...(Interruptions).. You know the rules.

SHRI TRIUCHI SIVA: It is an important question. ...(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: Every question is important. ...(Interruptions)..

श्री रामविलास पासवान : सर, बिहार में 4 हजार ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : पासवान जी, प्लीज़ आप बैठ जाइए ... (व्यवधान) ...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, only one question. ...(Interruptions).. Just one question, Sir. ...(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: I am afraid it will be opening the door for discussion which the Chair is not entitled to do during the Question Hour. ...(Interruptions).. So, let us finish one more question because we have only five minutes more. Thank you. Question No.186. ...(Interruptions)..

(Followed by 1M/sss)

SSS-SCH/11.55/1M

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, we have responded very positively. We have lifted the ban on recruitment and we are recruiting more number of teachers and

Government's advice has been responded to positively by the Tamil Nadu Government. One State which is Tamil Nadu, Sir, is positively responding to the advice of the Government and we have lifted a ban on recruitment. We are recruiting a lot of teachers and I would like to seek a clarification. Some States have expressed their financial constraints. I want to know what the Government is intending to do.

MR. CHAIRMAN: Please address the hon. Minister on this subject and he will give you a satisfactory answer. Thank you very much.

(Ends)

Q. NO. 186

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, my supplementary is that the projects and works shown here in the reply had been sanctioned during UPA-I period by Railways itself but during the UPA-II it has been proposed to be done through PPP route. My question is: What is the reason for such a change?

KUM. MAMATA BANERJEE: Do you have any projects to mention? Which project do you want to mention? There are so many projects. You please name the project. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt.

KUM. MAMATA BANERJEE: Sir, there are so many projects. If I know the name of the project, then, I can answer.

SHRI SITARAM YECHURY: You have listed it in the answer.

MR. CHAIRMAN: Mr. Yechury, it is not your turn.

KUM. MAMATA BANERJEE: Okay, okay, I will give the reply, Sir.

श्री राजीव प्रताप रूडी: *

MR. CHAIRMAN: Please put your question.

श्री राजीव प्रताप रूडी: *

MR. CHAIRMAN: Please put your question. (Interruptions)

---

* **Not recorded.**

श्री राजीव प्रताप रूडी: *

श्री सभापति: भई आप सवाल पूछिए, आप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? Mr. Rudy, this is not fair.

श्री राजीव प्रताप रूडी: *

MR. CHAIRMAN: You have misused this opportunity. I am afraid, I don't agree. No, no... Please...(Interruptions)... Nothing of this will go on record. I am sorry. That question has been ruled out. (Interruptions)

श्री राजीव प्रताप रूडी: *

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, I find that instead of replying to me she has pointed a finger at me. (Interruptions) Instead of replying to my question, the Minister has pointed a finger at me. (Interruptions) Sir, I seek your protection. (Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: *

MR. CHAIRMAN: No, you have taken two minutes on this. This is wrong. (Interruptions) Sorry. This is not on record. Shri Rajniti Prasad.

श्री राजनीति प्रसाद: सर, छपरा और मरहौरा में जब ...(व्यवधान) बैठिए, बैठिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: पाणि जी, आप बैठ जाइए, प्लीज़ ...(व्यवधान) Please, will you sit down?

श्री राजनीति प्रसाद: सर, छपरा और मरहौरा में जब फैक्ट्री के लिए शिलान्यास किया गया ...(व्यवधान) तो वहां के लोगों की आंखें चमकने लगीं। लेकिन हम लोगों को मालूम है ...(व्यवधान)

---

* **Not recorded.**

(Q.NO. 186 - contd.)

श्री सभापति: आपने सवाल पूछना है या नहीं पूछना?

श्री राजनीति प्रसाद: सर, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। मेरा सवाल है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सवाल पूछने के लिए आपके पास सिर्फ 20 सैकिंड हैं।

श्री राजनीति प्रसाद: सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मुझको मालूम है कि अभी वहां किसी तरह का कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि 2011-12 में काम कंप्लीट कर देंगे, वह भी गलत है। क्या आप बता सकती हैं कि यह कब तक कंप्लीट हो जाएगा और कब इसमें काम शुरू होगा और अभी तक इसमें क्या-क्या काम हुआ है?

कुमारी ममता बनर्जी: सर, मधेपुरा, मरहौरा और छपरा, सब बिहार में हैं। हम लोगों ने बहुत सारी कोच फैक्ट्रियों का काम लिया है। छपरा और मधेपुरा में 2011-12 में कंप्लीट हो जाएगा। वहां पर काम बहुत तेजी से हो रहा है। You will be glad to know that मरहौरा और मधेपुरा में भी हम लोगों ने जो PPP के रूप में एक joint venture set up किया है, उसमें भी टेंडर वगैरह का प्रोसेस चल रहा है, यह जल्द-से-जल्द finalize हो जाएगा और यह काम भी बहुत जल्द कामयाब होने वाला है। So, Marhaura, Madhepura, Chapra and on other projects throughout the country, including Raibareille, the work will start immediately within the Eleventh Plan. Also, Sir, Katchrapada, Jankuni and the wagon factory are also under progress.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

(Ends)

PAPERS LAID ON THE TABLE

1. **SHRI SRIKANT JENA**: Sir, I lay on the Table—

I.(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956: —

(a) Fifty-fifth Annual Report and Accounts of the Hindustan Antibiotics Limited (HAL), Pune, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b)Review by Government on the working of the above Company.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN IN THE CHAIR)

2. **SHRI KAPIL SIBAL**: Sir, I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) Notification No. A.U./Comm.Sec./Uni.Coll./1140/2008, dated the 13th September, 2008, amending the Statutes of University of Allahabad, to substitute certain entries in the original Notification, under sub-section (2) of Section 44 of the University of Allahabad Act, 2005.

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i)(a) Annual Report and Accounts of the Bihar Education Project Council (Bihar Shiksha Pariyojna Parishad), Patna, for the year 2004-05, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (i) (a) above.

(ii)(a) Annual Report and Accounts of the Indian Council of Philosophical

Research (ICPR), New Delhi, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (ii) (a) above.

(iii)(a) Annual Report and Accounts of the Indian Council of Historical Research (ICHR), New Delhi, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (iii) (a) above.

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the Centre for Studies in Civilizations for implementation of the Project of History of Indian Science, Philosophy and Culture, New Delhi, for the year 2007-08, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (iv) (a) above.

(v)(a) Annual Report of the Indian Institute of Science Education and Research, Bhopal, for the year 2008-09.

(b) Annual Accounts of the Indian Institute of Science Education and Research, Bhopal, for the year 2008-09 and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Institute.

(d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (v) (a) and (b) above.

(vi)(a) Annual Report and Accounts of the North Eastern Regional Institute of Science and Technology (NERIST), Itanagar, Arunachal Pradesh, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (vi) (a) above.

(vii)(a) Annual Report of the National Institute of Industrial Engineering (NITIE), Mumbai, for the year 2008-09.

(b) Annual Accounts of the National Institute of Industrial Engineering (NITIE), Mumbai, for the year 2008-09 and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Institute.

(d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (vii) (a) and (b) above.

(viii)(a) Annual Report and Accounts of the Sant Longowal Institute of Engineering and Technology (SLIET), Longowal, Punjab, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (viii) (a) above.

(ix)(a) Annual Report and Accounts of the Orissa Primary Education Programme Authority (OPEPA), Bhubaneswar, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (ix) (a) above.

(x)(a) Annual Report of the Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, for the year 2007-08.

(b) Annual Accounts of the Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, for the year 2007-08 and the Audit Report thereon, under sub-section (4) of Section 22 of the National Institute of Technology Act, 2007.

(c) Review by Government on the working of the above Institute.

(d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at

(x) (a) and (b) above.

(xi)(a) Annual Report and Accounts of the Dr. B.R. Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xi) (a) above.

(xii)(a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Technology, Agartala, for the year 2007-08, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xii) (a) above.

(xiii)(a) Annual Report and Accounts of the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Uttarakhand, Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xiii) (a) above.

(xiv)(a) Annual Report and Accounts of the School of Planning and Architecture (SPA), Bhopal, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xiv) (a) above.

(xv)(a) Annual Report and Accounts of the Rajiv Gandhi Shiksha Mission, Chhattisgarh, Raipur, for the year 2007-08, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xv) (a) above.

3. **PROF. K.V. THOMAS:** Sir, I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) Notification No. S.O. 1480 (E), dated the 18th June, 2010, amending Notification No. S.O. 3267 (E), dated the 22nd December, 2009, to substitute certain entries in the original Notification, under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) Notification No. G.S.R. 551 (E), dated the 23rd June, 2010, amending Notification No. G.S.R. 632 (E), dated 2nd September, 2009, to substitute certain entries in the original Notification, under sub-section (4) of Section 83 of the Standards of Weights and Measures Act, 1976.

III. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (2) of Section 35 of the Food Corporation Act, 1964:—

(a) Annual Report and Accounts of the Food Corporation of India (FCI), New Delhi, for the year 2007-08, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b)Review by Government on the working of the above Corporation.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

IV. A copy each in (English and Hindi) of the Statement giving reasons for not laying the Annual Report and Audited Accounts of the Jammu and Kashmir Horticultural Produce Marketing and Processing Corporation Limited (J&K HPMC), Srinagar, for the years 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 and 2008-09, within the stipulated period.

II. SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, I lay on the Table, under clause (1) of article 151 of the Constitution, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports:—

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March, 2009: Report No.11 of 2010-11: Union Government (Indirect Taxes Central Excise) (Performance Audit) - Performance Audit on Excise Duty on Pharmaceutical Products.

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March, 2009: Report No.12 of 2010-11: Union Government (Defence Services) Army and Ordnance Factories; and

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March, 2009: Report No.15 of 2009-10: Union Government (Indirect Taxes - Customs) (Performance Audit) - Performance Audit on natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal and articles thereof, imitation jewellery, coin (Chapter 71 of Customs Tariff Heading).

(Ends)

NOMINATION TO PANEL OF VICE-CHAIRMEN

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform the House that Shri Tariq Anwar has been re-nominated to the Panel of Vice-Chairmen.

(Ends)

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT LEGISLATIVE AND OTHER BUSINESS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform the House that the Business Advisory Committee at its meeting held on the 5th August, 2010, has allocated time for Government Legislative and other Business as follows:

Sl. No.	Business	Time Allotted
1.	Consideration and passing of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2008.	Four Hours
2.	Consideration and passing of the State Bank of India (Amendment) Bill, 2010, as passed by Lok Sabha.	Three Hours
3.	Consideration and return of the following Appropriation Bills relating to the following Demands, after they are passed by Lok Sabha:-	
	(a) Supplementary Demands for Grants (General) for 2010-11.	Two Hours
	(b) Supplementary Demands for Grants (Railways) for 2010-11.	Two Hours
	(c) Supplementary Demands for Grants (Jharkhand) for 2010-11.	Two Hours
4.	Consideration and passing of the Jharkhand Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2010 (to replace Ordinance), after it is passed by Lok Sabha.	Two Hours

(Ends)

MOTION FOR ELECTION TO THE COURT OF THE ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Sir, I move the following Motion:—

That in pursuance of item (xxiv) of clause (1) read with clause (2) of Statute 14 of the Statutes of the Aligarh Muslim University appended to the Aligarh Muslim University (Amendment) Act, 1981, in terms of Section 28 thereof, this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one Member from amongst the Members of the House to be a member of the Court of the Aligarh Muslim University in the vacancy caused due to the retirement of Shrimati Mohsina Kidwai from the membership of Rajya Sabha on the 29th June, 2010."

The question was put and the motion was adopted.

(Ends)

STATEMENTS BY MINISTERS

STATEMENT RE: IMPLEMENTATION OF FIRST REPORT OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. K.V. THOMAS): Sir, on behalf of Shri Sharad Pawar, I make a statement regarding status of implementation of recommendations contained in the First Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2009-10) of the Department of Agriculture and Cooperation.

(Ends)

STATEMENT RE: IMPLEMENTATION OF SECOND REPORT OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): Sir, I make a statement regarding status of implementation of recommendations contained in the Second Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers (2009-10) of the Department of Fertilizers.

(Ends)

ANNOUNCEMENT RE: GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 9th OF AUGUST, 2010

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Consideration and passing of the following Bills, as passed by Lok Sabha:-
   (i) The Land Ports Authority of India Bill, 2010.
   (ii) The Security and Insurance Laws (Amendment and Validation) Bill, 2010.
   (iii) The State Bank of India (Amendment) Bill, 2010; and
   (iv) The Energy Conservation (Amendment) Bill, 2010.

3. Consideration and passing of the following Bills:-
   (i) The Foreign Trade (Development and Regulation) Amendment Bill, 2009.
   (ii) The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2008; and
   (iii) The Foreign Contribution (Regulation) Bill, 2006.

4. Consideration and return of the following Appropriation Bills, after they are

passed by Lok Sabha:-

(i) The Appropriation (No. 4) Bill, 2010; and

(ii) The Jharkhand Appropriation Bill, 2010.

5. Consideration and passing of the New Delhi Municipal Council (Amendment) Bill, 2010, after it is passed by Lok Sabha.

(FOLLOWED BY PB "1O")

PB-DS/1o/12.05

BILL INRODUCED

THE CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (RESERVATION IN ADMISSION) AMENDEMNT BILL, 2010

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I introduce the Bill. (Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We now take up the Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS *

NBR

DEMAND FOR NAMING ANY EXISTING OR UPCOMING AIRPORT AS DR. B.R. AMBEDKAR AIRPORT

SHRI AMBETH RAJAN (UTTAR PRADESH): Hon. Chairman, Sir, there are 17 international airports, including 3 JVCs, 8 customs airports and 81 domestic airports in our country. All these airports are named after many national leaders, State leaders and other historical figures. But, I am constrained to state that out

---

*** Laid on the Table of the House**

of these airports, both international and domestic, none of them are yet to be named after an iconic figure of this counry, Baba Sahed Dr. B.R. Ambedkar, who was the founding father of our Constitution.

It is important to mention here that Dr. Ambedkar was the first Law Minister of the Independent India and he is still a role model for many people belonging to all walks of life. Taking into account of his valuable serviced to the society and this country, he was awarded India's highest Civilian Award, Bharat Ratna in the year 1990.

Recently, a new terminal has been inaugurated in the Delhi International Airport. So also, so many new airports are coming up in various parts of the country.

So, it is my earnest appeal to the Government, through this august House, to keep the name of Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar to the newly inaugurated terminal in the Delhi International Airport or to a new upcoming airport at Mumbai which will be a befitting tribute to him.

(Ends)

MP

DEMAND TO TAKE ACTION FOR COMPLETE CONVERSION OF THE NATIONAL HIGHWAY No. 42 INTO A FOUR-LANE HIGHWAY

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : महोदय, उड़ीसा के अंदर कटक के मंगुलि से ढेंकानाल, अंगुल से संबलपुर तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42, राज्य की एक जीवनरेखा है एवं सांस्कृतिक संयोगकारी राजपथ है। पश्चिम उड़ीसा के प्राणकेंद्र संबलपुर तथा उड़ीसा की

सांस्कृतिक राजधानी कटक के बीच यह संयोगकारी है। इसके साथ-साथ इस राजमार्ग के दोनों पार्श्व में अब व्यापक रूप से औद्योगीकरण हो रहा है। राज्य के कई हिस्सों में नक्सलवाद की स्थिति भयंकर होने के कारण कई लोग घूमने जाने हेतु भी अब इस राजमार्ग का इस्तेमाल करते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार इसमें अब दैनिक 20,000 से ज्यादा वाहनों का आवागमन होता है। दैनिक 5,000 से अधिक छः चक्के वाले, 5,000 से अधिक दस अथवा अधिक चक्के वाले, 300 से अधिक भारीयान एवं 100 से अधिक ट्रेलर चलने के कारण दोपहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन, जिनमें आम आदमी सफर करते हैं, भयंकर रूप से प्रभावित होते हैं। प्रतिदिन कोई न कोई दुर्घटना घटती है। 2010 के प्रथम 180 दिनों के अंदर 178 बड़ी दुर्घटनाएं घटी हैं, जिनमें कुल 79 लोगों की मृत्यु हुई है, 133 लोग गंभीर रूप से आहत हुए हैं एवं 124 लोग आहत हुए हैं। 2003 से 2005 के बीच, दो साल के अंदर, दो विधायकों का इसी राष्ट्रीय राजमार्ग में दुर्घटना से मृत्यु होने का इतिहास है। अतः वर्षों से इसको 4-लेन विशिष्ट बनाए जाने हेतु मांग की जा रही है। इस पवित्र सदन में भी कई बार इस मांग को उठाया जा चुका है। बीच में समाचार आया था कि "नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट" (एन.एच.डी.पी.) के चौथे चरण में इस परियोजना को लिया गया है और पहले पर्याय में मंगुलि से अंगुल के बीच 110 किलोमीटर के रास्ते को 4-लेन विशिष्ट किया जाएगा एवं अंगुल शहर के लिए एक बायपास भी बनाया जाएगा। इस कार्य हेतु "डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट" (डी.पी.आर.) बनाई जा रही है, ऐसा भी कहा जा चुका है, लेकिन इसमें अनावश्यक देरी की जा रही है और अब कहा जा रहा है कि पहले दो लेन विशिष्ट इस राजमार्ग का उन्नयन करके 'paved shoulders' संपन्न किया जाएगा - यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है । अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 के संपूर्ण 4-लेनीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाए।

(समाप्त)

DEMAND TO IMPOSE PENALTIES ON TELECOM OPERATORS NOT COMPLYING THE TERMS AND CONDITIONS OF THE SPECTRUM ALLOCATION IN THE COUNTRY

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (KARNATAKA): Sir, our vast nation is, presently, witnessing a revolution in telecommunication sector and new technologies are forthcoming every now and then. This sector is expanding very fast. However, I wish to draw the attention of the House to recent news reports about some telecom companies offering to return their licenses against a refund of license fees paid by them, which will be a setback to this revolution.

This is clearly unacceptable. These operators are under contractual obligations to invest and rollout services. Therefore, Government must impose a punitive fee/penalty on them for failure to discharge their obligations. Also, Government must allot surrendered spectrum to new operators through an auction process only, which will realize higher prices.

These operators got licenses in January, 2008 at far below market prices. The Government, while issuing these licenses without any tender/auction process, had cited "increase in competition" as the rationale, to reduce tariffs and ensure that rural telephony objectives of the country were met.

However, subsequent Government decision to allow M&As across the board in the sector is in sharp contrast to this rationale, because it will lead to reduction in level of competition, eventually prices and take us back to the cartelization days.

These operators are clearly using this tactic to get a relaxation on these M&A norms, where they are not obligated to invest or roll out services.

This twin Government policy objectives of increasing competition and realizing the maximum value for the spectrum must be adhered to, with no compromise. The operators must pay penalty as per their contractual obligations, if they fail to invest and roll out services.

I urge the Government to take A serious note of this matter.

(Ends)

SC

DEMAND TO TAKE EFFECTIVE STEPS FOR TRANSFER OF ASSETS TO THE STATE OF HIMACHAL PRADESH UNDER THE STATE OF PUNJAB REORGANIZATION ACT, 1966

श्री शान्ता कुमार (हिमाचल प्रदेश) : महोदय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम - 1966 के अनुसार हिमाचल प्रदेश को उसके अधिकार दिलाने के मामले में मध्यस्थता करे। केन्द्र सरकार इस संबंध में प्रभावित राज्यों - पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से बातचीत कर रही है परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए समय की अवधि समाप्त हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश की जनता चिंतित है। वस्तुतः हिमाचल प्रदेश को राज्य में स्थापित पंजाब राज्य की बिजली परियोजनाओं में बारह प्रतिशत मुफ्त बिजली, स्थानांतरित जनसंख्या के आधार पर परिसम्पत्तियों में 7.19 प्रतिशत का हिस्सा और पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड में से 2.5 प्रतिशत की भागीदारी इस अधिनियम के अनुसार देय है। यह मामला प्रदेश सरकार ने विभिन्न मंचों पर समय-समय पर उठाया है लेकिन कोई आशाजनक परिणाम आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रदेश सरकार ने इस मामले को सुलझाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दर्ज की

थी। न्यायालय ने गत 29 अप्रैल को एक निर्णय में केन्द्र सरकार को तीन सप्ताह में प्रभावित राज्यों की बैठक बुलाकर और तीन मास में इस मामले को बातचीत के माध्यम से हल करने का निर्देश दिया। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया कानून है और इस कानून के हिसाब से हिमाचल को हक मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का पानी, प्रदेश की जमीन, प्रदेश के हजारों लोग उजड़े, बिजली पैदा हुई, पड़ोस के प्रदेशों में खुशहाली आई लेकिन वह हिस्सा, जो संसद ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए, आज तक राज्य को नहीं मिला। केन्द्र सरकार के पास यह मामला विचाराधीन है। हिमाचल को उसके अधिकार मिलने का यह अंतिम अवसर है। अतः अनुरोध है कि निश्चित अवधि में केन्द्र सरकार हिमाचल को न्याय दिलाए।

(समाप्त)

MCM

DEMAND FOR LAYING OF ADEQUATE RAILWAY NETWORK IN PUNJAB

श्री अविनाश राय खन्ना (**पंजाब**) : महोदय, पंजाब में रेलवेज का जितना विस्तार होना चाहिए था, उतना सरकार नहीं कर रही है। चिंता व दुख की बात है कि श्री अमृतसर और श्री आनन्दपुर साहिब को रेलवे से जोड़ने की जो घोषणा रेलवे बजट में की गई थी, उसका एक सर्वे भी हो गया था परन्तु केन्द्र की पंजाब के प्रति जो रवैया रहा है, इस प्रोजेक्ट को मंजूर करने के बजाए पंजाब राज्य को पूरे प्रोजेक्ट का 50 प्रतिशत हिस्सा डालने को इश्यु बनाकर इस प्रोजेक्ट को ड्रोप कर दिया। इसी प्रकार होशियारपुर जहां से आजादी के पहले पेशावर तक गाड़ी जानी थी, अब कोई भी गाड़ी होशियारपुर से अमृतसर, पठोनकोट को नहीं जाती। यहां रेलवे लाइन भी बिछाने की जरूरत नही है, क्योंकि यह स्टेशन पहले ही रेलवे लाइन से जुड़े हुए हैं। पंजाब का यात्री रेल में यात्रा टिकट लेकर करता है, कभी भी किसी पंजाबी को बिना टिकट नहीं पकड़ा होगा। इसलिए उक्त मांगों पर सहानुभूति से विचार करते हुए इन मांगों को मान लेना चाहिए। (समाप्त)

GS

REQUEST TO DEPUTE THE RPF PERSONNEL ON THE TRAINS FROM PATNA JUNCTION TO MOCAMA AND PATNA JUNCTION TO GAYA IN BIHAR

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) : महोदय, पटना जंक्शन से मोकामा एवं पटना जंक्शन से गया जो रेलवे का आवागमन होता है उसमें यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। दिन में जितनी रेलगाड़ियां चलती हैं, उनमें कोई व्यक्ति किसी भी डिब्बे में बैठ जाता है और chain pulling करके ट्रेन को कहीं भी रोक देता है। उपरोक्त दो जगहों में किसी तरह के सुरक्षा बल की व्यवस्था नहीं रहती है। इसके संबंध में, मैं व्यक्तिगत रूप से डी.आर.एम. दानापुर एवं आर.पी.एफ. के महानिदेशक से मिला। उन्होंने इस पर किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर कड़ाई नहीं कर सकते हैं। अगर यही अव्यवस्था रही तो दिन में इन इलाकों में परिवार के साथ लोगों का सफर करना संभव नहीं होगा।

महोदय, डी.आर.एम. दानापुर का कहना था कि सभी आर.पी.एफ. को वहां से हटा लिया गया है। इन दोनों इलाकों में यात्री भगवान के भरोसे चलते हैं। इतना ही नहीं, आए दिन इन इलाकों में ट्रेन में लूट-पाट भी होती रहती है।

अत: मैं इस विशेष उल्लेख के जरिए रेल मंत्री से अनुरोध करता चाहता हूं कि पटना जंक्शन से मोकामा एवं पटना जंक्शन से गया के रूट पर दिन की ट्रेन में विशेष तौर पर रेलवे सुरक्षा फोर्स की व्यवस्था की जाए ताकि लोग ठीक ढंग से यात्रा कर सकें।

(समाप्त)

ASC

CONCERN OVER THE DANGER POSED TO RESIDENTS OF BIRSINHPUR PALI IN DISTRICT UMARIA OF MADHYA PRADESH BY THE UNDERGROUND BLASTS BEING DONE FOR MINING OF COAL IN THE REGION

सुश्री अनुसुइया उइके (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बिरसिंपुर पाली तथा

अन्य नगर कोयला खदानें आरंभ होने के पूर्व से बसे हुए हैं। कोयला कम्पनी द्वारा बाद में इन स्थानों पर भूमिगत कोयला खदानें स्थापित की गई हैं।

भूमिगत कोयला खदानों कोयला उत्पादन के लिए विस्फोट कर कोयले की खुदाई की जाती है। नीचे भूमिगत कोयला खदानें हैं तथा ऊपर पहले से आबादी निवास कर रही है। खदानों में कोयला निकालने के लिए जो विस्फोट किया जाता है, वह इतना तीव्रवेग का होता है कि उससे ऊपर स्थित, मंदिर, मस्जिद, सड़क, पुल, तालाब इत्यादि अधोसंरचना बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। घरों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे मकान गिरने की संभावना उत्पन्न हो गई है। किसी भी दिन कोयला खदान में कम्पनी द्वारा किए जा रहे विस्फोट से बड़ी जनहानि हो सकती है।

मध्य प्रदेश में स्थापित कोयला खदानों की कम्पनी का मुख्यालय महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में है, जबकि कोल इंडिया की नीति के अनुसार जिस प्रदेश में कोयला खदानें हैं, उनका मुख्यालय उसी प्रदेश में होगा।

अतएव, मैं इस सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि आबादी के नीचे स्थापित कोयला खदानों में विस्फोट प्रक्रिया को नियंत्रित अथवा समाप्त किया जाए, ताकि कोई बड़ी जनहानि न हो। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में स्थापित कोयला खदानों के लिए कोयला कम्पनी का मुख्यालय भी मध्य प्रदेश में प्रारंभ कराया जाए।

(समाप्त)

MATTERS RAISED WITH PERMISSION OF CHAIR

ATROCITIES ON AN ADIVASI GIRL

श्री राजनीति प्रसाद (**बिहार**): सर, मैं आपकी अनुमति से एक विशेष मामला आपके सामना उठाना चाहता हूँ। ..(व्यवधान)

श्री एस.एस. अहलुवालिया: क्या राज्य का विषय यहाँ उठाया जा सकता है? ..(व्यवधान).. क्या आप राज्य का विषय यहाँ उठाने देंगे?

श्री उपसभापति: नहीं, वह किसी महिला का मामला उठा रहे हैं।

श्री राजनीति प्रसाद: सर, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने उठाना चाह रहा हूँ। पश्चिमी बंगाल के बीरभूम क्षेत्र में 15 साल की एक आदिवासी लड़की ने जब गांव के एक आदमी के साथ शादी कर ली, तब वहाँ की पंचायत में यह फैसला हुआ कि इस आदिवासी लड़की को नंगा करके घुमाया जाए। ..(व्यवधान).. फिर नंगा करके उसे घुमाया गया ..(व्यवधान).. यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ..(व्यवधान)

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, can he authenticate it? ...(Interruptions)... I have also enquired it. No such incident has taken place. Without authenticating it, he cannot say it. ...(Interruptions)...

श्री राजनीति प्रसाद: आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? ..(व्यवधान)

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, this cannot go on record. ...(Interruptions)...

श्री राजनीति प्रसाद: यह क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा? ..(व्यवधान)

श्री उपसभापति: राजनीति प्रसाद जी, मैम्बर्स इस पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। क्या आप इसे authenticate करेंगे?

श्री राजनीति प्रसाद: सर, मैं कह रहा हूँ कि कल "आज तक" में ..(व्यवधान)

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं। आपका कहना अलग बात है, लेकिन क्या आप इसे authenticate करेंगे?

श्री राजनीति प्रसाद: बिल्कुल सर, क्या मैं बिना authentication के बोल रहा हूँ? ..(व्यवधान)

श्री उपसभापति: नहीं, authenticate करना अलग बात है, लेकिन आपको अपना signature करके देना पड़ेगा। ..(व्यवधान).. आप पहले इसे authenticate करके दे दीजिए, तब बोलिए। ..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इस पर privilege हो जाएगा।

(1पी/एनबी पर आगे)

श्री उपसभापति : आप authenticate करके दे दीजिए।

श्री राजनीति प्रसाद : हमें कोई प्रिविलेज का डर नहीं है ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप authenticate करके दे दीजिए, बाद में बोलिए ... (व्यवधान)

श्री राजनीति प्रसाद : सर, यह अखबार में आया है ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : अखबार की बात नहीं है, Hon. Members from West Bengal has raised an objection that it has to be authenticated. ...(Interruptions)...

श्री राजनीति प्रसाद : यहां जो इतनी बातें होती हैं, क्या सब authenticate करके देते हैं?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you authenticate it, I will allow it. If you don't authenticate it, I will not allow it. ...(Interruptions)...

श्री राजनीति प्रसाद : सर, यह authenticated मामला है ... (व्यवधान)

... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आपको साइन करके देना है, आप authenticate करके दे दीजिए। आप जो विषय उठा रहे हैं, यह authenticated है, यह आप लिखकर दे दीजिए और फिर सोमवार को उठा लीजिए ... (व्यवधान)

श्री राजनीति प्रसाद : सर, आप मुझे यह मामला नहीं उठाने दे रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप लिखकर दे दीजिए और फिर सोमवार को उठा लीजिए।

(समाप्त)

CLOUDBURSTS IN LEH

श्री राजीव प्रताप रूडी (**बिहार**) : उपसभापति जी, आज सुबह लेह में एक भयंकर त्रासदी हुई है, उस समय तक नोटिस देने की संभावना नहीं थी। आज सुबह cloud burst के कारण लेह में एक भयंकर त्रासदी हुई है और 100 से अधिक लोग मर गए हैं और मलबे के नीचे सैकड़ों लोग दबे हुए हैं। लेह की हवाई पट्टी पर भी बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार प्रयास कर रही है,

लेकिन केन्द्र सरकार को चाहिए कि राहत कार्यों में पूरी तरह से मदद करे। आज इस cloud burst के कारण यह जो त्रासदी हुई है, इसमें जो लोग प्रभावित हुए हैं, हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। सरकार की तरफ से राहत कार्यों के लिए हर प्रकार का सहयोग दिया जाना चाहिए।

(समाप्त)

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश) : मैं अपने को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : मैं अपने को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

(समाप्त)

श्री राजनीति प्रसाद : उपसभापति जी, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं ... (व्यवधान) आपके यहां जो भी मामला आता है, क्या सभी लोग लिखकर देते हैं ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप यह contentious issue यहां मत उठाइए। वहां जो बात होती है, उसे यहां नहीं उठाना चाहिए। आप मेरी बात सुनिए। आपको मामला उठाने की परमीशन दी गई थी, लेकिन पश्चिमी बंगाल के 2 मेंबर्स objection कर रहे हैं कि यह मामला authenticate नहीं हुआ है।

श्री राजनीति प्रसाद : किसका authentication नहीं हुआ है?

श्री उपसभापति : Authentication का मतलब यह है कि आपको इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मैं जो विषय उठा रहा हूं, यह सही है, मैं पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, इस तरह से आपको authenticate करके, लिखित रूप में सभापटल पर रखना पड़ेगा।

श्री राजनीति प्रसाद : मैं लिखूं या बोलूं?

श्री एस.एस. अहलुवालिया : इतना ही नहीं है। अगर अखबार में कुछ छपता है या टी.वी. पर कुछ बोला जाता है या दिखाया जाता है, तो उसकी कॉपी, along with the transcription, authenticate करके देनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया।

श्री उपसभापति : मैं वही कह रहा हूं ... (व्यवधान) राजनीति प्रसाद जी, उस अखबार की कॉपी होनी चाहिए। अब आप बैठिए।

(समाप्त)

CLARIFICATIONS ON STATEMENT OF 4TH AUGUST, 2010 RE: RECENT VIOLENCE IN THE STATE OF JAMMU & KASHMIR

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, the Hon. Home Minister has made a Statement before this House on 4th August, 2010. The Statement broadly gives a list of events and some very serious developments which have taken place since the 11th June this year. It does not reflect the enormity of the seriousness of the situation and what roadmap the Government has in mind for resolving the current impasse that is taking place.

(Contd. by 1q/KSK)

KSK/12.15/1Q

SHRI ARUN JAITLEY (CONTD): Sir, we get an impression that the situation is slowly slipping out of control. And, it is clear from the Home Minister's statement, as also various pieces of information that we are getting from media organisations, as also the citizens of the Valley, that in the last few months, particularly in the last two years, there has been a significant change in the strategy by both, the ISI, various agencies across the border, as also the separatist forces who act at their behest in the Valley itself. Sir, earlier, the strategy used to be to have illegal infiltration into the Valley and other parts of the country to indulge in acts of sabotage, acts of terrorism, blasts, killings, destruction of public property, etc. I think, somewhere, in the strategic thinkers amongst those who are the handlers

across the border and their friends within, there seems to be a realisation now that the global acceptability for these kind of events does not exist. Even domestic support, when incidents of this kind take place, starts reducing and vanishing. Also, Sir, in the last 20 years, two decades, our own security forces, our own intelligence network has also been considerably strengthened and we have dealt with large number of these incidents, and, therefore, if I may, without meaning to be arrogant about India's potential, say that the potential of Indian State itself was increasingly becoming more powerful in tackling these incidents of sabotage. The changed strategy, therefore, appears to be that instead of these individual acts of terror and violence, instigate people for the purposes of mob violence and this entire strategy of mob violence, which has taken effect in the Valley since 11th of June, when some efforts were also made two years ago when they tried to create a controversy on the issue of pilgrim facilities in the Amarnath Yatra. But, gradually, it has been building up since then in the last two years. From young children to women, youth, elderly people, are all being trained in acts of sabotage by way of stone pelting and mob violence wherein large crowds collect. Sir, women are organised by several separatist groups. The name of Dukhtaran-e-Millat is being regularly mentioned. Regarding school children, there have been incidents which have been reported that when they go to their schools, besides textbooks, their bags are also filled up, by some vested interests, with stones and the target is public property, the target is security forces. The Home Minister, in his statement, has mentioned that more than 1200 security personnel have already been injured. Now, the entire strategy appears to be that somehow indulge in

these acts of mob violence and provoke the security forces, damage public property. Now, after all, public property has to be protected, human life has to be protected. And, every time, a defensive action is taken by our security forces, obviously, in a confrontation of this kind, lives will be lost. Even innocent lives will be lost. The Home Minister has rightly said that we sympathise with all those who have lost their lives even if they were a part of the agitating crowd because we do not want even a misled citizen of India to meet his end in this manner. Now, the entire strategy appears to be that through these acts of mob violence, instigate violence, create tension and then use the emotive content of that confrontation in order to spread it further. Sir, today, we are faced with a situation where, as I said earlier, that our security forces, our local police, our CRPF, our other security forces, were actually, for the last two decades, tackling individual acts of terror and violence.

(continued by 1r - sk)

-ksk/sk/12.20/1R

SHRI ARUN JAITLEY (Contd.): This is a new situation which has emerged today. Unfortunately, and I say this with a sense of deep regret, even when efforts are being made by separatist groups to escalate the situation, and we had evidence of it which was broadcast by national television where handlers across the border are informing the so-called organizers of this mob violence, as to what the start point of the protest would be, as to what actions they are to take, they were even measuring the size of the crowd which was collecting for these particular purposes. Therefore, how do we handle a situation of this kind? What has,

unfortunately, happened is that the political parties, which operate in the Valley within the political framework of India's democratic polity, have, unfortunately, taken a back seat. Their ability to reach out to the people in a situation of this kind has somehow suddenly got diluted. Also, Sir, there is a reasonable sense of worry that we have, as to what is the preparedness of both our intelligence agencies and our security agencies to deal with this new situation which is now emerging where mob violence as a substitute to the isolated terrorist attacks is now the strategy of the separatist groups. The biggest worry, Sir, is that today, the State Government within the Valley, and this is the information which we are getting, has increasingly got alienated from the people. In the two other parts of the State, that is, Leh Ladakh and Jammu, there is a huge amount of anger as these two regions have a feeling that they suffer from having been discriminated against historically. And, today, these two are feeling helpless as the entire concentration of the State and the country is on the Valley, and within the Valley, where large parts of our national resources are spent, and this kind of a situation has taken place. I mean no personal disrespect to any individual, but I am given to understand that forget the State, the Home Minister has to ask his own party, the Chief Minister is getting alienated even from his own party and even from his own alliance partners, and that is one of the reasons that the activity of the mainstream political parties within the Valley, I can understand his opponents in the PDP, who at times are making contradictory statements, probably want the State Government to go. But, today, even within the ruling alliance, the activity of all these parties which function within the framework of India's democratic polity in

reaching out to the people has somehow got diluted and they are not making conscious efforts to do that. Whereas we have to prepare our intelligence and our security network to face a situation of this kind, we have also to be prepared to get together all the nationalist forces within the Valley for their politics so that they don't themselves get alienated from the people and are able to reach out to the people directly. When all this was happening, and as I said, this has been gradually building up, there is a deep sense of disappointment also. What have we done, as far as the Government of India is concerned? We experimented with new ideas every time without realizing whether those experiments will bring any return home or not. You had a political alliance with one group for six years. Then you switched over to a political alliance with a rival group. This kind of alliance hopping by a national party itself we thought perhaps is the political situation. But it has paid no dividends. The Prime Minister went there around three years ago. He went recently also, just before the violence started. And, without considering the consequences of what he was going to do -- there is no difficulty if you say that we stand for economic development, we stand for jobs, we stand for human rights -- he thought that a round table conference and some working groups were a solution.

(Contd. by ysr - 1s)

-SK/YSR/12.25/1S

SHRI ARUN JAITLEY (CONTD.): Just consider what happened. You constituted a Working Group to again work out a constitutional relationship between India and the State; the rest of the country and the State. The manner it went on was a

complete farce. We got a retired judge of the Supreme Court for this. I say it with utmost respect for him. The Group hardly met. For twenty-two months, it did not meet. And suddenly without discussing it with the Group, without discussing it with the mainstream political parties, he produced a report. Who wrote the report nobody knows. Were these farcical experiments to be done with India's most sensitive area? Then we were told that this was a kind of autonomy document.

You then had a situation where the Home Minister has been maintaining what we have 'silent diplomacy,' which is on, for the last few months. What has the 'silent diplomacy' produced? Who are we talking to? I presume the kind of people we are talking to as a part of 'silent diplomacy' or 'quiet diplomacy.' The 'quiet diplomacy' has been going on for over a last few months. Because we are not finding the persons who are partners across the table in the quiet diplomacy. You are even going amongst the people in a situation of this kind which exists today.

Sir, before I come to the immediate issues involved in it, there are a few worrisome things. I would urge the Home Minister that while dealing with a situation of this kind, the Government of India certainly must not have a knee-jerk or panic reaction. We must realise this -- my party has always believed it, and I have no hesitation in reasserting it even if many other parties don't agree -- that our historical vision, or how the State's problems were to be resolved, was at fault. We started with a situation where we felt that, ' let us give them a separate status, it will please the people.' Please, stand up and honestly analyse this. Sixty-three years after independence, is the separate status journey moving

towards separatism? Or is it moving towards integration? Has your vision been historically proved right or wrong? Therefore, every time there is a problem of this kind, the solution which is suggested is that let us make a few more concessions; as it is you have authority over security, defence, external affairs, telecommunications, currency, and four or five areas of this kind.

Political parties within the valley may have their own compulsions. They speak in terms of pre-1953 status; they speak in terms of self-rule; and they speak in terms of autonomy. They have the freedom to advocate what they honestly believe in. But at the end of the day, are we going to go back to a situation where the Supreme Court of India has no jurisdiction or where the Election Commission has no jurisdiction? Therefore, when you decide how to deal with this, let there be no knee-jerk reactions, because you have to find a long-term solution. What did the President Musharraf, the former head of Pakistan, say after he went to London? This was a worrisome statement. We want somebody in the Government of India to clarify that this was not correct. In London, he said on Track-II we had almost come to a settlement on Kashmir. Now Track-II can be a step away from Track-I, but it cannot be diametrically opposite to Track-I. Track-I has visible diplomacy. What was the settlement that he was talking about. I only hope what he said was not an accurate version of what transpired.

Therefore, Sir, in a situation of this kind my queries to the hon. Home Minister or clarifications on the statement are: Does the Government of India have specific information that this entire change of strategy is being engineered from

across the border and the handlers of this changed strategy of the separatist are across the border?

Secondly, there also seems to be some churning out of leaders within the separatist groups. Therefore, as a part of this churning out within the separatist groups, you have new leaders, who have suddenly emerged, who are leading the current agitation.

(Contd. by VKK/1T)

-YSR/VKK/1t/12.30

SHRI ARUN JAITLEY (CONTD.): And, therefore, if some of them, who have been traditionally involved in pro-Pakistan and separatist activities in the Valley, suddenly start giving statements one day which seem to be more conciliatory, is it a case of change of heart? I am particularly referring to Ali Shah Gilani's statement made yesterday. Is it a change of heart or is it part of a concerted strategy that these statements have been made?

Thirdly, Sir, would the Home Minister acquaint us with the extent to which violence has speared across the State and what steps the Government of India and our security forces are going to take to make sure that this mob violence comes to an end?

Finally, Sir, I hope, his answer is in the negative. When the situation is at such a sensitive point, no kind of political packages -- and the kind of things which are mentioned in those political packages -- be envisaged at this stage by the Government of India because packages of this kind will only indicate the weakness of the Indian State. Suggestions which are made are like dilute the

border across the PoK which may become an option of legitimate infiltration; dilute the provisions of the Armed Forces (Special Powers) Act which will cripple the Armed Forces who are trying to save the sovereignty and integrity of India; take away the land meant for army cantonments. Your former partner, PDP, even goes to the extent of suggesting that allow both the currencies of both the States. And then, of course, there is the famous President Musharraf's suggestion that the Government of India has never accepted, irrespective of the party in power, to lose control of an area and go in for some kind of joint administration and control. Sir, I hope that there is no such proposal to make any concession of this kind because any concession made at this stage will further dilute the sovereignty and further make the separatists realise that their dreams are, at some point of time, realisable. Unless you give a clear strong signal from India that forget this being crystal-gazing or forget this being a distant dream, it's an impossibility. India will never compromise or bargain on its sovereign territory. It's only in that situation that you can go and negotiate from a position of strength rather than from a position of weakness. Thank you.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Honourable Members, this is for clarifications on the statement. The Leader of Opposition has his own prerogative. But, don't take it as a discussion. (Interruptions) It is not a sort of discussion.

SHRI S.S. AHLUWALIA: It is very important. Sir, this subject cannot be taken up in this session for discussion. So, this is a sort of discussion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, already a statement has been made. Yes, it is an important subject. That is why, we are departing from the regular clarification rule. But, I want to remind the Members that don't take it as a discussion or debate. Now, Shri Saif-ud-Din Soz.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (JAMMU AND KASHMIR): Sir, I express my deep anguish on the situation that is prevailing in the Kashmir Valley. See the deaths that have occurred during the last 20 days including youngsters. It's a colossal waste of property. Education system is in a shambles, and people there have suffered great frustration in spells of curfew and strikes. This is no occasion to describe the misery that the people of Kashmir have suffered. Now, while I stand to seek some clarifications from the hon. Home Minister, I will ask: Will it be too much to expect that this House responds to the miserable situation which prevails not only on the ground but also dangerously in the mind of the young generation who have seen nothing but violence all these years of turmoil? I would request the Leader of Opposition also to care to understand and appreciate the content of my appeal.

(Contd. By MKS/1u)

MKS-GS/12.35/1U

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (CONTD.): If this august House cares for my appeal, then it could support my suggestion that a Group of Parliamentarians, from all parties, may visit Kashmir soon and talk to a cross section of society besides visiting the bereaved families. It is, then, possible to understand better the perception of the Chief Minister, His Excellency, the Governor, and different

segments of civil society. The people of Kashmir -- this august House will, certainly, try to agree with me -- deserve a message of compassion more than any package for economic well-being. Around this time, we should all be feeling to send a powerful message of irreclusiveness and togetherness, cutting across party lines. That is my appeal. Thank you, Sir.

(Ends)

SHRI SITARAM YECHURY (WEST BENGAL): Thank you, Sir. With a deep sense of anguish at the situation in Kashmir and with a sense of anger that we, somehow, seem to appear impotent in dealing and settling with this issue, I want to seek certain clarifications. It is very difficult, Sir, not to say something before I raise certain questions, and that is connected with the fact that the hon. Home Minister's statement begins from the incidents that have taken place from the 11th of June. Now, the 11th of June incidents did not happen all of a sudden. There was a built-up to it, and in the built-up to it, various things were happening which were noticed by all of us and the fact that there was no reaction to that and no anticipation that this is going to lead up to this. That itself is very worrisome. ...(Interruptions)... Yes, there are all sorts of information about cross-border support that they have received from the people who are not interested in the integration of Kashmir with India. The issue that needs to be addressed is, essentially, the capacity of people to enlarge the area of alienation between the people of Kashmir and India. How are we going to bridge that? The solution, Sir, does not -- and that is apart from agreeing with the hon. Leader of the Opposition on many other things, but, on one aspect, I will have to disagree with

him -- lie in abrogating the provisions of Article 370. The solution lies, actually, in implementing it properly. The lack of its implementation has led to the alienation, and keeping that in mind, we have to understand, Sir, that it took nearly six months after the general indications that have come for an all-party meeting to be called in Kashmir. It is only after a month and 22 days, since these incidents began, that you have the Chief Minister issuing a statement! The political initiatives that we are all talking about and all that, at the moment, I think, can wait. What is actually required is to generate the confidence and remove that feeling of alienation. One important element of alienation is the role of our Army. I do not wish to undermine the role of our Army; they are doing a yeoman service in the integrity of our country. I mean, on that, there is no dispute. But whatever issues are whipping up the sentiments of alienation in Kashmir will have to be addressed, and, therefore, in this context, I think, the statement that the Army Commander -- this is a clarification I would seek from the Home Minister -- has made to declare the Armed Forces Special Powers Act, what is the reaction of the Central Government and how are we going to address this? At a time when there is a resentment building up saying that civilian deaths are increasing in the hands of Armed Forces, yes, there is utmost provocation; the strategic paradigm has shifted; the strategic paradigm is no longer the individual attacks of terror, but in order to incite mobs to violence; this has been happening; we have seen, this happened in the Amarnath Yatra period, two years ago; we have seen this happening even today -- in such a situation, the most important thing is to show restraint, but, at the same time, to gain the confidence of the people as well. My

party has been seeking, Sir, for a long time, since all these disturbances began, a solution; we want -- I fully endorse Prof. Saif-ud-Din Soz's suggestion -- an all party delegation to be sent to Kashmir immediately, as soon as possible. And, there, the clarification I want to have is.....

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आप वहां जाओगे, तो वहां बंद होगा।

श्री सीताराम येचुरी : नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, we are not going; you are right. I understand. You are absolutely right.

(Contd. by TMV/1W)

-MKS-TMV-ASC/1W/12.40

SHRI SITARAM YECHURY (CONTD.): At the time of Amarnath Yatra also we all went there if you remember. Then the people came to talk to us. Now the point is to tell them that India is with them. We have to tell the people of Kashmir, "We are with you and you are with us". The whole political spectrum in India, not just the Government, all of us, is there together to solve this problem, to overcome this alienation and to give them the confidence, "Yes, you have this future there and we are all there to support you". We will all go there; we will sit there; we will tell them that whoever wants to come and meet us, please come. We will listen to everyone and we will generate that confidence. It is not as though we are going to come out with any great proposal. The proposals are there. The question is to create confidence among the people.

My last clarification is this. The Home Minister, in the concluding para 9, has stated and I quote:

"Once peace and order are restored, I am confident that we can explore the possibility of reactivating the political process that holds the key to solutions".

My point is that the process of restoring peace and order required the political process to go along simultaneously. It can't be one after the other. Therefore, in order to restore peace and order, it is necessary for the political process to begin and that should begin with an all-party delegation visiting Kashmir, and from there you start the political process and then your process of restoration of peace and law and order. I think that both must go simultaneously. That is what I urge upon him. (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him seek clarifications. When the Minister replies, he will definitely consider it.

SHRI SITARAM YECHURY: On the last occasion, when we went at the time of the Amarnath Yatra, it was the then Home Minister who carried the all-party delegation. That could work. You could work out your strategy, what could be the best. There is merit in first Members of Parliament going and subsequently the Government stepping in. There is also merit in the Government taking the lead and the Members of Parliament going later. I would suggest that first let the political process begin without the Government. Let Members of Parliament from all parties go first and generate the confidence amongst the people, and then the Government could step in on the basis of that. I think that would be a better strategy. So, that is what I will, therefore, suggest. Thank you.

(Ends)

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, the whole country is anguished at the situation that is prevalent in the State of Jammu and Kashmir. The Home Minister's statement makes very clear the dimension of the crisis in the State.

Sir, as far as my party is concerned, we believe in the political process that can bring a solution to the problems of Jammu and Kashmir State. I hope the Government should reassure that everything possible will be done under article 370 of the Constitution. The question of full autonomy needs to be addressed and also regional autonomy to the three regions, Jammu, Kashmir and Ladakh can be considered in this process.

Having said that, I would like to ask the Home Minister and the Government, with due respect to the security forces: What is our attitude in applying the Armed Forces (Special Powers) Act? In the case of Manipur, the Armed Forces (Special Powers) Act is not applied in Imphal city, if I am correct. It is not applied in Imphal city, but it was applied outside Imphal city. Why can't you think of such a thing in the case of Srinagar City? The Armed Forces (Special Powers) Act need not be applied in the State of Jammu and Kashmir for experiment because the security forces need not be in the streets of Jammu and Kashmir State. Sir, the situation is grave. Women are pelting stones. I don't draw any parallel from the history of the world. It definitely reminds me of the situation once prevailed in West Asia. The Palestinian women and children pelted stones at the tanks of Israelis.

(Contd. by 1X/VK)

SHRI D. RAJA (CONTD): Now the children are being killed; the women are being killed. As Prof. Soz has pointed out, there is colossal loss to the property. We should think radically to change the situation. I think the Armed Forces can vacate the streets of Srinagar. There are many ways to control the people. I do not want to call them as mob. I differ from some of my colleagues calling them mob. They are people of Jammu and Kashmir. There are several methods to control the people when they agitate. Water cannons can be used; rubber bullets can be used. Now straightaway firing at the people, I do not think that can bring the people with us and it will help us to build confidence measures with the people of Jammu and Kashmir. So, Sir, I think, the Armed Forces (Special Powers) Act will have to be relooked. Should it apply to the entire State? I think the Srinagar City can be kept out of the purview of this Act, as has been done in the case of Imphal. Then, Sir, negotiations will have to continue. Under article 370, the State must be reassured full autonomy. And there we can consider the regional autonomy to three regions. Finally, I tend to agree with what Prof. Soz has said. An all-party delegation can go there in order to win the confidence of the people of Jammu and Kashmir and to identify with them and they should also identify with us. When Shri Shivraj Patil was Home Minister, there was a Delegation to Jammu and Kashmir and there was a good response. I think there is a need for political process and the people of Jammu and Kashmir should understand that the whole country is concerned with their problems and is willing to address their problems and the whole country is with them. There, I think, the political process

is must and the political process should begin by reassuring that the problems of Jammu and Kashmir will be addressed under article 370. Thank you.

(Ends)

SHRI TIRUCHI SIVA (TAMIL NADU): Mr. Deputy Chairman, Sir, we share the concern of the Government towards the escalating unrest in the Valley and also understand the restraint it has to adhere in restoring the issue. The Minister's statement says, "The Central Government initiated a 'quiet dialogue' with key political groups and individuals. I had hoped that the dialogue would open a window of opportunity to activate the political process in order to find solutions. However, that dialogue was interrupted on 4th December, 2009, when there was an attempt on the life of Shri Fazl-ul-Haq, a leader who favoured dialogue, and he was seriously injured." The problem now which is going on is not by militants for the statements says, "There is reliable intelligence that some armed militants may have mingled with the crowds". So it is 'by the people' means, only a quiet dialogue could resolve the issue. What is the Government doing? Whether the atmosphere is congenial or not, you should have a quite dialogue. Why has it not been restarted after December, in these eight months? Is it not the right time to initiate a quiet dialogue? I would like to know from the hon. Minister, before mooting the idea of sending an all-party delegation, whether it is on the Government's agenda to convene an all-party meeting to discuss and resolve the issue. I would also like to know the composition of the Unified Command in Srinagar. I would like to know whether it is similar to that one in Naxal affected

areas, which comprises a retired Major General or it is different one. Thank you.

(Ends)

(Followed by 1Y)

AKG/1Y/12.50

श्री रामविलास पासवान (बिहार) : उपसभापति जी, अभी तक जो बातें चली हैं, मैं उनसे थोड़ा differ करता हूँ। कश्मीर एक समय जन्नत कहा जाता था। वहाँ के लोग तलवार की बात तो दूर रही, रूमाल से तलवार खेला करते थे। आज वह कश्मीर खून से खेल रहा है। हम यहाँ फौज का experiment कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार के मुताबिक वहाँ कितने terrorists हैं? वह संख्या हजार में भी नहीं होगी, सैंकड़े में होगी और वहाँ कितने लाख फौज है। हम फौज के बल पर वहाँ शान्ति-व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। फौज का दो काम होता है। एक यह होता है कि जो civilian है, उसकी रक्षा करना और दूसरा यह होता है कि जो terrorists हैं, उनसे लड़ना। लोगों का विश्वास सबसे बड़ा विश्वास होता है। आज लोगों का विश्वास हिल गया है। जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई से अलगाववादी तत्वों को बल मिल रहा है। जेटली साहब ने ठीक कहा कि इसके पीछे अलगाववादी तत्वों का हाथ हो सकता है। अलगाववादी तत्वों का हाथ हो सकता है, लेकिन क्या हम ऐसी कार्रवाई करें, जिससे अलगाववादी तत्वों को और बल मिलता जाए?

पिछली बार श्राइन बोर्ड का मामला था, तो एक issue था, जिस issue के ऊपर वहाँ घटनाएँ घटीं। आज कौन सा issue है? सबसे बड़ा basic प्रश्न है कि हम गृह मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो इतने निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, सब लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ issue क्या है? Issue सिर्फ इतना ही है कि एक civilian को encounter में मार दिया गया। जब एक निर्दोष को मारा गया, तो उसके खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। जब वे सड़क पर उतरे, तो बजाय इसके कि आप उन्हें सांत्वना देने का काम करते, बजाय इसके कि आप उसके परिवार के लोगों से मिलने का काम करते, आपने फौज का सहारा लिया और निर्दोष लोगों के मरने का सिलसिला जारी किया। मुझे नहीं मालूम

कि यह सिलसिला कितने दिनों तक चलेगा। ये जो 39 लोग मारे गए हैं, ये 39 लोग आपके कथनानुसार civilian हैं। इनमें कोई terrorist नहीं है। सर, हम उन लोगों में से हैं, जो हर साल कश्मीर जाते हैं। हम उन लोगों में से हैं, जो कश्मीर के डाऊन टाऊन एरिया में जाकर इफ्तार पार्टी करते हैं। जितना कश्मीर के सम्बन्ध में terrorists के बारे में बताया जाता है, यह vested interests के लोगों का काम है। Terrorists के नाम पर बहुत लोगों की रोजी-रोटी चलती है। जिस दिन वहाँ terrorists खत्म हो जाएँगे, उस दिन बहुत से लोगों की रोजी-रोटी खत्म हो जाएगी। हमें इस बात को भी समझने की आवश्यकता है।

श्री उपसभापति : रामविलास जी, आप खत्म कीजिए।

श्री रामविलास पासवान : सर, मैं खत्म कर रहा हूँ।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें इसे सेना के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हमें इसे humanitarian point of view से देखना चाहिए। आज भी अमरनाथ की बस की यात्रा हो रही है। हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। सैंकड़ों की संख्या में बसें जा रही हैं। कहाँ attack हो रहा है? हमारे परिवार का कोई आदमी मारा जाएगा और हम उसके funeral में जाएँगे, तो क्या हमें जाने का अधिकार नहीं है? आप वहाँ जाकर उनके ऊपर गोली चलाएँगे! 4 आदमियों ने पत्थर फेंक दिया, तो क्या इसके जवाब में आपके पास प्लास्टिक की गोली नहीं है या और दूसरी चीजें नहीं हैं? क्या आपके पास सीधे firing करके लोगों को मारने का सिर्फ एक ही हथियार है? यदि इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी, तो कभी घाटी में अमन-चैन होने वाला नहीं है।

इसलिए एक political will, इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। नेता के पास दिल होना चाहिए। दिमाग bureaucrats के पास रहता है, लेकिन नेता के पास दिल होना चाहिए। जब तक हम दिल से काम नहीं लेंगे, तब तक कश्मीर की समस्या solve होने वाली नहीं है और न ही यह आन्दोलन रुकने वाला है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस पर सरकार ने जिस तरह से संवेदना व्यक्त की है, उसी लहजे में सरकार, जो लोग मारे गए हैं, उनके आँसू पोंछने का भी काम करे और देखे कि भविष्य में किसी माँ का बेटा या बच्चा उसकी गोद से नहीं छीना जाए और निर्दोष लोगों की हत्या नहीं हो, इसकी गारंटी सदन में देनी चाहिए।

(समाप्त)

(1जेड/एससीएच पर आगे)

1z/12.55/sch-ks

श्री राशिद अल्वी (**आन्ध्र प्रदेश**): सर, पर्शियन का एक शेर है -

ग़र फ़िरदौस बररुए जमीनस्तो

हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्तो

अगर इस दुनिया में कहीं जन्नत है, तो यही कश्मीर है, यही कश्मीर है। लेकिन सर, आज वह जन्नत जहन्नुम बनी हुई है। आज जिन हालात से कश्मीर गुज़र रहा है, शायद पिछले 63 साल में उन हालात से नहीं गुजरा। एक महीने में 40-50 लोग मारे गए, जिनमें 17 बच्चे हैं और जिनकी उम्र सात, आठ या दस साल की है। यह चिन्ता का विषय है।

सर, मैं बड़े अदब से होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि इसका जो इम्पैक्ट हमारे यहां हो रहा है, वह तो हो ही रहा है, लेकिन इसका इंटरनैशनल इम्पैक्ट क्या हो रहा है? वह और भी ज्यादा खराब हो रहा है। सर, अभी यूनाइटिड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट आया है, Ban ki-moon ने कहा है। The Home Minister would have definitely gone through this statement. He has voiced concern about the prevailing situation in the 'Indian Occupied Kashmir'. He does not consider Kashmir to be a part of India. So, he has talked about the prevailing situation in the 'Indian Occupied Kashmir' and called for further resumption of Indo-Pak composite dialogue. We are unable to resolve whatever is happening in Kashmir, according to the Secretary-General of United Nations. He says that we cannot do it without the consent of Pakistan. हमें पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी, तभी हम कश्मीर की समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह बहुत सीरियस बात है। हम अपने घर में बैठकर कहते रहें कि कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब तक बाहर के लोगों को हम यह यक़ीन नहीं दिलाएंगे। पाकिस्तान के एम्बेसेडर ने अभी तीन दिन पहले ही

बोला है कि कश्मीर की सिचुएशन तब तक ठीक नहीं हो सकती, जब तक पाकिस्तान के साथ बात-चीत नहीं होगी। यह बात वहां का एम्बेसेडर बोल रहा है। अमरीका के अन्दर ह्यूमेन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशंस कॉन्फरेंसिज़ कर रही हैं; the Home Minister must know this कि उन कॉन्फरेंसिज़ के अन्दर रैज़ोल्यूशंस पास हो रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: आप क्लैरिफिकेशन पूछिए ...(व्यवधान) क्लैरिफिकेशन पूछिए ...(व्यवधान)

श्री राशिद अल्वी: सर, होम मिनिस्टर से मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि: what shall be the impact internationally?

और मेरा सैकेंड क्लैरिफिकेशन है: The Home Minister has said in his statement that the Government of Jammu and Kashmir is actively considering a number of political and administrative measures that would help restore normalcy. The Chief Minister, while affirming his commitment to take certain political and affirmative measures, has made it clear that the current cycle of violence would have to end before he can take the initiative. Sir, my question is: what kind of initiative are you taking? Are you sure that these initiatives will help resolve the situation? The primary concern is that there should be peace in Kashmir. This is not the time to blame any political party. The party that is ruling Kashmir today, was ruling Kashmir in yesteryears with your help. Today, it is ruling with our help. It is not the question of who is responsible. The basic thing is, peace should be there in Kashmir.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri H. K. Dua. I request all Members to be brief.

SHRI H. K. DUA (NOMINATED): Sir, there is, certainly a sensitive situation and the Home Minister's statement has a welcome hint of starting a political dialogue with political groups and individuals. The dialogue was disrupted, unfortunately, last December.

It is just not a law and order situation. There is need for political dialogue with various elements in the State across the broad spectrum. I would like to know who is going to talk and when the dialogue is going to start. I am asking this also in the context of the previous promises we have made to the people of Kashmir, P. V. Narasimha Rao onwards. He said sky is the limit for giving autonomy to Kashmir. Mr. Vajpayee, when he was the Prime Minister, said that there will be talks but "इन्सानियत के दायरे में बात-चीत हो"। Dr. Manmohan Singh has been repeating the promise of autonomy and the talks. The last time that he spoke about the dialogue, and a quiet dialogue, the Home Minister did not rule out the question of autonomy. Will the political dialogue he has in mind pick up the threads from where they had been left last time?

(Ends)

(Followed. at 2a/kgg)

श्री मोहम्मद अदीब (उत्तर प्रदेश): सर, होम मिनिस्टर साहब की रिप्लाई के बाद और अखबारों में पढ़ने के बाद यह अंदाजा हुआ कि कश्मीर के जो हालात हैं, ऐसे कभी नहीं हुए। लेकिन, अगर तसफिया किया जाए, अपने गिरेबान में मुँह डाला जाए, तो कहीं-न-कहीं हम भी कुसुरवार पाए जाएँगे...

श्री उपसभापति: आप क्लैरिफिकेशन ही पूछिए।

श्री मोहम्मद अदीब: मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, सर। जब यह मुल्क आजाद हुआ था तो ...(व्यवधान)... यह तय हुआ था कि...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: क्लैरिफिकेशन देना नहीं, लेना है।

श्री मोहम्मद अदीब: कौन हिस्सा किधर जाएगा तथा कौन पाकिस्तान होगा और कौन हिन्दुस्तान होगा? कश्मीर की अवाम ने खुद यह फैसला किया था कि वे हिन्दुस्तान में आएँगे। शेख अब्दुल्ला ने सन 1966 में अलीगढ़ में यह कहा था कि मैं अपनी कौम की लाशों पर से गुजरकर यहाँ गांधी और नेहरु से यह कहने आया था कि मुझे जिन्ना के तास्सुब से बचा लो। हमने उन शेख अब्दुला को दसियों साल जेल में रखा। यह बुनियाद पहले पड़ी। आज तक कश्मीर के साथ यह हो रहा है कि वहाँ के बच्चों को आज भी यहाँ शक और शुबहे की नजर से देखा जा रहा है। मैं सिर्फ तीन सजेशंस के साथ यह कहना चाहता हूँ कि ...

श्री उपसभापति: आप सजेशंस नहीं दीजिए, क्लैरिफिकेशन पूछिए।

श्री मोहम्मद अदीब: सर, कश्मीर के बच्चों को हिन्दुस्तान में, यहाँ की मेन स्ट्रीम में, नौकरियों के लिए स्पेशल मराआत दिए जाएँ, ताकि वे लोगों के साथ interact कर सकें, लोगों से मिलें और यहाँ वे यह समझें कि वे हिन्दुस्तान का ही एक हिस्सा हैं। यह एक बुनियाद हुकूमत को बनानी चाहिए।

दूसरी बात, पाकिस्तान को यह बाआवर कर देना चाहिए कि वह अगर इसमें मुदाखलत करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि Human Rights Activists को भी कश्मीर भेजना चाहिए। जैसा अभी हमारे सोज़ भाई ने कहा, यह एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन हमको शक और शुबहात के दायरे से निकलकर किसी न किसी सूरत से कश्मीर के लोगों को यहाँ लाना पड़ेगा, फौज पर पाबंदी लगानी पड़ेगी और यहाँ के जो एक्टिविस्ट्स हैं उनको वहाँ भेजना पड़ेगा।

मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि जैसा हमारे राजा डा0 कर्ण सिंह साहब ने एक शेर पढ़ा था कि "नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद वह मुहब्बत कर बैठे", तो यह वक्त है कि वह मुहब्बत करेंगे, वे हमारे हैं और हमारे रहेंगे। हमारे पड़ोसी को कहीं-न-कहीं सोचना पड़ेगा। हमने कहीं-न-कहीं गलती जरूर की है।

(समाप्त)

جناب محمد ادیب (اتر پردیش) :سر، ہوم منسٹر صاحب کی ریپلائی کے بعد اور اخباروں میں پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ کشمیر کے جو حالات ہیں، ایسے کبھی نہیں ہوئے، لیکن اگر تصفیہ کیا جائے، اپنے گریبان میں منھ ڈالا جائے، تو کہیں نہ کہیں ہم بھی قصوروار پائے جائیں گے۔

جناب اپ سبھا پتی : آپ کلیرفکیشن ہی پوچھئے۔

جناب محمد ادیب : میں صرف کلیرفکیشن دے رہا ہوں، سر۔ جب یہ ملک آزاد ہوا تھا تو ---(مداخلت)--- یہ طے ہوا تھا کہ ----(مداخلت)----

جناب اپ سبھا پتی : کلیرفکیشن دینا نہیں ہے، لینا ہے۔

جناب محمد ادیب : کہ کون حصّہ کدھر جائے گا کون پاکستان ہوگا اور کون ہندوستان ہوگا؟ کشمیر کی عوام نے خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہندوستان آئیں گے۔ شیخ عبداللہ نے سن 1966 میں علی گڑھ میں یہ کہا تھا کہ "میں اپنی قوم کی لاشوں پر سے گزر کر یہاں گاندھی اور نہرو سے یہ کہنے آیا تھا کہ مجھے جناح کے تعصب سے بچا لو"۔ ہم نے ان شیخ عبداللہ کو دسیوں سال جیل میں رکھا۔ یہ بنیاد

جناب اپ سبھا پتی : آپ سجیشنس نہیں دیجئے، کلیرفکیشن پوچھئے۔

جناب محمد ادیب : سر، کشمیر کے بچوں کو ہندوستان میں، یہاں کی مین اسٹریم میں نوکریوں کے لئے اسپیشل مراعات دئے جائیں، جس میں وہ انٹریکٹ ہوں، لوگوں سے ملیں اور یہاں وہ یہ سمجھیں کہ ہندوستان کا ایک حصّہ ہیں۔ یہ ایک بنیاد حکومت کو بنانی چاہئے۔

دوسری بات، پاکستان کو یہ باآور کر دینا چاہئے کہ اگر وہ اس میں مداخلت کرے گا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔

تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ Human Rights Activists کو بھی کشمیر بھیجنا چاہئے۔ جیسا ابھی ہمارے سوز بھائی نے کہا، یہ ایک بہت اچھا قدم ہے، لیکن ہم کو نہ شک و شبہات کے دائرے سے نکل کر کسی نہ کسی صورت سے کشیمر کے لوگوں کو یہاں لانا پڑے گا، فوج پر پابندی کرنی پڑے گی اور یہاں کے جو activists ہیں ان کو وہاں بھیجنا پڑے گا۔

میں ہوم منسٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا ہمارے راجہ ڈاکٹر کرن سنگھہ صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا کہ "نفرت سے نہ دیکھو دشمن کو، شاید وہ محبّت کر بیٹھے"۔ یہ وقت ہے کہ وہ محبّت کریں گے، وہ ہمارے ہیں اور ہمارے رہیں گے۔ ہمارے پڑوسی کوکہیں نہ کہیں سوچنا پڑے گا۔ ہم نے کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کی ہے۔

(ختم شد)

श्री राजनीति प्रसाद (**बिहार**): सर, कश्मीर वादियों का एक खूबसूरत स्थान है और हमलोग उसको..

श्री उपसभापति: आप क्लैरिफिकेशन पूछिए। ...(व्यवधान)... कश्मीर बहुत अच्छी जगह है, यह सब को मालूम है। ...(व्यवधान)...

श्री राजनीति प्रसाद: सर, कश्मीर वादियों का एक खूबसूरत स्थान है। वह जहाँ में सबसे सुन्दर जगह है। वहाँ की एक साधारण-सी घटना पर इतना एजिटेशन हो गया कि वहाँ इनकाउंटर में एक बच्चे को मार दिया गया और उसके बाद ये घटनाएँ घटी हैं। मैं गृह मंत्री जी से क्या यह पूछ सकता हूँ कि क्या इस समस्या का कोई और समाधान नहीं था या यह केवल मिलिट्री भेजने का ही मामला था?

सर, दूसरी बात यह कि हमारे एल0ओ0पी0 साहब ने कहा कि वहाँ बच्चे स्कूल के बैग में पत्थर रखते हैं, तब यह तो अच्छा हुआ कि वे पत्थर ही रखते हैं, उन्होंने यह नहीं कहा कि वे उसमें बम रखते हैं। खैर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस समस्या का बंदूक के अलावा क्या और कोई दूसरा समाधान नहीं था कि चार वर्ष के, सात वर्ष के बच्चों को मार-मार के वहाँ सुला दिया गया? इसके बाद आप खुद कहते हैं कि हमें दुख है। यह * जो आपने वहाँ बच्चों को मारने के लिए, innocent लोगों को मारने के लिए किया और राम विलास जी ने सही कहा कि उसमें कोई आतंकवादी नहीं मारा गया, कश्मीर बॉर्डर को क्रॉस करने में कोई नहीं मारा गया। तो आप जरा इस पर विचार करिए कि क्या गोली के अलावा कोई दूसरा भी यंत्र था जिससे आप वहाँ की स्थिति को काबू में कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? यही मैं पूछना चाहता हूँ।

(समाप्त)

---

* **Not recorded**

(2बी/डी0एस0 पर आगे)

DS-TDB/2B/1.05

श्री जी.एन. रतनपुरी (जम्मू और कश्मीर): सर, मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिए because I represent Jammu & Kashmir.

श्री उपसभापति: आप clarifications पूछिए।

श्री जी.एन. रतनपुरी: सर, मैं clarifications ही मांग रहा हूँ। होम मिनिस्टर ने कहा है कि हम कश्मीर में political process शुरू करेंगे और यह मसला हमें सियासी तौर पर तय करना है। 1947 से यह political process चल रहा है। Between the State and Centre, कई agreements हुए हैं। पहले हमें यह देखना है कि उन agreements का क्या हश्र हुआ, उनका क्या अंजाम हुआ, ये दूरियाँ क्यों पैदा हो गयीं और यह mistrust क्यों पैदा हो गया। अगर वहाँ कोई Parliamentary Delegation, कोई भी टीम या मिनिस्टर्स जाएँ, तो पाएँगे कि वहाँ credibility नहीं है, लोग एतबार नहीं करेंगे। You have to offer something other than talks. 1947 से बात चल रही है, लेकिन बात में से कुछ निकलना चाहिए। 9 अगस्त 1953 को, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्हें depose किया गया। शायद कश्मीर उनसे बड़े stature या उनसे बड़े following का लीडर future में नहीं देखेगा, लेकिन अगर Govt. of India को लगा कि उनकी वजह से security of India किसी तरह से, चाहे यह गलतफहमी हो ..(व्यवधान)

श्री उपसभापति: देखिए, आप clarifications पूछिए। There is no time for all this.

श्री जी.एन. रतनपुरी: आप मुझे दो मिनट अपनी बात कहने दीजिए, प्लीज़। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन यह एक ऐसा issue है कि इस पर हमें बोलना है, क्योंकि इस पर लोग हमें यह कहते हैं कि आप बात क्यों नहीं करते, जब आप हिन्दुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में हैं तो आप वहाँ बैठ कर क्या करते हैं? हमें वहाँ भी जवाब देना है। तो अगर उस autonomy के बावजूद

उस वक्त इतने बड़े लीडर को हटाया जा सकता था तो मेरे ख्याल में आज सबसे पहला स्टेप यह होगा कि आप autonomy को बहाल कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से over the last 57 years जो भी ईख्तियारात लिये हैं, उनको लौटाने की बात कीजिए तो शायद आपकी बात पर वहाँ कोई ध्यान देगा।

दूसरी बात यह है कि Govt. of India सिर्फ पुलिस, security agencies और intelligence agencies पर बहुत ज्यादा rely करती है। जब political process की बात हो तो आप अवाम के नुमाइंदों से बात करें। हम यहाँ दिल्ली में हैं, कभी हमें भी बुलाएँ और हमसे भी जानने की कोशिश करें। Security Forces में सभी फरिश्ते नहीं हैं। यह प्रॉब्लम सिर्फ कश्मीर में नहीं है, अब यह पूरे मुल्क में हो रहा है। Security Forces या पुलिस के खिलाफ कोई criticism बर्दाश्त नहीं की जाती, यह बिल्कुल blasphemy के बराबर माना जाता है। वहाँ भी ऐसे लोग हैं जो points score करने के लिए, अपने ACR को बढ़ाने के लिए या किसी और मकसद के लिए गलतबयानी से काम लेते हैं। कल मेरी constituency में हालात खराब थे। मैंने बात की तो मुझे बताया गया कि crowd में militants हैं, उन्होंने फायर किया। होम मिनिस्टर साहब ने भी यह कहा है कि crowd में militants होते हैं। स्टेट पुलिस जो हर शाम को briefing या handout देती है, उसमें उन्होंने आज तक यह mention नहीं किया है। मैंने कल शाम को उस incident के बारे में mention किया और independent sources से पता करने की कोशिश की। I am inclined to presume, क्योंकि आजकल आर्मी हेल्प को नहीं आती है, लेकिन अगर militancy का जिक्र करें कि militant है तो शायद आर्मी निकल आये। वहाँ हालात ज्यादा खराब थे और वहाँ security forces and Police इतनी नहीं थी कि वे उस situation को tackle कर पाती। इसके लिए District Magistrate और District Superintendent of Police ने रिक्वेस्ट की थी। आज कश्मीर में आर्मी बुलाने का यह मकसद नहीं है कि उनको cantonment से निकलना है। तकरीबन हर टाउन में आर्मी मौजूद है और normally वह निकलती है और इसका हल करती रहती है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि

पिछली बार चीफ मिनिस्टर को क्यों रिक्वेस्ट करनी पड़ी। Normally, District Magistrate की रिक्वेस्ट पर आर्मी निकल आती है और law and order situation में भी हेल्प करती है। जब खुद होम मिनिस्टर साहब यह कहते हैं कि crowd में militants होते हैं, it becomes a sort of their duty. Armed Forces Special Powers Act के तहत हेड कान्स्टेबल से ऊपर के लेवल के किसी भी ऑफिसर को वहाँ जाने और intervene करने का इख्तियार है। यह समझ में नहीं आता कि जब जरूरत पड़ी और आज जब सूरत-ए-हाल बहुत ज्यादा गम्भीर है तो चीफ मिनिस्टर को क्यों लिखना पड़ता है। आज वहाँ हर गांव में सूरत-ए-हाल खराब है और अगर local administration request करती है, तो इसमें आर्मी को हेल्प करनी चाहिए थी। ऐसा हर कहीं होता है, मुल्क के किसी भी हिस्से में होता है, तो यह क्यों नहीं हो रहा है? मैं होम मिनिस्टर साहब से एक तो यह जानना चाहूँगा कि उन्होंने किस आधार पर यह कहा कि crowd में militants हैं? क्या कहीं फायर हुआ है या कहीं यह रिपोर्ट हुआ है? दूसरे, यह कि अगर Parliamentarians या politicians का कोई delegation जाता है तो वे क्या offer करेंगे? सिर्फ talks से कुछ नहीं चलेगा, यह उन्होंने clear कर दिया है। हम 1947 से अब तक talks करते रहे हैं, agreements का तो बुरा हश्र कर दिया, talks की तो बात ही नहीं है। थैंक यू।

(समाप्त)

SHRI Y.P. TRIVEDI (MAHARASHTRA): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this issue. The situation in Kashmir seems to be perennial. There are times when there is peace, but some incident takes place, and suddenly, there is violence, largely inflamed by forces from across the border. The situation, if not alarming, is certainly quite serious.

(Contd. by 2c-kls)

SHRI Y.P. TRIVEDI (CONTD): What is the need of the hour is that the entire House, the entire country is behind the Government cutting across all the party lines. We believe that the Governments hand should be strengthened. What should be attitude of the Government, what should be the policy of the Government, political solution is one thing, but the first and the primary duty of any Government is to maintain law and order. What is the need of the hour, according to me, is twin-fold. We need action of the sturdiness of Abraham Lincoln who said that 'in spite of violence we will see to it that there is no further division or there is no further bifurcation.' Attitude of Abraham Lincoln should be adopted in the first instance. The second thing which is the need of the hour is what Mahatma Gandhi did when he want Nokhali. A delegation from all of us, from this House should go there, should sit there, talk with people, inspire confidence in their minds and whatever is the problem, you should try to understand that. For all this, I think, the Home Minister should be assured that the entire House cutting across all the party lines is behind his action. Thank you.

(Ends)

सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा (पंजाब) : उपसभापति जी, जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि कश्मीर का मसला आज से नहीं, बल्कि 1947 से ही चल रहा है और आज जो हालात हैं, बहुत बुरे हो गए हैं, बद से बदतर हो गए हैं। सारे देश में इस पर चिंता है और सारा देश इस पर एकजुबान है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले तो बहुत देर तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। जैसा हमारे साथी ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजेपयी, प्रधान मंत्री होते हुए खुद बस लेकर गए और उन्होंने कहा कि मैं हर विषय पर बात करना

चाहता हूं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर डा. मनमोहन सिंह आए हैं, इन्होंने कोशिश की है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, बल्कि वहां के लोग और ज्यादा खलल डाल रहे हैं। मेरा यह सुझाव है कि इन हालात को सुधारने के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। मैं सोज़ साहब के सजेशन के साथ हूं कि वहां पर सभी पार्टियों के एम.पीज़ का एक डेलीगेशन जाना चाहिए। पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, उसके बाद कोई फैसला होना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर से पंडित तो पहले ही आ गए हैं, लेकिन अभी सिख लोग वहां पर हैं। पहले एक दफा उन पर हमला किया गया, ताकि वे वहां से चले जाएं, जिसमें बहुत से सिख मारे गए। अभी हाल ही में उनके बाल काट दिए गए। इस पर बहुत एजीटेशन हो रहा है। हो सकता है कि वे यह चाहते हों कि सिख भी यहां से चले जाएं। सिख लोग हमेशा भाईचारे और एकता में विश्वास करते हैं और किसी के खिलाफ नहीं हैं, उनको भी वहां से निकालने की कोशिश हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर क्या इस पर कोई ऐक्शन लेंगे?

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब में मिलिटेंसी की गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं और यह बात होम मिनिस्टर साहब जानते हैं। क्या उनका कश्मीर के militants से कोई नाता है, क्या उनको वहां से कोई सपोर्ट मिलती है, क्योंकि दोनों की बात पाकिस्तान से चलती है। मैं एक क्लेरिफिकेशन यह भी चाहता हूं कि पंजाब के सी.एम. हमारे होम मिनिस्टर साहब से मिले थे और उन्होंने कहा था कि अभी इस स्टेज को संभाल लो और हमारी जो para military forces हैं, उनको आप modernize करो, यदि आप इनको modernize नहीं करोगे, तो स्थिति और खराब होगी। पाकिस्तान से पंजाब में और कश्मीर में terrorists आ ही रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस को modernize करने का सरकार का कोई विचार है?

(समाप्त)

SHRI SITARAM YECHURY (WEST BENGAL): Sir, I have only one point to make. I want the hon. Home Minister to keep in mind that the holy month of Ramadan is coming. So, before that whatever initiative is to be taken should be taken.

(Followed by 2D/SSS)

SSS/2D/1.15

SHRI P. CHIDAMBARAM: Mr. Deputy Chairman, Sir, I have heard the hon. Members, who have sought clarifications on my Statement that was made day before yesterday, very carefully. I am grateful to the hon. Leader of the Opposition as well as all other leaders who have joined me in expressing our deep sense of regret and anguish at the loss of lives in Jammu and Kashmir. Sir, the problems of Jammu and Kashmir are problems that have remained with us since 1947. It was not my intention when making a Statement to lay out a road map to the solution of those problems. It could not have been done in a Statement that describes the current situation nor is it possible to deal with those problems while replying to clarifications on that Statement. The statement was intended to capture the current situation, how we intend to deal with the current situation and, therefore, with your permission, Sir, I should be very happy to answer questions that pertain to the current situation. Sir, it is often forgotten that beginning 2004 and up to the middle of this year, except the year 2008, Jammu and Kashmir has not witnessed serious civilian strikes. I underline the word 'civilian'. We have had incidents involving terrorists and infiltrators on the border, maybe even inside the borde,r but, if you leave that out, the State has been largely peaceful and there has been no civilian unrest since 2004. Sir, 2008 was an exception when the

Amarnath Yatra triggered a controversy and lives were lost. In fact, a hundred lives were lost that year. But, otherwise, I think, it is well to remember that very, very few lives were lost in those years. In 2005, it was actually one, in 2006 it was six, in 2007 it was two and in 2009 it was only seven. I think, in large measure or at least in substantial measure the fact that there was no civilian unrest in Jammu and Kashmir is owing to the policy pursued by the UPA-I Government and the policy that was pursued by UPA-II beginning May 2009. The Amarnath strife was a separate issue and I don't wish to go into that now. I do not think raising issues like abrogate articles like 370 do not offer a political solution to the Jammu and Kashmir issue or send more paramilitary forces, send in the Army. I think, this is not the policy of the UPA Government and with great respect to the Leader of the Opposition, some of these demands were articulated in a memorandum submitted by the principal opposition party to the Prime Minister yesterday, we beg to differ. This is not the approach that we should adopt for Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir acceded to India under very unique circumstances. That is why on my first visit to Jammu and Kashmir after I took over as Home Minister I said, 'this is a unique problem. There is a unique history to the problem and therefore, we must put our heads together to find a solution, a unique solution to this unique problem'. That is what I said.

(Contd. By NBR/2E)

-SSS/NBR-MP/2E/1.20

SHRI P. CHIDAMBARAM (CONTD.): Be that as it may, I think, it is important to win hearts and minds in Jammu and Kashmir. The fact that there is no civilian

strife for five out of six years gave me a lot of encouragement when I embark upon the path of quiet dialogue. The quiet dialogue did yield result. Between May and December 4, 2009, there was hardly any civilian strife. I am no attributing it entirely to the quiet dialogue. But, certainly, the quiet dialogue contributed to the fact that there was, largely, peace and order in Jammu and Kashmir. The dialogue was interrupted on December 4, as I said in my statement, when Fazal-ul-Haq Quereshi, a moderate leader who favoured dialogue, was very seriously injured. Since then, I confess, we have not been able to resume the quiet dialogue. But, it is my intention to do everything possible to resume the quiet dialogue.

Sir, it is true that Pakistan appears to have altered its strategy in influencing events in Jammu and Kashmir. I do not think there is any let up, as such, in infiltration nor is there any let up in sending militants into the Valley. But, as the hon. Leader of the Opposition pointed out, our capacity to deal with infiltration and militancy is, certainly, much higher today than what it was a few years ago. Our intelligence is, certainly, better equipped. And, therefore, we have been able to foil these designs. Sir, it is possible that there is an altered strategy. It is possible that they believe that relying upon civilian unrest will pay them better dividends. But, I am confident, if we are able to win the hearts and minds of the people of Jammu and Kashmir, even those designs can be foiled.

Sir, there are a number of issues which deserved to be addressed. The most important is, our own pronouncements and our own promises to the people of Jammu and Kashmir, the larger issue of solving the problem of Jammu and

Kashmir, the problems that are raised by Pakistan, is a larger issue. We will keep that aside for the time being. But, there are our Government's pronouncements and our own promises to the people of Jammu and Kashmir in that part of Kashmir which is with India. And, I think, it is important that we deliver on our promises and we follow-up on our own pronouncements. There is intense debate on these issues, as they should be. There is an intense debate in the country. There is an intense debate in many fora, including Parliament. There is intense debate within the Government too and that is only to be expected. In a coalition Government, intense debate is to be expected. But, I have not yielded on the argument that Government must deliver on the promises that made, the Government must follow-up on the pronouncements that were made. One amongst them is the Armed Forces (Special Powers) Act. I cannot brush aside other points of view. But, it will be my endeavour to work with everyone else and find a way in which we can deliver on our promise on the AFSP. Likewise, we have said that we would like to reduce the presence of security forces if conditions improve. In fact, we did it in 2009. A significant number of armed forces personnel were moved out of the valley. A significant number of paramilitary forces personnel were also moved out of the valley. When the situation warrants, we may have to send more forces. But, when the situation warrants, we may have to withdraw the forces too. And, that is the policy of the Government of India.

(CONTD. BY PK "2F")

SHRI P. CHIDAMBARAM (CONTD.): Sir, the UN Secretary General did not make the statement attributed to him. In fact, it was made by one of his staffs who happens to be a national of Pakistan. The UN Secretary General's office has flatly denied any such statement. In the immediate short-term, this is an area in which I agree with the Leader of the Opposition and many others, we must bring an end to the violence on the streets of Jammu and Kashmir. I think it requires firm action by the security forces as well as the Government of Jammu and Kashmir reaching out to the people. It is not my purpose to find fault, to apportion blame, but I think some lessons have been learnt. I think the Government of Jammu and Kashmir is now reaching out to the people. The Chief Minister has visited the injured people in the hospitals. Ministerial delegations have been sent to various district headquarters. We have advised the Government to ensure that the District Magistrates and other civilian officials are more visible, more present and more accessible to the people. In the last 48 hours, there has been a declining trend of incidents. I am not saying that this is the beginning of the end of violence, I hope it is sincerely. There is, certainly, a declining trend, but there is no comfort in the fact that there is only one death a day. Loss of one life diminishes all of us. The loss of one life diminishes the credibility of governance in this country, but it is my sincere hope that our appeal, the appeal made by all the hon. Members belonging to all sections will be heeded by the people of Jammu and Kashmir. Sir, there was a period in 2004-05 when the streets of Jammu and Kashmir did not hear the word *'azadi'*. On the contrary, youth came and said, "we want an MBA programme in the University.

We want an IIT to be established here. We want an IIM to be established in Jammu and in Sri Nagar." It is unfortunate that those voices have been muted and the voices of *azadi* or Quit India have been raised. But I sincerely hope that this is only a passing phase and we will hear the voices of young Kashmiris saying that their destiny lies with India and that they want to be part of the India. I am sure that the voices that we heard in 2004, 2005 and 2006 will be heard once again on the streets of Jammu and Kashmir. The immediate task is to restore law and order. No Government can allow the law and order to collapse. That means, the Government has collapsed. So, we have to restore law and order. The Armed Forces have acted, as I said in my Statement, with a great degree of restraint. Over a thousand security personnel have been injured. And, they have been injured in the eye; they have been injured in the head; they have been injured in other sensitive parts of the body. Stones have been thrown by crowds running into a few thousands and if a few thousand stones are raining on police post or a platoon, you can imagine the kind of injury which they will suffer. I think they have acted with restraint. They have used *lathis*, they have used tear gas; then, they have used rubber bullets. In fact, some of the deaths have occurred because the rubber bullets can also kill if they hit a wrong spot in the body. To the bitter end, they have used the regular bullets too and they have killed. We continue to advise our security forces to act with restraint, but security forces, as I said in my Statement, have to act not only in self-defence but also to protect police stations, police outposts and Government offices. So, we will resume the political process. The answer to the problem of Jammu and Kashmir lies only through the political process and only through dialogues with all sections of the people.

(Contd. by PB/2G)

PB/2G/1.30

SHRI P. CHIDAMBARAM (CONTD.): Sir, we will resume the political process. Yesterday, we received a message that an All Party Delegation from Jammu and Kashmir wishes to call on the Prime Minister and I am happy to say that the Prime Minister has agreed to receive the All Party Delegation. We hope the delegation will come soon. In fact, we will be very happy to receive the delegation even as early as Monday.

Secondly, we are contemplating convening a meeting of leaders of political parties in Parliament. The date and time will be fixed by the Prime Minister's Office. We will let you know. So, let us meet here first, and, certainly, we will take on board your suggestion that a Parliamentary Delegation should visit Jammu and Kashmir. All this is part of reactivating the political process. Simultaneously, I have once again pressed upon all our interlocutors in Jammu and Kashmir that I am willing to resume the quiet dialogue. What happened in December 4 was indeed a rude interruption but we have to get over that. We have to pick ourselves up, we have to find the courage that allowed us to hold a dialogue earlier and I sincerely hope that moderate leaders will resume their dialogue with the Government of India.

If Mr. Gilani's statement of day-before-yesterday marks a shift in his position, I do not know. But if it marks a shift in his position, I think, we should welcome that shift in his position. I think we should accept at face value his statement until the contrary is proved. I don't think there is any reason to doubt

people's statement. If it is a shift in his position, I would welcome that shift in position and I would be very happy if Mr. Gilani also joins the group of leaders who wishes to hold a dialogue with the Government of India in one form or the other.

Sir, there are some good signs. This year up to the 3rd of August, we have had 5,10,781 tourists visiting the State. That is a larger number than last year. This year until the 3rd of August, 4,11,407 yatris had *darshan* at Amarnath shrine. Last year the total number until the end of the yatra was 3,92,000 and we still have another 17 days for the yatra to conclude, and I think that the number will cross 5 lakhs. So, there is something else happening in Jammu and Kashmir also that the people of that State are welcoming the yatris, are welcoming tourists, people who depend upon tourism for their livelihood, people who depend upon the yatra period for earning their income for the rest of the year, those who supply ponies, those who supply food and those who carry the *dollies*. I think there is something else also happening in Jammu and Kashmir, a story that is somehow not reflected in our discourse or in our media. So, while, unfortunate events have happened in the streets of Jammu and Kashmir, something else is also happening in Jammu and Kashmir.

It is important that the cycle of violence must come to an end, and, let me conclude, Sir, by once again warmly thanking all hon. Members and appealing to the people of Jammu and Kashmir, especially, young men and women, especially parents. Please work with us and put an end to this current cycle of violence so that we will pick up the threads, we will reactivate the political process and we will

through dialogue find solutions that will bring equity, justice and honour to all sections of the people of Jammu and Kashmir. (Ends)

MESSAGE FROM LOK SABHA

THE APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 2010

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (No. 4) Bill, 2010, as passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 5th August, 2010.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at thirty-five minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at thirty-nine minutes past two of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KALRAJ MISHRA) in the Chair.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

RESOLUTION RE: CONSTITUTION OF AN ENVIRONMENT ADAPTATION AND MITIGATION FUND - (CONTD.)

SHRI N.K. SINGH (BIHAR): Thank you, Sir. I had, while making an intervention on the last occasion on this subject, made some suggestions for the constitution of a fund for mitigation and adaptation on environmental challenges. In that first intervention of mine, I had given an overall global framework of why we needed such a fund, what the costs are likely to be and what are the various dimensions on account of adaptation and mitigation problems.

(continued by 2k - sk)

-ksk/sk/2K/2.40

SHRI N.K. SINGH (Contd.): And, in addition to financing a technology, we needed to take a holistic view of the entire issue. In today's intervention of mine, Sir, I wish to concentrate on two basic problems. First, how to raise the money? From what sources? And, to recall that, one of the principal objectives of the Environmental Adaptation and Mitigation Fund is to move away from inefficient highly polluting energy intensive industries. Second, how to spend the money? This goes beyond merely the normal question of expenditure, but into the deeper question of how to make the governance of this fund multi-disciplinary,

complementary and catalyst to the efforts of the private sector which is capable of keeping pace with the emerging science and technology on this issue.

I want to be clear about the scope of what I am discussing here today, Sir. This is not a fund to address every challenge of environment. It is not, because those challenges are far more complex. What I am focusing on today is how we can best use innovative public finance mechanisms to both push people away from unsustainable practices and pull new technologies and practices that are more sustainable and support the adaptation effort of the Government.

Let me also say that while making the suggestions, I am conscious of the broad inequalities of the economy, namely, the large parts of the country don't have access to energy at all, and, therefore, there must be a floor level of minimum energy availability in any effort which we design. Let me also just remind your, Sir, that estimates which have been made, globally speaking, on what it would cost for mitigation and adaptation efforts to bring the green house emission to levels which are considered safe on current scientific estimates, they would require an investment of two hundred billion dollars to one trillion dollars per annum. These estimates can increase if, for instance, the scientific community comes to the conclusion that the present levels of projected reduction in green house emission should be more aggressive in order to really deal with the environmental challenges.

Let me now directly go to the important question which I had raised: How to raise the money for the Environmental Adaptation and Mitigation Fund in India? Clearly, Sir, the first and the one obvious source is to have a carbon tax in order to

promote low carbon intensive activity. This creates a push for cleaner technology. We already have energy cess on coal to start with. So, what I will discuss is how to complement and supplement this broad measure of cess on coal in other dimensions. This Environment Adaptation and Mitigation Fund would complement the coal tax by focusing more on downstream fuel use, specially highly-polluting fuels as well as fuel use for upper income groups. Some other revenue streams to tap these, which are consistent with this approach, are these. First, a diversion of cess on aviation turbine fuel. We clearly harmonise this across the States to reduce distortions, but one option is to keep the level the same while diverting some part of their accrual of this aviation turbine fuel cess towards the Environmental Adaptation and Mitigation Fund. This, Sir, is also quite consistent with the recommendations of the global discussion of tax on air travel. Second, taxing small fossil-fuel power generation, including smaller captive power plants. This is actually inefficient power generation and is, unfortunately, encouraged by the current electricity policy scenario. Raising the cost of substitutes for an efficient public network would create more pressure for faster improvement in the electricity sector. Third, a surcharge on per capita energy usage above a certain level. This would only hurt the more elite class, and, therefore, it would protect the poor. This would preserve the access to electricity, such as it is, for essential needs, but would also encourage those who can afford to trim their electricity bills by investing in more efficient electricity appliances.

(Contd. by ysr - 2L)

SHRI N.K. SINGH (CONTD.): The modalities of applying this need to be worked out, given the concurrent jurisdiction over electricity policy and state dominance in setting electricity prices.

Fourth, increase taxes on lower-grade (higher emissions) fuel. This would also encourage the introduction of higher-grade fuels, which in turn opens up possibilities for increased use of existing cost-effective technologies to reduce emissions from mobile sources. India cannot currently take advantage of advances in automobile engine filters and emission-reducing parts since low-grade fuel damages these components.

The funds from these sources, cesses, also need to be supplemented by general budgetary support for "pulling" greener technologies and practices and for accelerating adaptation. Fortunately, this year, the Finance Minister's Budget had a whole chapter on what additional budgetary support the Government proposes to give which can supplement the garnering of resources from these special sources.

Overall, faster development is the best adaptation to climate change. We all know that includes investing in skills, knowledge, better infrastructure, etc., which can really alter the economy's present pattern. Funds can be further leveraged by ring-fencing and creating a non-lapsable fund of a corpus to enable borrowing against the future revenue stream from these special sources which I have proposed here.

I will give just two examples of such non-lapsable funds. One is the Central Road Fund. Another is the International Finance Facility. It enables Government and enables borrowers to hypothecate and borrow against future revenue stream to meet current expenditure. The fund should also have legal clearances to accept international funds. Setting up of this fund could help attract more external funds by providing funders with some assurance of the purposes for which monies would be used.

Sir, I now come to my second question. It is: How to spend the money? What is the best way in which this corpus, which is thus created, can be put to the most efficient use? In this context, I first propose setting up of a Public Sector Challenge Fund to support the additional costs of making current infrastructure more sustainable.

This initiative would allow Ministries and other bodies to apply for additional funding, resources additional to what the budget has allocated, to convert standard projects to state-of-the-art projects. It will be a kind of incentivising existing projects.

Additional fiscal resources are necessary for public infrastructure investment both for retrofitting -- most of them have been retrofitted, you know that -- and new ones, agriculture research and development and extension, health care (dealing with new disease vectors arising out of climate change), and protecting public goods such as ecosystem linked with conflict and social tensions connected with climate change.

With this structure, in which "additionality" is built into the application process, it may also be possible to garner revenues from carbon markets. As we know, the state of carbon markets is uncertain given pending revision in 2012, but it seems that any new regime will certainly continue these kinds of "above-and-beyond-business-as-usual" initiatives. This Fund, which I have proposed today, would play an important role in channeling these funds for projects in India.

This institutional design will help us leverage large infrastructure funds rather than just replace them, and the application process will ensure that the projects have 'owners' and are more likely to succeed.

Secondly, I propose a programme of Publicly Backed Guarantees (PBGs) to support research, development, and deployment of technologies or develop new ones in the energy, water supply, agricultural, forestry, and livestock. You will notice that I am requesting Publicly Backed Guarantees instead of subsidies. The advantage of Publicly Backed Guarantees is that they can be designed to keep the strength of market incentives and entrepreneurial insight while at the same time leveraging public funds to jumpstart the market. Basically, the public sector has to play an important role given the fact of risk of private investment. But we require synergy between both public and private efforts.

(Contd. by VKK/2M)

-YSR/VKK/2m/2.50

SHRI N.K. SINGH (CONTD.): There are, therefore, several kinds of initiatives from Publicly Backed Guarantees which are especially relevant. First, Publicly Backed Guarantees for asset finance to encourage financial institutions to lend to small

businesses for upgrading them to cleaner technology. Right now, access to finance is a barrier for many small businesses and their efforts to upgrade, and we want to remove this barrier because the significant impact for many of these small businesses could be large. The initiative could include public guarantees for loans for, say, auto conversion kits, technology upgrades for brick makers, bakers, laundries, etc. -- reducing emissions from the millions of high-emissions small industry sources and mobile sources.

Second is, Publicly Backed Guarantees for international technology transfer ventures. This fund that I am proposing could work with existing multilateral agencies and export finance agencies in countries with technologies relevant to India to create a floor on the risk of deploying and adapting a technology. A committee of technology, financial sector and governance experts should be formed to design an initial set of such mechanisms.

Sir, I also propose for the consideration of the Government the launch of something that I call an 'inducement prize' outlined in the National Action Plan on Climate Change. We need to be creative in supporting innovation for new energy sources and energy efficiency. One cutting-edge mechanism for funding innovation is inducement prizes. We all know that. It sets target specifications for technology, invites competitors to produce it and competes for a prize of Government-led scaling or Government contract. The National Programme on Improved Biomass Cookstoves, for example, is contemplating running an inducement prize for improved stoves as a public health measure which could have climate co-benefits by reducing black carbon and methane emissions.

I also propose to allocate a part of this proposed fund to be set aside for further inducement prizes. Sir, we must invest in creating monitoring and measurement infrastructure to effectively implement incentives for efficiency. Pricing policies that encourage efficient use of energy, water, agriculture and other natural resources, for example, will be essential for encouraging, adaptation, and, as a consequence, of course, mitigation. But, these require investments -- in better documenting hydrology for being able to assign and price water rights, in metering and redesign of electricity supply to ensure a politically sustainable shift to a new equilibrium of higher payment for better services, etc.

Building institutions for greenhouse gas accounting that enables more efficient and targeted policies to efficiently reduce carbon house gas emissions is imperative to deal with this challenge. In this way, the fund invests in its own future, in the institutional underpinnings for becoming more effective. Carbon taxes and the variants which I have described are generally seen as an easier and cheaper form of regulating greenhouse emissions than cap and trade mechanisms because of relative ease of implementation and monitoring. This is important in a developing country like India in which carbon house gas accounting process is still nascent, and it can be difficult to track both actions and outcomes.

However, Sir, market-based mechanisms like cap and trade are generally more effective at ensuring that mitigation is undertaken in the most cost-efficient way. Carbon tax is also vulnerable to political manipulation. It raises revenues from a source chosen by policy makers and to be given to a source chosen by

policy makers. There are, therefore, the opportunities for manipulation -- choosing what to tax, choosing how to spend and choosing on what to spend.

So, we need to build up the underpinnings for being able to credibly implement market-based mechanisms. This means strengthening the ability and incentives to measure and account for carbon gas emissions. This proposed Environment and Adaptation Mitigation Fund will, therefore, support the development of three important objectives. First is, development of emission factors customised to the Indian context, to improve accuracy of accounting and reporting following global standards. Second is, development of a common registry and reporting mechanisms to encourage companies that are already accounting to contribute this information to public databases. Third and the most important is, capacity building for greenhouse emission accounting.

(Contd. By TMV/2n)

-VKK-TMV-PSV/2N/2.55

SHRI N. K. SINGH (CONTD.): Sir, I also propose to set apart a portion of the Fund, once it is created, for supporting the ongoing efforts of the Ministry of Environment and Forests and the Pollution Control Boards to upgrade their environmental monitoring networks.

Overall, the Environment Adaptation and Mitigation Fund governance has to be built in potential for new mechanisms to be proposed over time.

I propose that the Fund to be overseen by a Board of Governors from public and private sectors, with a rotating membership, clear criteria for joining and a transparent selection process.

This will enable the Fund to be nimble as an incentive mechanism. It can add programmes as needed as science and technology evolves.

In conclusion, Sir, for the reasons which I mentioned, I beg to move this Resolution for the constitution of an Environment Adaptation and Mitigation Fund.

The key features of the Fund, in short, are that the funding sources include proceeds from targeted cesses that also create incentives to reduce emissions; general budgetary resources, which can then be leveraged through creative public finance; external resources flow related to global sustainability.

The initial Fund activities are designed to ensure the use of the Fund to activate public sector activity by offering funds to support moving beyond business as usual, activate private innovation through innovative public finance and build the institutional capacity to track outcomes and target incentives more effectively in future.

The Environment Adaptation and Mitigation Fund governance is designed to allow the Fund to evolve as a coordinating force over time, which is essential for a fast-changing and wide-ranging policy action.

This, Sir, is an inescapable necessity to finance the huge cost that individual and society will inevitably have to bear both for adaptation in short term and mitigation where outcomes inevitably have a long gestation period. In the absence of an innovative financing mechanism, mere reliance on traditional

sources is inadequate and unpredictable. Adaptation activities are necessary to enable an orderly transition to mitigate the adverse effects of climate change facing the communities and sectors and enable adaptive response. Mitigation, of course, involves a whole slew of measures affecting different facets of life and enabling gainful economic activity to continue while reducing carbon emission. I would urge the Government to accept this Resolution in the hope and belief that based on best international practices and given the enormous repercussions it has on the present and future generation we need to move away from business as usual and traditional approach.

Small boutique funds from incremental sources are well behind the compelling necessity curve. We need an integrated approach. I have given some ideas on the necessity, the sources of financing, the deployment of the resources, monitoring outcomes and the governance structure for the Fund.

Let us, Sir, make a reasonable beginning. I very much hope and expect that the Government would rise to the challenge, the challenge of our time, the compelling challenge in our face, and constitute an Environment Adaptation and Mitigation Fund for the reasons and objectives which I have outlined for the consideration of this House both today and in an intervention which I had an opportunity to make on an earlier occasion. Thank you.

(Ends)

THE VICE-CHAIMAN (SHRI KALRAJ MISHRA): Dr. T. Subbarami Reddy. He is not there. Shri E. M. Sudarsana Natchiappan.

DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (TAMIL NADU): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. I rise to speak on the Resolution moved by a very reputed former Revenue Secretary of Government of India and present Rajya Sabha Member, Shri N. K. Singh. After his presentation in the last session and also in this session, we can easily expect that he is going to come out with a very good literary work which can be followed by the developing and underdeveloped countries so that they can meet the requirements of the renewal energy and also learn how to promote research and technology development.

(Contd. by 2O/MKS)

MKS-DS/3.00/2O

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (CONTD.): At the same time, they can know how to mobilize the financial resources for meeting the situation. I hope, Mr. Singh is having the experience of being a Consultant in IMF also. Therefore, his suggestion, with all his experience, is very useful for us to meet the situation. Sir, I would like to suggest that the Indian situation is much different from the Vedic days. We are people who loved the nature, who lived with the nature and who never hurt the nature. Our life was like that. But it is only subsequently, when the other countries started to invade India and tried to change the culture of Indian people, that we started to deviate from our Hindu culture and, in the name of development, we sacrificed many things of the nature and also hurt the nature. Now, we are really suffering due to that. We have got polluted water; the mineral water, which was once a rich man's property, has now become a normal usage of the middle class people too. Even it has gone down to the level of villages where

you cannot get water other than the bottled water. Similarly, even our vegetables were, earlier, based on natural manures. With the propagation of pesticides and fertilisers, we started deviating from getting it from our own natural manures. We have started using fertilisers only. Today, we have reached a new situation that has compelled to go back to the old method of using the natural manures. We can go away from using the fertilisers. We have to create a balanced situation. That is why I feel that if we empower the local people in villages and urban areas too, they will know how to solve their own problem, but we are not giving them their own powers which were taken away from them. We are not ready to give constitutionally-accepted new powers to them. We want to show that as a carrot and stick policy; since you are getting a Panchayat Raj, you have got the rights to decide yourself; you will get it; you will get it, but wait for some time! Similarly, in urban areas, we are not following certain things which are happening in western countries where they have got their own accounting system of managing their resources and having the community discipline and other things. But even, here, we want to follow the colonial system of administration, rather than the management, or we want to allow the people to decide their own fate by their own democratic process. Sir, we are going on reducing the power of a common man; we are going on taking away their powers and the community powers in the name of development. Now, we have reached a situation from where nobody can save us from any natural catastrophe. Naturally, we are losing all our natural wealth, including the minerals. We are losing the forests; we are losing the environment; we are losing our health. Everybody, from an ordinary person to a rich man, is

spending more of his money not on food, but on the medicines. There used to be a situation where educational institutions used to come up very well. On health aspects, institutions used to come. Now, only the nursing homes and hospitals are coming. A huge industry of medicine is coming. A huge sum of money is stolen from the ordinary person's packet. Not only that; they are selling their own property to save themselves and their children from the environment catastrophe.

(Contd. by VK/2P)

VK/2P/3.05

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (CONTD): This is the situation. In such a situation, we have to think how much we can extract from our own natural resources; more so, we have also got renewable resources. I would like to concentrate on the solar energy. 'Surya Namaskaram' is the system of praying to the almighty by the Hindus. The Sun God is going to protect me the whole day; the Sun God is the super most power to my eyes, and, therefore, it is going to protect me, this is how every Indian starts his day. But are we utilizing the sun fully? Are we utilizing the solar power fully? There is the very wonderful UPA-II Government which has propagated the Jawaharlal Nehru Solar Mission. It is a very successful programme, which has been mooted. Sir, they started thinking about one megawatt or five megawatts, but they have not started working on whether a consumer can be made a producer. We should borrow ideas which are good. Mahakavi Bharathi used to say: wherever there is knowledge, you bring that here and utilize it for the welfare of the people. The Germans are utilizing it. They have done it in a big way. They have installed solar panels in every house.

The Government is subsidizing it. The energy produced in every house there is taken to the National Grid. Whatever energy is produced through solar panels in every house, that is taken to the National Grid every day. They are paid six times more than the normal price. At the same time, they can utilize that energy for their own purpose also. They are benefitted in two ways. Firstly, in this way, the consumer becomes the producer. That is what should be done in India. In India, people live in remote villages. For going from one village to another village, we need to travel a minimum of 25 kilometres. If we lay electricity wires from one village to another village, the transmission cost and the loss itself will come to more than 40 to 45 per cent. This is simply for putting up some lamps at certain places. That is not for providing electricity for 24 hours a day. The farmers are not able to plough their fields because there is no electricity. Electricity is available for only five to six hours. Our poor villagers are not getting that benefit. So the solar energy needs to be utilized properly. Even our own science and research institute at Jodhpur has developed a project. I have also seen a presentation made by a Government agency where it was shown that by putting up even a small panel, half-horse power to one-horse power, at places where wells are available, power can be generated and it can be utilized for 24 hours. Why shouldn't we make it fully subsidized for agriculturists and farmers? Instead of putting up electricity lines for taking electricity to villages and incurring a loss of 40 to 45 per cent in transmission cost itself, these power panels can be provided to them. If you produce panels in large number, it would cost you less. These panels can be prepared with the help of the private sector and the public sector

and then they can be distributed to every household. They can produce electricity by utilizing these panels. They can utilize it for the community and they can utilize it for the neighbourhood also. If we are able to do it, then the money that we are spending in the name of making available electricity to the ordinary citizen, that can be easily saved. Shri N.K. Singh, was talking about it theoretically. I have a very ordinary way of looking at the issue. We need to promote research. It is not that if you have good buildings and instruments then only you can promote research.

(Contd. By 2Q)

RG/3.10/2Q

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (contd.): Sir, we are also following the system of the Western countries, where you have to formulate things logically and data-wise. But poor villagers of our country are having a lot of research-oriented minds, and they are doing it. We are having our own Departments to develop these research minds at the village level, and we are also awarding them annually. But many of the research-minded people are not educated enough to suit the modern society. When I was a Member of the Standing Committee on Environment and Forests, I had the opportunity to visit many of the laboratories throughout India. We have to praise Pt. Jawaharlal Nehru; how visionary he was! He made a huge investment on these laboratories. But the Directors of these laboratories and scientists say that these laboratories are being utilized only for presentation of Papers in the Western countries and for getting better posts there, rather than serving the local people, whose tax money is set apart for these

laboratories in every Budget. I asked them: How many patents have they got registered in each and every laboratory when we are spending so much of money? They only say, it is only one or two. Otherwise, they say, "We are presenting Papers in the international fora. They are utilizing our services and getting awarded for themselves." We are not coming forward with more and more patents, when we are, otherwise, spending so much money on our centres. The time has come when they are made accountable. When we are giving them the Budget grant of Rs.20 crores every year, they have to at least earn Rs.25 crores by way of patent registration and from other proceeds. Otherwise, that grant has to be stopped, and the same can be utilized for betterment of the ordinary people. We are only spending more and more money of the Exchequer for betterment of research work in these laboratories. Instead we can encourage the private sector which is doing a good amount of research and capturing new markets because they are market-driven. They want to bring new research materials so that they can meet the growing needs. Even, the small cell phone, which was started as a tool to transmit voices, has now become a full-fledged internet-facilitated computer in the hands. It can transmit pictures immediately; it can transmit videos; it has got several other features which can be very easily passed on to other people. This was all done within a period of five years because of continuous research by the private sector. When Apple comes with a I-phone, then, Nokia starts its research and Siemens also start its research. They are competitive because they want to improve their market share. Therefore, Sir, we have to think about diverting our money to villages, to those people who are

getting the minimum of education, but who are research-minded. That research mind has to be tapped. The human potentiality, which is available in the remote parts of the country, is not at all tapped. The Chinese are tapping that energy in the fullest possible way. On the one hand, they are modernizing their country and, on the other hand, they are fully utilizing human resources in every aspect. That is why they are now becoming a super power. But the Americans could not tap that resource properly. Even for their military, they are borrowing from other countries. I recall having read in some news journal of the U.S. that they are spending huge sums of money for lobbying. Like, to make a rogue State an acceptable State, lobbying goes on with the Congress people and other legislators. For everything, they need lobbying. But here, we need a lobbying for making solar energy as a part of man's existence. Similarly, we have to see to it that fertilizer is replaced by manures. But then what will happen? Big industries, which are manufacturing fertilizers and pesticides, would lobby against it, and they will say that this is not the correct way to increase production.

Sir, I would also like to stress upon the developmental aspect. Here again, I would only have to argue on the basis of the potentiality of the people, who have only studied up to XII standard in their own vernacular languages, be it Tamil, Telugu or Malayalam.

(Continued by 2R)

DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (contd.): When they come to higher studies or professional courses, they have to pay huge amounts. In Tamil Nadu, during Shri Kamraj's period, it was made free. Subsequently, Dr. Kalaignar has also made it free up to the college level. In Andhra Pradesh, students are reimbursed the fees that they pay in professional colleges. This had been done by Shri Y. S. Reddy. Subsequently, Shri Rossaiah has also done it. So, if we want to have development, we should see to it that students in rural area are given free education, especially in research. They are so intelligent that they adapt themselves to every situation very easily. But we are not encouraging them to come up to that level. We are utilizing only their physical energy. We are utilizing them only for manual work. They keep going to countries in the Gulf, in Arab countries and in Europe, even to Malaysia and Singapore, mainly for manual work, but not for mental work. Now, of late, we have been seeing the phenomenon of USA and many European countries outsourcing their work to companies in India, companies in south India which are providing their services at very cheap rates. The young boys and girls who graduate from colleges are able to adapt themselves, just after a month's training, to various jobs including software development and so on. Such is the energy of the common man. That energy is now being tapped again. Previously, our professionals used to go to foreign countries. Now, people even at the Bachelor degree level are going abroad. They are going to foreign countries as very, very cheap labour wherein they are paid a minimum of 2000 dollars monthly; here, we give them just

Rs.2000. Even if they give Rs.20000, even then, there is a profit of Rs.25,000 per head. That is the situation in India. Therefore, we may not adopt their development model, but we have to have this type of a situation. Give power at the local level. Help them. Give more aid to them. Give them more guidance. Show the world how it is working. For example, we enacted one of the best laws for utilizing research and whatever patent or copyright is created at the village level, the community would share the profit. I would like to know how many villages are being benefited by that. At the international level, it has been one of the best laws enacted by this Parliament. But are we utilizing it? Do we have the time to see whether this particular provision is being properly utilized at the village level? How many community people were being benefited by taking away such natural herbs which were available. Our findings on herbs have been utilized by multi-national companies. They give them different names, different colours and then sell them back to us again. The same thing happened during the colonial rule of the British. They took away all our knowledge, our raw materials, put it in the *lanka charan* and brought it here to the same market and sold everything to the same Indians. Similar things are happening here. The Government should think that we must concentrate on the masses rather than the people who have already been lured by money to invest in foreign countries. We are very happy that huge amounts of money are being diverted from public sector undertakings in different names and our own people are purchasing many of the companies. Even today, I saw some US gas company was bought. We are very happy and proud that now Indian corporates are buying UK companies, European and American companies.

We are very proud of that. But, at the same time, are we doing the same thing for our own Indians? They are starving. They are going out of the country. There is an assessment that from Tamil Nadu alone, every year, ten lakh people are migrating to foreign countries in search of jobs.

(Contd. at 2s/kgg)

kgg-sc/2s/3.20

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (contd.): Such is the situation. How are we going to solve this problem? Therefore, when we talk about environment, it means we are talking about carbon accounting and everything else, which is the creation of the western knowledge, the creation of the western culture. No doubt we are benefited for some time; at the same time, we should not forget our own culture, our own nature which brought us to this level.

India is a very, very great country. It has got natural resources and human resources which can be utilised for hundreds of years if we get a proper leadership at the district-level and at the national level. I used to say that every Member of Parliament should feel proud to be in the highest position in India. People cannot even dream to be a Member and sitting here, which is one of the highest positions in India. We must constantly inquire whether we are doing our jobs as a Member of Lok Sabha or Rajya Sabha so that the same situations available in Mumbai or Delhi or Kolkata are created for our own villages. Are we planning like that? Are we bringing money in their hands? Are we showing a path to them? Some Ministers have occupied the seat of Lok Sabha Membership for fifteen years, twenty years. But, they have not done even a small thing in their constituencies.

Here is our Member, Shri Mani Shankar Aiyar. I can quote him. He is a man who has done a lot in his constituency. He was defeated in the recent Lok Sabha elections. But, he has done many things even sitting in the opposition or in the ruling benches. In whichever Ministry he was, he has done something in his constituency. That is the greatness about him.

Similarly, Sir, whatever programmes we are making at the national level should go to the people. We need not boast ourselves being very resourceful people at the international fora. But, finally, what is the national development we have attained? In which way are our resources utilised? Are they utilised properly? That is the question that we need to answer ourselves.

The Resolution aims to create a situation by which we can address the challenges. Though the modern terminology is used, 'environment adaptation and mitigation fund', I would like to suggest that we have got a huge money as sovereign fund. We are not utilizing it. Now, I am told that some funds may be utilised for the corporate needs and other needs. But, at the same time, Sir, I request that sovereign fund needs to be utilised to see to it that the villages are developed, the Gandhian dream or Rajiv Gandhi's dream comes true, they become self-sufficient villages, they really attain the Rama-Rajya, the real Swaraj or the Grama-Rajya where there would be researches in place, where the environment is looked after, where there would be comprehensive development, where the scientific knowledge is taught, where something new comes out. If we make the small units become vibrant, one day we would realise the entire India

developed. Then, internationally the world would project India as the super-power in every aspect.

(Ends)

श्री अनिल माधव दवे (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, Environment Adaptation and Mitigation Fund की जो बात आयी है और उसको खड़ा करने के लिए आज जिस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि उसे कैसे खड़ा करना है, कितना फंड करना है और उसे कैसे खर्च करना है, इन सब बातों पर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है क्योंकि सोर्स, रिसोर्सेज़ या फंड, हम जो कुछ भी कहें, उसका मिलना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उसको खर्च करने का तरीका है क्योंकि हम जानते हैं, हम कॉमन वेल्थ को देख रहे हैं, हम साठ साल से कश्मीर को पैकेज पर पैकेज दे रहे हैं, हम देश के सड़क निर्माण से लेकर बाकी सब संसाधनों के अंदर करोड़ों-अरबों नहीं, कितना ही पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन इन सब पैसों का कोई परिणाम नहीं निकला। यह केवल इसलिए है क्योंकि खर्च करने के तरीके के साथ हमने न्याय नहीं किया है।

(2टी-एमसीएम पर क्रमशः)

SC/MCM-TDB/2T/3-25

श्री अनिल माधव दवे (क्रमागत) : और यहां पर चूंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज फैशन हो गया है, एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हर कोई बात करना चाहता है, जबकि यह सर्वाधिक तकनीकी विषय है और इसके ऊपर जो चर्चा होनी चाहिए, जो गंभीरता होनी चाहिए, इसलिए यह जो विषय आज उठा है वह बहुत गंभीर है। उसके अंदर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस समय पूरा विश्व दो हिस्सों में बंटा हुआ है, एक विकासशील देश हैं और एक विकसित देश हैं। विकसित देशों का अपना एजेंडा है, उनकी अपनी एक जीवन पद्धति है, उनकी अपनी एक लाइफ स्टाइल है, वे अपने तरीके से जीना चाहते हैं, वे भोग करना चाहते हैं, वे पृथ्वी का तापमान बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा रहे हैं और वे हमसे कह रहे हैं

कि आप त्याग करते रहिए। ये जिन देशों को कह रहे हैं उनके अंदर डवलप्ड कन्ट्रीज हैं, डवलपिंग कन्ट्रीज हैं और छोटे-छोटे देश हैं और वे उनकी छोटी-छोटी गल्तियों को भी निकालते रहते हैं। इसलिए मैं यहां पर एक विषय को जरूर उठाना चाहता हूं। मुझे कहीं न कहीं कोपनहेगन में दीखा था कि गणना करने के तरीकों को भारत में विकसित करना होगा। वे अपने ढंग से आंकड़े लेते हैं, अपने ढंग से उसकी गणना करते हैं, अपने ढंग से वे एक आखिरी कांक्लुजन पर पहुंच जाते हैं और अपने ढंग से आखिर में वे एक धाराप्रवाह भाषण देते हुए हम पर चिपका देते हैं कि गाय के घास चबाने से कार्बन उत्सर्जन होता है, गाय के गोबर से कार्बन उत्सर्जन होता है। चूंकि हमारे पास कोई आर0एंड डी0 नहीं है इसलिए हम मान लेते हैं कि हां, होता है। जब वे हमसे कहते हैं कि यहां चूल्हा जलने से इतना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि हां हो रहा है, भारत के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा केवल भारत के साथ ही नहीं है, सारे विश्व के उन विकासशील देशों के साथ है। चूंकि हमारे पास गणना करने का कोई मकेनिज्म नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि भारत के अंदर इस पूरे कार्बन वर्ल्ड को समझने के लिए इसकी एक गणना करने की वैज्ञानिक पद्धति भारत में विकसित करनी चाहिए। विश्व को गणित हमने सिखाया। इसलिए अगर हम इस पूरी व्यवस्था के एक-एक पक्ष के ऊपर किस चीज से कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, किस चीज से आक्सिजन आ रहा है, किससे कितना मिल रहा है और किससे कितना नहीं मिल रहा है और ऐसा करते समय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अंदर कृपा करके जो सरकारी ढांचा है उसकी व्यवस्था में इनको न लगाया जाए। अगर हमें इसके अंदर लगाना है तो IIM, IFS और बाकी जो सारी संस्थाएं हैं -IIFM जितने भी संस्थान हैं, जो ऐसे संस्थान हैं, जिनमें उस विषय के अंदर ऊर्जावान नौजवान हैं उनको लगाएं और अगर उन्हें सही तरीका दिया तो वे निश्चित ही गणना कर सकेंगे। हम भारत में ऐसी व्यवस्था खड़ी करें कि जब हम 2010 के आखिर में मेक्सिको जाएं या आगे विश्व में अलग-अलग जगहों पर जाएं तो हम उनके आंकड़ों को काउंटर कर सकें और हम कह सकें कि आपकी गणना गलत है, सही गणना का तरीका

यह है, हमने कच्चे आंकड़ों का संग्रह यह किया, इसकी गणना इस पद्धति से की है, इस पद्धति से गणना करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि सारी पौलिसीज का जो बेसिक है वह बेसिक निष्कर्षों के ऊपर निकला हुआ है। आप देखिए, देखते ही देखते भारत को डम्पिंग यार्ड बना दिया गया। कहा जाता है कि आप हमारे यहां से कम्प्यूटर ले जाइए, क्योंकि आपके स्कूलों में कम्प्यूटर नहीं हैं। ऐसे कम्प्यूटर अब जिनकी एक साल, डेढ़ साल या दो साल की लाइफ बची है, जो आज से 20-30 साल पहले विकसित देशों के अंदर प्रयोग होते थे, वे सब हमारे यहां लाकर के रख दिए जाते हैं और देश के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अलग-अलग प्रकार से एन0जी0ओज0 और बाकी संस्थाएं जो योजनाएं चलाती और सारे कम्प्यूटर लग जाते हैं और अब मुश्किल से वहां बिजली नहीं पहुंच रही है तो वहां कम्प्यूटर क्या लगने वाला है। इस कारण वे सारे कम्प्यूटर कचरा घर बन जाते हैं, वे ठीक वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि भोपाल में मैं देखता हूं कि चाहे इजतिमा हो रहा हो या दुर्गा पूजा हो रही हो, करोड़ों की संख्या में लाखों कपड़े विदेशों से भारत आते हैं और बिक जाते हैं। भारत कपड़ों का डम्पिंग यार्ड बन रहा है, भारत ई-प्रोडक्ट का डम्पिंग यार्ड बन रहा है। डिस्मेंटल होने वाले सारे जहाज भारत के अंदर लाकर के डिस्मेंटल किए जाते हैं। मैं खुद जाकर के एक-दो डिस्मेंटलिंग याड्र्स को देख चुका हूं, लोग गाड़ियां ले-लेकर आते हैं, वे पुरानी टाइप की कुर्सियां, पुराने टाइप की गद्दियां, पुराने टाइप के वाश बेसिन जो-जो उस जहाज में से निकलते हैं, वे सब निकाल-निकाल कर ले जाते हैं और वे कहीं प्रयुक्त नहीं होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो बहुत गहरा दिमाग लगा करके डवलप्ड नेशन के लोग पौलिसी बनाते हैं, वे अपने इस प्रकार के सारे वेस्ट को भारत के अंदर डाल रहे हैं और केवल भारत में ही नहीं डाल रहे हैं,.....

(2U/gs पर क्रमशः)

श्री अनिल माधव दवे (क्रमागत) : हमारे अतिरिक्त सारे विकासशील देश जहां इसकी आवश्यकता हो सकती है, वे इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए हमको इससे बचना चाहिए। कहीं न कहीं हमें पॉलिसी और गणना के अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है, वरना हम धीरे-धीरे डम्पिंग यार्ड बनते जाएंगे और आज से पांच-सात साल बाद ये सारे लोग हमसे कहेंगे कि आप के यहां पर इतना waste है। हर दर्जे का मेडिकल waste आज शहरों के अतिरिक्त, नगरों के अतिरिक्त गांवों में विकसित होने लग गया है। वह केवल इसलिए हो रहा है कि हमने एक लाइन अडॉप्ट कर ली, हमको लगता है allopathy ही pathy है rest no pathy. हमको लगता ही नहीं है कि कोई होम्योपैथी होती है। हम हर एक को कहते हैं कि वह झोलाछाप डाक्टर है। अजीब तमाशा लगा रखा है। पांच सौ साल पहले ब्रुश करने की औकात नहीं थी, ठीक से तुम जीभ साफ नहीं कर रहे थे और हमको बोल रहे हो कि आयुर्वेदिक ठीक पैथी नहीं है, होम्योपैथी ठीक पैथी नहीं है, नेचुरोपैथी ठीक पैथी नहीं है, लेकिन ठीक है, । disagree यानी कोई यह कहता है कि एलोपैथी की आलोचना हो रही है। इमरजेंसी में एलोपैथी से अच्छी कोई पैथी नहीं है, कुछ मामलो में इसके अलावा कोई substitute नहीं है, लेकिन अजीब पागलपन है, सारे अस्पतालों से से waste निकल रहा है, उस waste को ठीक से सम्भालने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। उसी के कारण सारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं, सारे तालाब प्रदूषित हो रहे हैं, सारा अंडरग्राउड वाटर का रिर्सोस प्रभावित हो रहा है। ये सब पॉलिसी के अंदर परिवर्तन के कारण हो रहा है और जब तक हम पॉलिसी में परिवर्तन नहीं करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को भारत अकेला सम्भाल नहीं पाएगा । हमें इस पॉलिसी को सभी देशों के सामने लाना पड़ेगा, यानी हमें उनको अंतत्वोगत्वा समझाना पड़ेगा कि भैया हम जो मार्ग बता रहे हैं, यही रास्ता काम करने का है। होता यह है कि दो सौ, ढाई सौ साल हम लोग गुलाम रहे, तो हमें गोरी-गोरी चमड़ी और वैसी ही भाषा हमको इतना प्रभावित करती है कि हमको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं, ये सत्य बोल रहे हैं और यह जो तेलगु में बोल रहा है यह ठीक नहीं बोल रहा

है, यह जो असमिया में बोल रहा है यह ठीक नहीं बोल रहा है, यह जो हिन्दी में बोल रहा है यह ठीक नहीं बोल रहा है। भाषा के माध्यम से कंटेंट की गुणता नहीं बदलती है। कोई अपराध कर देने पर दुनिया की किसी भी भाषा में बोलिए, उससे अपराध का अर्थ नहीं बदलता। सत्य और अच्छी बात दुनिया की किसी भी भाषा में बोल देने से उसका अर्थ नहीं बदलता है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कितना असंवेदनशील विश्व का नेतृत्व करने वाला समाज है, उसका मैं एक ही उदाहरण आपके सामने देता हूं। कोपनहेगन के अंदर टुआलू से आए हुए वनवासी दर-दर भटक रहे थे, एक-एक काउंटर पर जाकर कह रहे थे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। टुआलू न्यूजीलेंड के ईस्ट में और फिलीपींस के साउथ में टापुओं का एक छोटा सा समूह है। वहां मुश्किल से तीन या साढ़े तीन हजार वनवासी रहते हैं। उनकी सोलह अक्षरों की भाषा है और वह चीख-चीख कर कह रहे थे कि भाई साहब 1.5 डिग्री टेम्परेचर अगर इस पृथ्वी का बढ़ेगा, तो हम इस पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण विस्थापित होने वाले पहला समाज हैं। लेकिन कोई उनको सुनने को तैयार नहीं था। लोग बिना बताए एक दूसरे के कमरे में घुस रहे हैं और बातचीत करने के लिए जा रहे हैं और वहां वे लोग चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि साहब हमको सुन लो, हमको सुन लो, लेकिन कोई उनको सुन नहीं रहा है। ऐसे असंवेदनशील लोग इकट्ठा होकर कह रहे हैं, अरे संवेदना होनी चाहिए। जो टापू 1.5 डिग्री पर डूब जाएगा, जिसके लोगों को विस्थापित करके कहीं और ले जाना पड़ेगा, उनकी संवेदना को न समझते हुए, लोग दो डिग्री टेम्परेचर के ऊपर समझौता कर रहे हैं। कोपनहेगन समझौता 2.0 डिग्री पर है। यह अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, लेकिन वह समझौता 1.5 पर नहीं है, वह समझौता 2.0 डिग्री पर है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को समझने का सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर भारत को लीड लेनी पड़ेगी। क्योंकि बाकी जो लीड लेने वाले देश हैं, वे असंवेदनशील हैं, वे आत्मकेन्द्रित हैं, उनको अपने अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। उनको दिन भर यही लगता है कि मेरे लिए खाने का हो जाए, मेरे लिए पहनने का हो जाए, मेरे लिए नहाने का हो जाए, उनकी वसुधैव कुटुम्बकम की कल्पना है ही

नहीं । उन्होंने जब आंख खोली और उनकी सिविलाइजेशन ने जब जन्म लिया, तो उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि देख भाई आडम्बर हौवा यह संसार जो है तेरे भोग के लिए बना है, तुम दोनों ऐश करो और अपने संसार में वृद्धि करो। यह बकरी तेरे खाने के लिए, यह पेड़ तेरे खाने के लिए, यह जंगल तेरे लिए हैं, ये नदियां तेरे लिए हैं, इन सब को तू उजाड़ दे, तेरे लिए सब कुछ है। हमने कहा,

'तेन त्यक्तेन भुंजीथा' लेकिन इसको जब तक आप भारत की गलियों में गायेंगे, तब तक इसका महत्व नहीं है।

(2W/asc पर जारी)

ASC-SSS/2W/3.35

श्री अनिल माधव दवे (क्रमागत) : शिकागो के धर्म सम्मेलन में एक संन्यासी खड़ा होकर जब दस मिनट का भाषण देता है, तो हजारों की संख्या में लोग उसके पीछे दोड़ने लगते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के लोगों को ही विश्व के रंगमंच पर ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन के सारे विषयों को लेकर नेतृत्व करना पड़ेगा और हमें उसमें अपनी बेसिक लाइन को नहीं छोड़ना है। अगर यह फंड खड़ा करने वाला विषय आता है, तो इसके अंदर भी मुझे लगता है कि इसमें दो-तीन चीजें मेरे विवेक से जोड़ी जानी चाहिएं, हम सारी चीजें जोड़ते हैं। हर प्रोडक्ट के साथ Pre and post environment cost जोड़ी जानी चाहिए। एक बार प्रोड्यूस करने के लिए आप कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, इस कार की manufacturing cost में नहीं जोड़ेंगे। आप कार के अंदर मेटल की cost जोड़ रहे हैं, labour जोड़ रहे हैं और इंवेस्टमेंट की बाकी सारी चीजें जोड़ रहे हैं, लेकिन environment cost नहीं जोड़ रहे हैं, pre-production environment cost किसी भी प्रोडक्ट के साथ। एक पेन को पैदा करने में कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, आपको लग रहा है कि तीस पैसे का हो रहा है, तो उसमें तीस पैसे जोड़ दीजिए। उसकी MRP के अंदर उसे आने दीजिए और उसकी post production cost भी जोड़ी जानी चाहिए। आपने एक कार बनाकर सड़क पर चला दी। वह

कार दस साल या बीस साल तक कार्बन उत्सर्जन कर रही है, वह कार्बन उत्सर्जन कैसे मिटिगेट होगा, कैसे उसका समझौता होगा, उसका कोई माध्यम नहीं है, कोई तरीका नहीं है। इसका यही तरीका है कि हमें उपभोग को कम करना है, क्योंकि पूरी civilization भोग वाली हो गई है, मैं कभी-कभी सोचता हूं कि हम कितने ज्यादा AC में रहने के आदी हो गए हैं और हमारी Non-AC life की कल्पना खत्म हो गई है। आज भारत का कितना ऐसा हिस्सा है, जो Non-AC में रहता है। अगर सारे विश्व के लोग AC में रहने लग जाएंगे, इतनी विद्युत पैदा करने के लिए अगर इतना कार्बन उत्सर्जन होने लग जाएगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है और दो डिग्री या दस डिग्री तक टेम्प्रेचर बढ़ जाएगा। क्योंकि वहां इस समय लीड करने वाला आदमी नहीं है, बल्कि एक गरीब आदमी है, एक पिछड़ा है, वनवासी है और वह झुग्गी बस्ती में रह रहा है तथा वह अपनी बात को कह नहीं सकता है, बस इतनी सी बात है। अगर हमारे यहां रात को लाइट चली जाए और AC बंद हो जाए, तो दूसरे दिन ही हल्ला मच जाता है। वह इसलिए हो रहा है। सब मामलों में Pre and post production cost जोड़ी जानी चाहिए, चाहे environment cost कहिए या चाहे जिस किसी cost base पर हो। यह फंड कलैक्शन का एक बहुत ही नायाब तरीका हो सकता है, क्योंकि ऐसा करके हम consumerism को कम कर सकते हैं, उपभोक्ताओं को अपने आप कष्ट होगा। जैसे tobacco का consumption है, cigarettes की consumption है, आप इसकी cost बढ़ाकर consumption कम करिए। हमें कोई चिंता नही है, जिनको पीना है, पीजिए। यदि पांच रुपए की cigartte 12 रुपए में मिलती है, फिर भी पीजिए, एटोमेटिकली वह धीरे-धीरे कम होने लगती है। मेरे कहने का तत्पर्य यह है कि इसमें कहीं न कहीं Pre and post production cost जोड़ी जानी चाहिए।

मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि जैसे हम फाइनैंस के अंदर balance sheet बनाते हैं, वैसे ही environment की भी balance sheet बननी चाहिए। यह हर व्यवस्था, व्यक्ति, संस्था, प्रथा हर एक का बताते हैं कि एक आफिस है, यह स्ट्रक्चर है, यह 12 मंजिला भवन है। इसकी balance sheet क्यों नहीं बननी चाहिए? इसके अंदर जो power consumption हो रहा है

और power consumption को प्रोड्यूस करने के लिए जितना मुझे कार्बन उत्सर्जन करना पड़ रहा है, मैं उस काबर्न उत्सर्जन को उसके अंदर जोड़ दूं, तो अंततोगत्वा यह मालूम पड़ेगा कि इस बिल्डिंग की, इस साल की environment balance sheet क्या है। अगर मान लीजिए मैंने उस बिल्डिंग के ऑनर होने के नाते अंदर consumerism किया है और कहीं पर जाकर दो हजार पेड़ लगाए हैं, तो मैं उसको compensate करूंगा, अपने उससे उसको बैलेंस करूंगा। मैं इसके अंदर corbon trading के विपरीत हूं। corbon trading एक महापाप जैसा काम है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं पाप करूंगा, आप पुण्य करिए। साल के आखिर में, मैं अपने पाप आपके पुण्य से खरीद लूंगा और दोनों मिल जाएंगे। आज विकसित और विकासशील देशों के अंदर एक हौवा खड़ा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे ले लो। अरे भाई, आप समझ नहीं रहे हैं कि विकसित देश आपको corbon trading के नाम पर अपने यहां का सारा कचरा भेज रहे हैं। वे आप से कह रहे हैं कि आप पेड़ लगाओ। अरे, तुम क्यों नहीं पेड़ लगाते, तुम्हें क्या हो गया है, G-7 nations तुम करो इस काम को। कल यहां पर जो स्वाभिमान से सशक्त, सम्पन्न बात चल रही थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हम जिस ढंग से foreign delegation से बात करते हैं, तो ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अभी गिरने वाले हैं। अरे भाई, ऐसा क्या आसमान उलट गया है। आखिर China प्रमुख चौराहे के ऊपर टैंक चला लेता है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा शासक उससे बात करने जाता है। ताकत के सामने दुनिया झुकती है।

(क्रमशः 2X/LP पर)

LP/2X/3.40

श्री अनिल माधव दवे (क्रमागत) : ताकतवर हो जाएंगे, तो सब कुछ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमें ई-बैलेंस शीट बनानी चाहिए। ई-प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट हर व्यवस्था में खड़ा होना चाहिए, हर संस्था में होना चाहिए, चाहे वह सोशल संस्था हो, चाहे नॉन प्रोफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रोफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वह पावर

कंजप्शन कर रहा है, अगर वह कहीं पर पॉल्युशन खड़ा कर रहा है, एक्सेप्ट ह्यूमन बींग, मनुष्य है, उसको मत काउंट कीजिए, क्योंकि वह अनिवार्य है, वह जानवर है, आप उसको कैसे काउंट करेंगे, लेकिन अपने लाइफ स्टाइल के कारण यदि उसके अंदर पावर कंजप्शन हो रहा है, अगर कहीं पर लाइफ स्टाइल के कारण कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे उसकी बैलेंस शीट बनाने की एक व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए। एकाउंटिंग नहीं होने से ही यह झंझट है। पूरी व्यवस्था के अंदर हिसाब ही नहीं है कि फाइल चल क्यों नहीं रही है। जो देखो वह यही कारण बताता रहता है कि फलाने सेक्रेट्री ने उसको लिख दिया, उसने उसको लिख दिया, उसने उसको लिख दिया। 63 साल हो गए हैं, अगर इस देश के अंदर स्कूल नहीं हैं, तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? व्यवस्था ठीक नहीं है तो कौन जवाबदेह है? अगर स्वर्ण चतुर्भुज नहीं बनता है और ईस्ट-वेस्ट, नॉर्थ-वेस्ट कॉरीडोर और गांव की सड़कें ठीक नही होती हैं, तो मुझे बताइए कि पचास साल के अंदर टोटल वियर एंड टियर कितना है? पचास साल के अंदर अनावश्यक फ्यूल जला-जलाकर आपने टोटल कितना कार्बन उत्सर्जन कर दिया? यह केवल इसलिए कर दिया, क्योंकि उस विषय के अंदर हमारी पॉलीसीज गलत थीं। यदि हर मामले में बैलेंस शीट बनेगी तो हम बहुत जल्दी किसी चीज को चैक कर लेंगे। हर साल के अंत में ही चैक कर लेंगे कि देखिए, आपका कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है, अब आप प्रोफिट पैदा करने के लिए कुछ न कुछ कीजिए। मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ करने की जरूरत है। इसी के आधार पर ई-टैक्स और ई-बोनस भी लगाना चाहिए। ई-टैक्स और ई-बोनस अंततोगत्वा कभी न कभी हमारी टैक्सेशन प्रणाली का हिस्सा बनेगा। आज नहीं बनेगा, दो साल बाद बनेगा, चार साल बाद बनेगा, लेकिन ई-टैक्स जरूर लगना चाहिए, क्योंकि जब तक हम टैक्स को महत्वपूर्ण नहीं बनाएंगे, तब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगी। अंत में इतना ही कहता हूं कि अगर इस ग्लोबल वार्मिंग का कोई आन्सर है, अगर इस कार्बन उत्सर्जन से विश्व लड़ रहा है और इसका कोई अंतिम उत्तर है और किसी एक के पास है, वह यह है कि यदि किसी को आपत्ति हो कि मुझे वैदिक वे कहने

में आपत्ति है, तो मैं कह दूंगा कि हिंदू वे कह दो, वह कहेगा कि हिंदू वे कहने में आपत्ति है, सांप्रदायिक है, तो मैं कह दूंगा कि गांधियन वे कह दो, वह कहेगा कि मुझे गांधियन वे कहने में आपत्ति है, तो मैं कहूंगा भैया, लोहिया वे कह दो, वह कहेगा इसमें भी आपत्ति है, तो मैं कहूंगा कि दीनदयाल वे कह दो, वह कहेगा कि नहीं, मैं इसको तिलक वे कहूंगा, तो मैं कहूंगा कि आप यह कह दो, कोई भी नाम दे दो, इस देश की जो वे ऑफ लाइफ है, वही इस विश्व को कार्बन उत्सर्जन से बचा सकती है। हमने कहा है, *तेन त्यक्तेन भुंजिथा,* विश्व के अंदर हम हैं, जो कहते हैं ऊँ द्यौः शांति, अंतरिक्ष शांति। ऐसा कौन कहता है? भारत का सिपाही कारगिल में लड़ता है तो उसका हृदय और उसकी जांघ काटने में लोगों को मजा आता है। यह सिविलाइजेशन है और हम कह रहे हैं ऊँ द्यौ शांति, अंतरिक्षं शांति, वनस्पतयः शांति। यह सिविलाइजेशन है। यह सिविलाइजेशन आगे जाकर इस देश को नहीं, विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकती है। इसलिए हमें इसको विकसित करना पड़ेगा और विश्व के धरातल पर जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा कि This is the right way, follow this. आप विश्व के रंगमंच पर लीडर के रूप में कहिए, रिरियाते और मिमियाते हुए मत कहिए। हम सोना बेच रहे हैं, धूल नहीं बेच रहे हैं। जब सोना बेच रहे हैं, तो हम टाइम टैस्टिड सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। दूसरे सिविलाइजेशन को अभी पांच सौ, सात सौ, हजार, दो हजार साल से ज्यादा नहीं हुए हैं। हम टाइम टैस्टिड सिविलाइजेशन हैं। हम कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं, वह सही है, हम इसके अंदर करेंगे। हमें छोटी-छोटी चीजों को उठाना चाहिए, बहुत बड़ी बातों का महत्व नहीं है। जैसे जब मैं कॉलेजों के अंदर जाता हूं तो छात्रों से कहता हूं कि आप एक साल तक जींस पर प्रैस मत करो। क्या आप बिना प्रैस किया हुआ जींस पहन सकते हो? यूं भी जींस पर प्रैस नहीं करनी पड़ती है। एक कॉलेज की छात्रा पूछती है कि इससे क्या होगा? मैंने कहा कि इससे यह होगा कि अगर तुम एक साल तक जींस पर प्रैस किये बिना पहनोगे, ऐसे ही अच्छे से नीटली सुखा दोगे या मां से कहोगे की ठीक से सुखा दीजिए, तो अठारह किलो कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। एक व्यक्ति के रूप में तो तुम इतना कर ही सकते हो। मेरे हिसाब से

इस देश के अंदर जो अठारह किलो कार्बन उत्सर्जन होना है, वह नहीं होगा। इसके लिए हर आदमी को कंट्रीब्यूट करना होगा। यह गोवर्द्धन का पर्वत है। कृष्ण की छोटी उंगली लगी थी, लेकिन इसमें सारे लोगों की ताकत लगेगी, वरना वही होगा, जो भारत के साथ हो रहा है कि जो करेगी, सरकार करेगी, सड़क सरकार बनाएगी, कश्मीर में शांति सरकार लाएगी, दुनिया में सारी झंझटों का निबटारा सरकार करेगी, देश की सीमाएं सरकार सुरिक्षत रखेगी और हम क्या करेंगे? हमारी मुंह पर कपड़ा बांधते हुए फोटो छपेगी।

(AKG/2Y पर जारी)

AKG/2Y/3.45

श्री अनिल माधव दवे (क्रमागत) : जब गाजा पट्टी के अन्दर फोटो छपते थे, तो मैं कहता था कि मत छापो, इसका spread effect होने वाला है। कालान्तर में spread effect देखने को मिल रहा है। कश्मीर में और कश्मीर के बाद हिन्दुस्तान के कोने-कोने में देखने को मिलेगा। यह spread effect होता है, अच्छी बातों का भी होता है और बुरी बातों का भी होता है। गाँधी जी गलत नहीं थे। गाँधी जी खाने-पीने, रहने-जीने की जो life बताते थे, वे गलत नहीं कहते थे। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अगर हम इन सब बातों के ऊपर ध्यान देंगे और इन सब बातों को आगे ले जाएँगे, तो मुझे लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हम जो फंड develop करने जा रहे हैं, हम उसको खड़ा भी कर पाएँगे और उसे खड़ा करके ठीक से utilize कर पाएँगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री ब्रजेश पाठक (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। आज सदन में बहुत गम्भीर विषय पर, जो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है, हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे विद्वान साथी, जो अर्थशास्त्री रहे हैं, धीरे-धीरे उनका दूसरा रूप भी पर्यावरणविद् के रूप में सामने आ रहा है। ऐसे साथी, श्री एन.के. सिंह जी, को भी हम इस

सदन में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। ... (व्यवधान) ... जयराम रमेश साहब तो इस समय लीडर हैं ही। सभी लोग इनसे खुश हैं, इनके साथी, जो बाईं तरफ बेंचों पर बैठते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : दोनों पर्यावरणविद् हैं।

श्री ब्रजेश पाठक : आज मैं "पर्यावरण अनुकूलन एवं राहत कोष (EAMF)" के बारे में बोलने के लिए खड़ा हूँ। कार्बन उत्सर्जन से भारत सहित पूरी दुनिया में पर्यावरण के लिए जो चुनौती उत्पन्न हुई है, उसके लिए इसके द्वारा एक ऐसी निधि की व्यवस्था करना है, जिससे हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकें और मानव जीवन एवं मानव सभ्यता को सुरक्षित रख सकें। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में कार्बन उत्सर्जन के बारे में, पर्यावरण से छेड़छाड़ के बारे में ज्यादा न बात कहते हुए, क्योंकि हमारे साथी इस पर बहुत कुछ कह चुके हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मानव सभ्यता ने जैसे-जैसे विकास किया, जैसे-जैसे विज्ञान के चमत्कार हमारे बीच आए, हमने प्रकृति से छेड़छाड़ करना शुरू किया। मौसम को उलटने के लिए हमने मशीनें बना डालीं। आज कितनी भी गर्मी हो, अगर 48 डिग्री temperature हो, तो भी भइया कम्बल ओढ़ते हैं। कुदरत ने, भगवान ने, प्राकृतिक व्यवस्था ने जाड़ा, गर्मी और बरसात बनाए, लेकिन हमने उनको उलटने का काम किया। धीरे-धीरे इसका प्रचलन इतना अधिक हुआ कि गर्मी है, तो ठंड होगी और ठंड है, तो हीटर चलेगा, तो हमारा कमरा गर्म रहेगा। उसका परिणाम यह हुआ कि प्राकृतिक व्यवस्थाएँ छिन्न-भिन्न होने लगीं। चूँकि भारत विकासशील देश है, हमने इस ओर सोचना शुरू किया। लेकिन हमारे सोचने के साथ ही वे देश, जो पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी चला रहे हैं, जो पूरी दुनिया में स्थापित हो चुके हैं, जो पूरी दुनिया में अपने को साबित कर चुके हैं कि सबसे बड़े संत वे ही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का सम्मेलन बुला कर यह साबित करना शुरू किया कि जो लोग पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं, वे लोग उसमें अपनी हिस्सेदारी दें और बराबर-बराबर का खर्च हो। हमने अखबारों में पढ़ा, प्रायः निकलता रहता है कि दूसरी दुनिया के देश, जिनके पास क्षमताएँ अधिक हैं, वे छोटे देशों के ऊपर, विकासशील देशों के ऊपर यह दबाव बनाते हैं कि आप पर उतनी ही जिम्मेदारी है,

जितनी हमारी है। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ में आता है, भारत को इस बात को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में दमदार तरीके से रखना चाहिए कि भारत चुनौतियों से निबटने के लिए तैयार रहा है और इस मुद्दे पर भी हमेशा तैयार रहेगा। हमारे साथी, दवे साहब अभी बता रहे थे कि भारत में जो भी उत्पादन की जाने वाली वस्तुएँ हैं, जो कार्बन उत्सर्जन करती हैं, उन पर हम कोई ऐसा टैक्स लगाएँ कि उनके प्रयोग के बाद टैक्स न लेना पड़े। उत्पादन के साथ ही, क्रय करने के साथ ही, हम उन पर permanent रूप से कोई ऐसा टैक्स लगा दें कि जो जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा, उसी मात्रा में उसे कर अदायगी करनी पड़ेगी।

(2जेड/एससीएच पर जारी)

SCH/3.50/2Z

श्री ब्रजेश पाठक (क्रमागत): और हम एक ऐसे फंड का निर्माण करें, ऐसे कर ढांचे का निर्माण करें कि आने वाले चुनौतियों से निपट सकें और अपने पर्यावरण को अपनी प्रकृति को बचा सकें। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा, जब भी विश्व में ऐसे सम्मेलन आयोजित होते हैं, तो भारत को अपनी बात मज़बूती से रखनी चाहिए कि हम तो पर्यावरण से लड़ने के लिए तैयार हैं, आप बताइए, सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन तो आपने ही किया है, आपने ही सबसे ज्यादा प्रकृति के साथ छेड़-छाड़ की है, प्रकृतिक व्यवस्थाओं को सबसे ज्यादा आपने ही तोड़ा-मरोड़ा है, तो आप हमें कितना टैक्स देने जा रहे हैं? अगर आप योगदान करोगे तो भारत योगदान में किसी भी कदम पर आपसे पीछे नहीं रहेगा।

ज्यादा वक्त न लेते हुए, मैं एक ऐसे बिल का समर्थन करना चाहूंगा, जो वास्तव में पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मानवता के लिए लाया गया है। मैं एक ऐसे बिल का समर्थन करता हूं और श्री एन.के. सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वह एक ऐसे प्रस्ताव को लेकर आए हैं, जो पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन चुका है। जय हिन्द, जय भारत। (समाप्त)

श्री समन पाठक (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य जो रैज़ोल्यूशन लेकर आए हैं, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। मेरे माननीय पूर्ववक्ता ने विस्तार से सभी बातें बताई हैं कि एक ऐसा सैंट्रल फंडिंग सिस्टम हो, जिसके तहत हम लोग पर्यावरण से सही ढंग से निपट सकें। यह जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। प्रस्तावक ने अपना रैज़ोल्यूशन रखते वक्त जो भी बात कही है, वह बिल्कुल सही है कि आज की परिस्थिति में पर्यावरण की समस्या बहुत गंभीर रूप धारण कर रही है। दुनिया के कई विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज़ बाकी देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार ग्रीन हाउस गैस का आज के पर्यावरण के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, मुख्य रूप से इसकी जिम्मेवार डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। आज अगर हम ग्रीन हाउस गैस के आंकड़ों को देखें तो हम लोग ग्रीन हाउस गैस का जितना उत्पादन करते हैं, वह मिनिमम है। जो देश ग्रीन हाउस गैस का ज्यादातर उत्पादन कर रहे हैं, और जिसके कारण आज पूरी पृथ्वी को संकटमय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, वही देश दूसरे देशों को मैंडेट कर रहे हैं कि आप अपने पर्यावरण में अमुक-अमुक सुधार करें। पर्यावरण के विषय पर जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, वही देश इस बात पर सबसे अधिक प्रेशर डालते हैं, जो स्वयं इसके लिए जिम्मेवार है। जिन डेवल्प्ड कंट्रीज़ के कारण दुनिया भयावह परिस्थिति की ओर जा रही है, वही रेज़ोल्यूशन लाकर बोलते हैं कि तुम यह करो, वह करो। लेकिन दु:ख की बात यह है कि हम भी अपनी सार्वभौमिकता को तिलांजलि देकर उनके एजेंडा को मान लेते हैं और उस पर साइन करके आ जाते हैं कि ठीक है, हम अमुक को 2% से अधिक नहीं बढ़ाएंगे अथवा यह करेंगे, वह करेंगे। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

PSV/3A पर जारी

श्री समन पाठक (क्रमागत): माननीय पाठक जी सही कह रहे थे कि आज दुनिया के सामने हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे भारत में जो हरियाली है, पर्यावरण को किस तरह से बचाना है, हम लोग परम्परा से ही इसका रख-रखाव करते आ रहे हैं। हम लोग हमेशा ही पर्यावरण सम्बन्धी जो भी विषय हैं, उसमें यह हरियाली है, नदी-नाले आदि हैं, इन सब के साथ भारतवर्ष की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ का जो ट्रेडिशन है और यहाँ का जो कल्चर है, ये सब हम लोगों के नेचर से मिले-जुले हैं। अपने नेचर के साथ मिलकर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसलिए यदि आज पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा गम्भीर है, सबसे ज्यादा कंसर्न्ड है तो हमारा देश है। इसलिए हमें विश्व के दूसरे देशों को बताना चाहिए कि इस पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए, वे आज हमारे एजेंडे पर बात करें। कोई भी इंटरनेशनल सेमिनार में हम किसी के, यू0एस0 के या किसी अन्य डेवलप्ड कंट्री के, एजेंडे पर हम बात क्यों करें, हम अपने एजेंडे पर बोलेंगे कि आप हमसे सीखो, हमारे देश से यह सीखें कि इसमें क्या करना है और पर्यावरण को कैसे बचाना है।

सर, माननीय सदस्य जो रिजोल्यूशन लाये हैं, उसमें इस वक्त यह सबसे सही होगा। आगे पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमारा अपना एक फंडिंग सिस्टम का जो उन्होंने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि सरकार को इसे मान लेना चाहिए। आने वाले दिनों में इस रिजोल्यूशन को, हालाँकि आज यह एक व्यक्तिगत या प्राइवेट रिजोल्यूशन है, सरकारी रिजोल्यूशन के हिसाब से मान लिया जाए। मैं इसका पुरजोर समर्थन करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

(समाप्त)

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): श्री आर0सी0 सिंह।... उपस्थित नहीं हैं। श्री राजनीति प्रसाद।

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): महोदय, सबसे पहले तो मैं श्री एन0के0 सिंह जी को, जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे और अभी हमारे यहाँ सदस्य हैं, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत गम्भीर रिजोल्यूशन यहाँ दिया है। Apart from other considerations, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

सर, यह पर्यावरण का जो विषय है वह आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस जगह में जी रहे हैं, अगर वहाँ का पर्यावरण स्वच्छ नहीं है तो वह आदमी के अन्दर डिजीज़ पैदा करता है, बीमारियाँ पैदा कर देता है। वह ऐसी बीमारियाँ पैदा करता है कि फिर उसका कोई उपाय नहीं निकलता है, इसलिए पर्यावरण के लिए हम लोगों को अलग से कुछ करना चाहिए। जैसा श्री एन0के0 सिंह जी ने कहा, सर, गाँवों में आप जाकर देखिए। हमारा देश गाँवों का देश है, यह शहरों का देश ज्यादा नहीं है। वहाँ लोग मॉर्निंग में शौच के लिए बाहर जाते हैं। एक बार हम कहीं दौरे पर गए थे, तो वहाँ हमें एक वैज्ञानिक मिले। उन्होंने कहा कि अगर किसी गाँव में एक आदमी भी खुले में शौच करता है तो वहाँ का पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। आप कोई ऐसा गाँव बताइए जहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अभी जैसा इन्होंने कहा कि इसके बारे में गाँवों में पंचायत लेवल पर हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए उनको भी कुछ अधिकार देना चाहिए, उनको भी फंडिंग देनी चाहिए, ताकि अगर कहीं शौचालय बनना है तो वे वहाँ शौचालय बनाएँ, लोग खुले में शौच नहीं करें। इसके बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। वहाँ यह एक समस्या है। उन्होंने कहा था कि अगर एक भी गाँव में एक भी जगह पर इस तरह से खुले में शौच होता है, तो उससे पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है।

(3बी/डी0एस0 पर क्रमशः)

-PSV/DS-KSK/4.00/3b

श्री राजनीति प्रसाद (क्रमागत): तो क्या हम 63 सालों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाये? आज भी गांवों में हमारी जो माताएँ और बहनें हैं या हमारे जो लोग हैं, वे पर्यावरण का क्या

ख्याल करते हैं? रमेश जी वहाँ चले गये और वहाँ क्या-क्या करके आ गये, लेकिन हिन्दुस्तान में पर्यावरण की जो समस्या है, उसके बारे में इन्होंने क्या किया? हिन्दुस्तान में आप कर सकते हैं। आप एक दिन में कानून बना सकते हैं। गांवों में महिलाओं, बुजुर्गों और लोगों के लिए आप पर्यावरण का निर्देश कर सकते हैं। आपने किया, लेकिन करने के बाद क्या हुआ? आपने जो पैसा शौचालय बनाने के लिए भेजा, वह शौचालय बनाने में यूज़ नहीं हुआ। अगर बनाया भी गया तो घटिया तरीके का बना दिया गया। अगर बनाया भी तो उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ।

सर, मैं एक दौरे पर गया था। मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि बिहार में एक जगह है, लखीसराय, आपने नाम सुना होगा। मैं जब वहाँ मीटिंग कर रहा था तो लोगों ने कहा कि बगल में किउल नदी बहती है। उन्होंने कहा कि वह बहुत बढ़िया नदी है, लेकिन 50 वर्षों से हमें मीठा पानी नहीं मिला है। यानी, चापाकल से भी मीठा पानी नहीं आता है। यह क्या होगा? हम लोगों को तो मिनरल वॉटर पीने की आदत हो गयी है। यहाँ भी हम लोग मिनरल वॉटर पीते हैं और ट्रेन में भी मिनरल वॉटर ही पीते हैं। पहले ट्रेनों में "पानी पाँड़े" होते थे, जो बाल्टी में पानी लाकर पिलाते थे। वे कहते थे, "लीजिए, पानी पीजो, पानी पीजो।" अब तो कोई भी मिनरल वॉटर 10-12 रुपये से कम में मिलता ही नहीं है। जो मिनरल वॉटर होता है, उसमें तो कोई जाता ही नहीं है। सर, समस्या यह है कि पहले तो जंगल को उखाड़ो और उसके बाद जंगल लगाओ। सारे जंगल उखड़ गए, खत्म हो गए। ये जंगल उखड़ जाते हैं और लगते हैं, तो पर्यावरण की यह एक समस्या है। मैंने जो बात कही है, वह remote village में जाकर कहा है। इसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो पर्यावरण को आप चाहे कितना भी खूबसूरत बना लें, आप चाहे कितना भी फंडिंग कर लें, लेकिन अगर यह समस्या नहीं सुधरेगी तो हमारे ख्याल से बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए पर्यावरण की जो समस्या है और इसके लिए एन.के. सिंह साहब ने जो बिल लाया है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा

इंतजाम किया जाए जिससे लोगों को राहत मिले और फिर हम लोग पर्यावरण के लिए आगे अच्छा सोच सकें। धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (NOMINATED): Sir, I rise to broadly endorse the approach indicated in the Resolution moved by my own college friend and present Rajya Sabha companion, Shri N.K. Singh. But, as it has been indicated by earlier speakers, we will be able to operationalise such a resolution only if the Government were to accept it in principle and convert it into a Government resolution. I am a bit concerned as to whether the concerns of the present Government, the immediately preceding one, totally match the requirement of what needs to be done to operationalise the broad approach indicated by Shri N.K. Singh. We are very fortunate that at this moment, we have with us here in the House two key Ministers who have been concerned with this issue - one, the former Minister of Science and Technology who was responsible for the National Policy on Climate Change, and second, the present Minister for Environment and Forests. Sir, it is only if we are able to bring the proposals made by Shri N.K. Singh within the framework of the National Policy on Climate Change and adapt that policy in accordance with the realities of our country, plus ensure that the endeavours of present Minister of Environment and Forests to access the third source of funds, that was mentioned by Shri N.K. Singh, namely, external financing, meet the requirements of our country, that the intentions that are expressed in this Resolution will be translated into effective action on the ground.

(continued by 3c - gsp)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (CONTD.): And, on both these considerations, I think, a great deal more needs to be done. First and the foremost, Sir, the National Policy on Climate Change does not give adequate space for the point that was being stressed by Shri Sudarsana Natchiappan that there is not an adequate involvement of local communities in ensuring that action is taken in communities, in villages, at the grassroots to combat (a) climate change itself, and, (b) the consequences of climate change. This inadequate attention to the delivery mechanism for any fund including the fund proposed by Shri Nand Kishore Singh is really at the root of all the problems that our country faces.

To illustrate how serious is this issue, may I draw the attention of the House to the fact that in 1994, when the total Central Government outlays on social sector and anti-poverty programmes was no more than Rs. 7,600 crore, India's position on the UN Human Development Index was 134. Over the next 15 years, at least, in nominal terms, the Central Government outlays on social sector and poverty alleviation programmes rose by a factor of 15, and, is today of the order of Rs. 1,35,000 crore compared to Rs. 7,600 crore just fifteen or sixteen years ago, and, yet, what is India's position on the UN Human Development Index. Tragically, exactly the same what it was fifteen years ago, it is 134. And, indeed the immediate consequence of economic reforms resulting in larger Government revenues, and, therefore, larger outlays on social sector and anti-poverty programmes, was that in 1977, we actually sank from position 134 to position 138. So, in these circumstances, it is abundantly clear to me, as it should be to the

House and to the country, and, it should be the central concern of our nation, that outcomes bear no relationship whatsoever to outlays, and, that is simply because we continue to be governed by a totally colonial mentality, which believes that the service to which Shri N.K. Singh belonged, the Indian Administrative Service, and, the one to which I too belonged, that is, the Indian Foreign Service, that these are models for the delivery of development. They are simply not. They were inventions of the colonial authority for collecting revenue and maintaining law and order, not for the delivery of development. Although at the start of Independence, we believed that we can adapt that steel frame to be able to deliver the development, the ugly truth is that the steel frame is rusted. It has proved itself to be an iron frame, totally incapable of doing the job of development, and, therefore, the only way of delivering any kind of development, including the fund that is referred to in this Resolution, would be to shift away from bureaucratic delivery mechanisms to relying entirely on communities, which are empowered with functions, finances and functionaries to do the job for themselves.

The present National Policy on Climate Change vaguely acknowledges that this might be so but is not adequately elaborated in this regard. And, the excuse always made is -- and, I stress that it is an excuse because I have heard that excuse again this morning during the Question Hour -- that Panchayati Raj is the responsibility of States; so beyond reminding them that there is a Constitutional obligation, there is nothing further that we can do.

(Contd. by SK-3D)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (CONTD.): I don't accept this at all, for one, all Centrally-sponsored schemes, including the guidelines that will be drawn up when Shri N.K. Singh's proposal becomes a reality, are going to be drawn up by the Central Government. And, why, if we can impose a series of guidelines on the States, can we not also ensure the centrality of the local bodies, which are elected for the implementation of these programmes? In any case, as against a few hundred civil servants, we have 32 lakh elected representatives in all these local bodies. If only we empower them, if only we ensure that moneys being sent from this fund proposed by Shri N.K. Singh or any other fund were to directly or indirectly reach the treasury accounts and the bank accounts of these elected local bodies, we would be able to, at least, ensure a measure of success instead of finding that Shri N.K. Singh's money for this fund suffers exactly the same fate as all other money sent from Delhi, which is 85 paisa on administrative cost and perhaps 15 paisa reaching the intended beneficiaries. So, the first and foremost, I would say that as Government converts the good intentions of Shri N.K. Singh into a really lively Centrally-sponsored scheme, there must be an absolute insistence that the provisions of Part IX of the Constitution, and in so far as tribal areas are concerned, the Provisions of the Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, 1996 are strictly conformed to. Without any such attention to the delivery mechanism, any kind of fund, including the fund now proposed, will simply not serve a constructive purpose. So, I would urge, Sir, the present Minister for Environment and Forest to revisit along with his current colleague, the

Minister of Science and Technology, the policy that was elaborated by the previous Government and try to see how it can be given teeth by making the local communities, through the Gram Sabhas and local institutions of governance through the Panchayats and in the urban areas, the municipalities and other urban local bodies, responsible within the community itself as also capable within the community itself to deal with these questions of environmental degradation which are so intimately connected to development issues.

The second lacunae, if I may say so, in Shri N.K. Singh's proposal is that while it does recognize the need for external financing, it has not, I think, adequately explained how such external financing might be made available globally in an equitable manner. There is reference in the remarks made by Shri N.K. Singh while moving this Resolution as to the scale on which funding would be required. It runs into billions of dollars; it runs indeed into hundreds of billions of dollars, but hundred of billions of dollars over a period of time. What is immediately required is the means to ensure that any form of development, that takes place henceforth, is based on the most environment friendly technology that is available. Twenty one years ago, Sir, I stress this, almost a generation ago, one of the more enlightened Prime Ministers of India, a young man, called Rajiv Gandhi, led the Indian Delegation to the Tenth Non Aligned Summit in Belgrade and in September 1989 made a proposal which the Government of India appears to have totally forgotten ever since. Since the talks in the climate change negotiations are in many ways deadlocked, I do believe that even though over the last ever since the Earth Summit, there has been no particular reference to the

proposal made by the then Prime Minister, Rajiv Gandhi, except in a glancing manner at the Earth Summit in 1992, where our delegation was led by the then Minister of State for Environment and Forests, Shri Kamal Nath.

(Contd. by ysr - 3E)

-SK/YSR/4.15/3E

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (CONTD): It is still possible to revive the essence of the idea. And I believe it is our national duty to promote it, partly to give teeth to the proposal made by Shri N.K. Singh but much more than that to ensure on the ground that whether it is the fund proposed by Shri N.K. Singh or any other mechanism that is devised by the Government, we do have the kind of international support necessary to ensure that in addition to whatever is the domestic Indian effort, which is really the focus of Shri N.K. Singh's proposal, whatever is the best environment-friendly technology available anywhere in the world or which has been made available through the history of development of technology, is made available to our industrialists, to our workers, to our farmers, and to our *kheti mazdoor*. And it was this that Rajiv Gandhi reflected on when he went to Belgrade in September of 1989.

Sir, with your permission, I would like to read into the record of the Rajya Sabha. It is a speech or a part of speech which has been allowed to simply gather dust for the last 21 years. What Shri Rajiv Gandhi said I am quoting from that speech.

"We need a global effort to bring within the easy reach of all, developing and developed, the technologies that exist and are yet to be developed to combat

pollution and environmental degradation. We cannot leave these matters to the mere play of market forces. Those with inadequate capacity to pay for environmentally-sound technologies would then be left with no alternative but to let development proceed without due regard for the environment. Equally, those who are denied access to such technologies would have no option but to fall into the same trap. It is not only these countries that will pay the price of environmental neglect, it is a price that will probably have to be paid by the world as a whole and by future generations. The international community has a common stake in sustainable development. We need global effort to ensure access to environment-friendly technologies and the funding of research and development into such technologies."

I am sure Shri N.K. Singh will acknowledge that what Rajivji said in Belgrade supplements and expands the fundamental point that he is trying to make. So, Rajiv Gandhi came to this conclusion by saying this.

"With these ends in view, I propose the establishment of Planet Protection Fund (PPF), under the aegis of the United Nations. The Fund will be used to protect the environment by developing or purchasing conservation-compatible technologies in critical areas which can then be brought into the public domain for the benefit of both developing and developed countries."

I now request the House to pay particular attention to the next sentence.

"All technologies over which the Fund acquires rights will be made available gratis, and without restriction, to all constituent members of the Fund. I would wish to stress that contributors to and beneficiaries of the Fund would

include not only developing countries but also the industrialized countries. We would wish to work towards universal membership of the Fund."

He further said, "We propose that all constituent members of the Fund, developed and developing, contribute a fixed percentage of their Gross Domestic Product (GDP) to the Fund with exemption but full access granted to the least developed countries. The annual contribution to the corpus of the Fund would be around $18 billion at as low an average contribution as of 0.1 per cent of GDP."

Now I need at this point to mention to the hon. Minister for Environment and Forests that in response to Starred Question No.1 posed by me on 26th of July...

(Contd. by MKS/3F)

MKS--SC/4.20/3F

SHRI MANI SHANAKR AIYAR (CONTD.): ....which, unfortunately, the House could not take up because we were expressing sorrow on the death of serving Members. By mistake, it is done. I presume, it is a typographical error. It says '18 million dollars'. It wasn't. It is '18 billion dollars'. That was calculated 21 years ago. But, today, that amount would be much, much more than 18 billion dollars. We were talking of 0.1 per cent contribution of GDP. It is not beyond human ingenuity to negotiate this percentage to a much higher figure than to 0.1 per cent. Why not 0.7 per cent? That would, automatically, increase by seven times the figure, what it was. That was, broadly, calculated, at the back of the envelope, by Shri Rajiv Gandhi 21 years ago.

Then he says:

"That is, for environment-related work, the international community would have, at its disposal, as significant a sum as eighteen billion dollars a year if only each country were willing to part with but a one-thousandth part of its GDP."

"Such a Fund would become the fulcrum for a truly co-operative global endeavour to measure up to a problem of global dimensions and global implications. Such a Fund would be a proof of our commitment to saving all creation and our planet Earth."

Here is a complete suggestion which we have just put to one side. There is an endless discussion going on between the developing and the developed countries on how to deal with the issue of Climate Change. The negotiations, despite the best efforts of our Minister of State for Environment and Forests to create a Chin India Block and to extend it to other developing countries, while noble in itself, is running into impossible difficulties. I suggest that it is part and parcel of breaking the deadlock in which we find ourselves. We try and float an idea promoted by a Congress Prime Minister of India 21 years ago instead of letting it on the wine as has been happening all the time. I would particularly wish to draw the hon. Minister's attention to the basic principle on which this proposal was based. That basic principle came a few paragraphs before he made the proposal, in which Shri Rajiv Gandhi said:

"Much of the blame for the depletion of the ozone layer, for global warming, for the dumping of hazardous wastes, and for deforestation lies at the door of the industrialized countries. Their high levels of consumption and production not only strain available natural resources but also lead to an alarming emission of pollutants into the atmosphere. The main

responsibility and burden for combating pollution and environment degradation must necessarily be theirs. The Polluter Pays Principle must apply."

So, there is no contradiction, Sir, in maintaining the Polluter Pays Principle, which is at the heart of the stand taken by India, and other countries, noble countries, at these International Climate Change Negotiations, but, it is, in fact, totally in conformity with the completely practical way of giving an international dimension within which the domestic dimension, addressed by Shri N.K. Singh, would fit in perfectly like a hand into a well-knit glove. I don't think we have the resources. I just don't think we have the resources, because we have to run the Commonwealth Games and other such important international events, to be able to fund this. There would be a serious danger if we had this kind of a fund. It may suffer the same fate as the Special Component Plan for the Scheduled Castes, which has now found its way into the Commonwealth Games. All these dangers are there. But if you have a programme which measures in to an international programme of totally practical dimensions where everybody is contributing, everybody except the least developing countries, the same share of GDP, ...

(Contd. by TMV/3G)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (CONTD.): ... but not the same amount of money because quite clearly the share, in absolute terms, of developed countries like the United States or a country more advanced than us like China will be much more than what we are contributing. But in terms of securing an equitable outcome rather than equity, which is the point being constantly stressed by the Government of India representatives in these climate change negotiations, it is perfectly okay to say that we will give the same share of our lower GDP as somebody else who has a much higher GDP. So, we are not abandoning the polluter pays principle and we are not abandoning the principle of equitable treatment. We are not shirking our international obligations. We are bringing in those with international obligations too such as the developed countries into the exercise. There is a suggestion here which seems to me to be eminently practical that we make available a huge bag of environmental technologies *gratis* to everybody around the country and we take as much of this as required down to the communities where they live so that these get adapted and implemented at the grassroots. If you measure all these and if you don't get stuck in merely the scientific aspects of climate change, but take into account the governance realities of our country and ensure a form of funding which will provide the resources that are required to be bale to meet the huge global challenge, the worst effects of which will be on countries like ours, there I see a way forward.

So, I urge the hon. Minister of State for Environment and Forests to kindly take a re-look at the National Policy on Climate Change, adapt it to the provisions

of Part IX of the Constitution and the provisions of the Panchayat Extension (Scheduled Areas) Act, and just revisit the Planet Projection Fund proposed 21 years ago by Prime Minister Rajiv Gandhi. Then, you marry it with what has been proposed by Shri N. K.Singh and, I think, we will find an India-friendly answer to the menace of climate change as it affects our country. Thank you.

(Ends)

SHRI V. P. SINGH BADNORE (RAJASTHAN): Mr. Vice-Chairman, Sir, undoubtedly, the subject under discussion and the Resolution put forth by Shri N. K. Singh is of immense importance. Before I go into the details let me say that if we go word by word we will be able to really see what the Resolution is focussing on and what Shri N. K. Singh wants. Sir, firstly, the Resolution says, "Let this House resolve to constitute an Environment Adaptation and Mitigation Fund". Basically, we are talking about Environment Adaptation and Mitigation Fund. For what purpose? It further says, "by innovative fiscal policies to finance". It goes into the finance part, the funding part and how we are really going to get it to meet the cost of technology. Now the technology can be indigenous, R & D in our own country, also what the technology is as per the international best practices and the cutting edge technology which is being proposed by the international community. Then we go into the renewable energy.

(Contd. by 3H/VK)

VK/3H/4.30

SHRI V.P. SINGH BADNORE (CONTD): Then we go into the renewable energy. What I feel here, the crux of the whole thing is the renewable energy. Because it

is not just a subject of the MoS of Environment and Forest who is present here, it is more on the power, renewable energy and how best we can, with the indigenous and the technology that we can get from abroad, go forward to really see that we power the hundreds and thousands of villages even in the 65th year of our Independence, which still do not have electricity or still do not have access to electricity. This is exactly what we are talking about. If we go into other things also, then we can go to adaptation arising from global warming and climate change. If we really have to talk about global warming, climate change, then all this is a very, very large subject. It is a subject which we have been talking about for very many decades now, from the Kyoto Protocol, all the way to Copenhagen and now the Minister will be going to Mexico to really talk about it. I will put some of my suggestions here and I will concentrate on the renewable energy part of it because if I go and start with what funding, how much funding is required, what we can do about it and also if I start talking about the commercial angles that these advanced countries have; one of the things that is being proposed is that the orthodox, the conventional energy that we are putting forth through thermal energy power plants, which have very little PLF, is that, we do not have the best coal available. We can go into details of it. But I will just concentrate on the renewable energy and also the commercial angle of the CCS that we are proposing - Carbon Capture and Storage. Now this has never been tried in even their countries and they are proposing that the Third World and the countries like India and China must adapt the CCS which is even 20 to 25 per cent higher than the state-of-the-art technical new technologies of thermal generation. Sir, when

we talk about the renewable energy, have we really looked at the potential that this country has, the potential that the neighbouring countries have? Have we really tapped them? If we really look into that, the potential is enormous. There is hundreds thousand megawatt potential from our neighbouring countries, from our country from the States that we have in Himachal, Uttarakhand, Kashmir, Jammu, Leh, Ladakh and if we even tap those, I think all the hundreds and thousands of villages which are still not electrified, can be electrified. I have a small suggestion. I don't know if we have talked also because we do not really have many perennial rivers. Also, like in Rajasthan, we have the IGNP - Indira Gandhi Nahar Pariyojna. Have we really looked into the technology of the low head hydel small little power plants that can be really put there in numbers which can be in thousands and thousands, and with very low head they can be functioning and we can really get energy out of it.

(Contd. By 3J)

RG/4.35/3J

SHRI V.P. SINGH BADNORE (contd.): Sir, there was a time when Germany had done away with lignite energy. But they have revisited that, and they have been able to develop a new technology. Now we have abundance of lignite in our country. That lignite research, made by countries like Germany can be used here, and we can have a lot of energy from that. That is still tapped.

Now, when I talk about solar energy, it is a fact that the Western countries do not have the sunlight that we have in our country. And, I think, the Third World Countries, that have sunlight, are not interested in giving it to us because they fear

that if we generate electricity through solar energy, then, they will not be able to put their commercial agenda on things like the CCS, which they propose, and on which they want to make lots and lots of money. I have another very small suggestion; of course, the Power Minister is not here. For a large country like India, why should we not have two sets of timings? We can have winter timing and summer timing. Now, if we have two timings, say, one particular time in Delhi and a different time in Kolkata, then, the peaking hour will be different and we can save electricity in the country. We will have two peaking time, and that can, really, help us save the daylight. That is my suggestion.

Sir, we have talked about carbon credit. We have also talked about this fund. But I would want to know from the Minister of Environment and Forests, that when there is also the CAMPA Fund, which is huge in amount, whether we have really utilized that. What was this fund collected for? This is the problem. If we have a new fund, then, its implementation, that is, how it is going to be utilized and where it is going to be utilized, should also be looked into. Otherwise, even when we have the fund, we do not know whether it is really going in the direction that we are talking about, that this legislation is talking about. Most importantly, I feel that when our Minister goes to Mexico, we should lead the Third World Countries, the developing countries. We should have a policy of our own. We can also talk to China because problems, which China and our country, are facing are similar. And the Minister has been talking about it. But whenever the Minister talks about something different, there are people who jump at it. They feel that he is talking something which is not his subject, which is not good for the country. I

feel that we should give him an opportunity. When we look at the amount of work that he has done for the conservation of tiger and deforestation, I think, no other Minister, in the last many decades, has been able to do it. And, I congratulate him. Thank you very much.

(Ends)

(Followed by 3K)

LP-KS/4.40/3K

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय विद्वान सदस्य श्री एन.के. सिंह द्वारा प्रस्तुत यह जो रिजोलूशन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग, मौसम के परिवर्तन, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव और प्रदूषण ये ऐसे विषय हैं, जिन पर आज पूरा विश्व चिंतित है। जो कई पर्यावरणविद् विद्वान हैं, वे इस पर बराबर चिंतन-मनन कर रहे हैं, मौसम के हालात की समीक्षा कर रहे हैं, उससे बचने के उपाय खोज रहे हैं। ऐसे समय में भारत एक बहुत बड़ा विकासशील और चिंतनशील देश है। हमारे माननीय मंत्री जी भी स्वयं पर्यावरण के प्रति काफी जागरूक हैं। वे बड़ी जागरूकता के साथ इस दिशा में अपने पूरे प्रयासों से अनवरत कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में, अपने रेजोल्यूशन में जो सुझाव दिया है, "to constitute an Environment Adaptation and Mitigation Fund by innovative fiscal policies to finance the cost of technology, promote research and development of renewable energy and lower the burden to meet the inevitable costs of adaptation arising from Global Warming and Climate Change".

यह जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, इसके समाधान के लिए कुछ रिसर्च किया जाए और कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए जाएं, जोकि प्रकृति के ज्यादा नजदीक हों, प्राकृतिक हों, जिनसे कम लागत पर इस तरह के परिणाम निकल सकें कि हमें इस ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण से किस तरह से रिलीफ मिल

सके, राहत मिल सके। मैं उनकी इस भावना की प्रशंसा करती हूं, समर्थन करती हूं। मेरे विद्वान साथियों, माननीय संसद सदस्यों ने अनुभव के आधार पर अपने जो विचार रखे हैं, मैं उन सबका स्वागत करते हुए, इस विषय में अपने कुछ विचार सदन में प्रस्तुत कर रही हूं। महोदय, इस विषय में चिंता करते हुए कई बार, पूरे विश्व के पर्यावरणविद् विद्वानों ने कई सम्मेलन किए, कई मीट्स हुईं, अर्थ समिट्स हुए, लेकिन पर्यावरण और इस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए खतरे से फिलहाल कोई पुख्ता निष्कर्ष नहीं निकल सका। सर, यह बरसों के विकास की देन है। जो पश्चिमी विकसित देश हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा तकनीकी विकास, बहुत ज्यादा मशीनी विकास पर जोर दिया और इस दिशा में बड़े जोरों से कार्य भी किया। उन्होंने बहुत बड़े-बड़े सराहनीय कार्य किए, लेकिन उसके दूरगामी प्राकृतिक दुष्परिणामों की चिंता नहीं की, जिसके कारण ही आज पूरे विश्व को इस ग्लोबल वार्मिंग से जूझना पड़ रहा है। जो ओजोन लेयर थी, वह छिन्न-भिन्न हो गई है। यह इसी तरह है, जैसेकि विश्व में अगर कोई देश सोचे कि जब यह खतरा बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्री जल स्तर ऊंचा उठ रहा है, यह विश्व के लिए एक चेतावनी है, खतरा है, अगर समुद्र में किसी जहाज में छेद हो जाता है, तो उसमें बैठने से कोई यह सोचे कि चूंकि, हमने यह जहाज बनाया है, इसलिए हम लोग बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, पूरा जहाज डूबता है। यह चिंता पूरे विश्व की है।

(AKG/3L पर जारी)

AKG/3L/4.45

डा. प्रभा ठाकुर (क्रमागत) : इसमें जिन पाश्चात्य देशों का ज्यादा योगदान रहा है, जिनके कारण यह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, ये खतरे बढ़े हैं, उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है कि इसे कम करने में वे अपना ज्यादा योगदान दें, इसके लिए ज्यादा प्रयत्नशील रहें और इस पर पूरे रिसर्च के कार्य करें। हमें भी आवश्यकता है कि एक ऐसा fund generate किया जाए, जिससे

इस तरह के रिसर्च हों कि किस प्रकार इन बढ़ते हुए खतरों से हम मुक्त हो सकें और उनसे बचाव कर सकें।

महोदय, अगर अप्राकृतिक संसाधनों से कुछ सुविधाएँ मिलती हैं, तो उनके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी निश्चित रूप से होते हैं। जब भी हम प्रकृति के विपरीत कोई कार्य करते हैं, कोई विकास करते हैं, जो प्रकृति के मिजाज के अनुकूल नहीं होता, तो हमें उसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह वैसी ही स्थिति है, क्योंकि विकास के नाम पर यह ध्यान नहीं रखा गया कि हमें प्रकृति को कहीं disturb नहीं करना है। जब हम कोई भी विकास करते हैं, तो उससे पहले मनुष्य जाति के विकास का ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य जाति, यह विश्व, ये जीव-जन्तु, यह प्रकृति अगर सुरक्षित रहेगी, तो सब सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा इस तरह के विकास से अंततः उसके दुष्परिणाम ही हो सकते हैं।

आज carbon trading जैसा एक funny शब्द, जो बड़ा ही अमानवीय और असंवेदनशील शब्द है, सामने आया है। अगर कोई मुल्क carbon trading की बात कहता है, तो हैरानी होती है कि यह कितनी अमानवीयता की बात है। उन्हें इसका कोई तोड़ निकालना चाहिए। वे developed nations हैं, उनके पास बहुत पैसा है। उन्हें कोई ऐसी रिसर्च करनी चाहिए कि क्या कार्बन को किसी प्रकार से clean करके इसके प्रदूषण के प्रभाव को कुछ कम किया जा सकता है और क्या कोई ऐसी प्रक्रिया बनाई जा सकती है। लेकिन carbon trading जैसी बात असंवेदनशील है, जो शायद किसी के भी गले उतरने वाली बात नहीं है।

महोदय, अप्राकृतिक संसाधनों से हमें एयर कंडीशनर्स की, रेफ्रिजेरेटर्स की सुविधाएँ मिलीं। परमाणु परीक्षण हुए, सुरक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर। ये भी प्रकृति पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव तो डालते ही हैं, क्योंकि ये अप्राकृतिक हैं। पूरे विश्व में करोड़ों की तादाद में गाड़ियाँ चल रही हैं। भारत में भी पिछले 10-15 वर्षों में कितनी गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। जितनी आबादी नहीं बढ़ी है, उससे ज्यादा गाड़ियाँ बढ़ी हैं। इतना डीजल-पेट्रोल, इतना धुआँ, इनसे इतना प्रदूषण हो रहा है। इन पर कैसे रोक लगेगी? अगर चंद सीएनजी की किट्स लगा कर

कुछ गाड़ियाँ चला दी जाएँगी, तो उनसे समाधान नहीं हो जाएगा। ये जो ट्रक चलते हैं, जो इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, जब तक ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं हो कि डीजल का कोई सीएनजी जैसा alternative हो, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि बढ़ती गाड़ियों पर कैसे नियंत्रण लगाएँगे? जितनी सड़कें नहीं बनती हैं, उतनी गाड़ियाँ बन जाती हैं। जितनी पुलियाँ नहीं बनतीं, उतनी गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं। अभी और सस्ती गाड़ी लाने की होड़ मची हुई है, तो जो कोई अभी दुपहिया वाहन चला रहा होगा, वह भी गाड़ी लेकर चलेगा। सड़कों पर चलने की जगह ही नहीं बचेगी। सर, ऐसे में कोई substitute होनी चाहिए, ऐसी कोई रिसर्च होनी चाहिए, जिससे प्रदूषण न हो और प्रदूषण में कमी हो। ओजोन लेयर, जो सूरज की भयंकर गर्मी से बचाने के लिए, प्रदूषण के दुष्परिणामों से बचाने के लिए, रोकने के लिए पूरे विश्व की ढाल थी, उस ढाल में दरार आ गई है।

(3एम/एससीएच पर जारी)

SCH/4.50/3M

डॉ. प्रभा ठाकुर (क्रमागत): इसलिए सूरज का सीधा ताप उन देशों को ज्यादा सहना पड़ रहा है, जो पहले से ही गर्म देश हैं, जैसे भारत। इन देशों में इतनी भयंकर गर्मी हैं।

महोदय, कई गांवों में तो स्थिति यह है कि बिजली कट जाती है, लेकिन उनके पास ऊर्जा का कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जैसे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। आगे हम उम्मीद कर रहे हैं कि परमाणु एनर्जी भी आ जाएगी। परमाणु करार के बाद इस देश को और इसके देशवासियों को एक बड़ी उम्मीद हुई है। जब ये संसाधन मिलेंगे तो गांव के लोगों को भयंकर गर्मियों में कुछ राहत मिलेगी। मैं कहती हूं कि आज कूलर जैसी चीज़ सुविधा का साधन नहीं रह गई है। एअरकंडिशनर भले ही सुविधा का साधन हो सकते हैं, लेकिन गर्मी इस कदर बढ़ गई है कि कूलर आज एक जरूरत बन गया है। कई शहरों और गांवों में बिजली की कटौती के कारण घंटों-घंटों तक पंखा भी नसीब नहीं होता है। वे किस तरह जी सकते हैं?

इसलिए ऊर्जा के जितने भी प्राकृतिक संसाधन विकसित होंगे, उतना ही मनुष्य जाति को, जीव-जंतुओं को एवं वनस्पतियों को, सभी को लाभ होगा।

महोदय, प्रदूषण से वायु, जल और कृषि अथवा वनस्पति सभी प्रदूषित हुए हैं। इन तीनों पर ही जीव-जंतुओं और मनुष्यों का जीवन आधारित है। यही उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। ऑक्सीजन अथवा हवा, पानी और कृषि अथवा वनस्पति पर ही हम सभी का जीवन निर्भर करता है। पेड़-पौधों पर मानसून भी निर्भर करता है। अगर यही स्वच्छ नहीं रहेंगे, प्रदूषित हो जाएंगे, तब अखिर हम कैसे जीएंगे? आज लोग तरह-तरह की सैकड़ों बीमारियों से ग्रस्त हो करके तकलीफें भुगत रहे हैं। इलाज भी इतना महंगा है, तो आखिर वे कहां जाएं? सरकारी अस्पतालों में भी लम्बी-लम्बी लाइनें हुआ करती हैं, आखिर वे कितने दिन तक इंतजार करें? महंगा इलाज करवाने के लिए पैसा कहां से लाएं? ये सब इस पर्यावरण पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के कारण ही हो रहा है।

पर्यावरण क्या है - वायु, जल, कृषि एवं वनस्पति, लेकिन ये सभी प्रदूषित हो गए। मनुष्यों और जीव-जंतुओं का जीवन इनसे ही चलता है। अगर सभी प्रदूषित पानी पी रहे हैं, प्रदूषित अन्न खा रहे हैं, प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, तो बीमारियां तो होंगी ही। इसलिए अपने जीवन के अस्तित्व के लिए, विश्व के सारे जीवों के जीवन के लिए, वनस्पतियों के लिए, इससे बचना बहुत जरूरी है।

महोदय, बिना सोचे समझे पहाड़ के पहाड़ वीरान कर दिए गए हैं। जहां पर किसी जमाने में बहुत से पेड़ हुआ करते थे, सघन पेड़ हुआ करते थे, लोगों ने अथवा माफियाज़ ने उन पेड़ों को काट दिया। लेकिन पेड़ लगाने की जिम्मेदारी वे क्यों समझेंगे? बरसों पहले सरकार ने भी इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। कभी-कभी तो ऐसा भी किया गया हैलीकॉप्टर से बीज डाले गए कि साहब, हैलीकॉप्टर से बीज गिराए जा रहे हैं और पेड़ लग जाएंगे। पेड़ लगाने के लिए आन्दोलन भी चलाए गए। अरे भई, पेड़ आप कैसे लगाएंगे? इतना बड़ा पेड़ कैसे लग सकता है? पौधे लग सकते हैं। अभियान कुछ इस तरह से होना चाहिए - "पौधे

लगाओ और पेड़ बचाओ"। लेकिन पौधे लगा दिए गिनती के, टार्गेट दे दिया कि इतने लगेंगे और कागजों में बता दिया कि इतने पेड़ लगा दिए गए हैं। आखिर उनमें से विकसित कितने हुए और पेड़ कितने बने, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए।

महोदय, जंगल के पेड़ों की मॉनिटरिंग जवाबदेही के साथ होनी चाहिए। हमारे यहां जन-बल की कोई कमी नहीं है, मैन पावर की कोई कमी नहीं है, अधिकारियों की कोई कमी नहीं है, हर विभाग में लोग भरे हुए हैं। अगर वे अपनी-अपनी जिम्मेदारी को समझ लें तो यह समस्या ही न पैदा हो। आज इतने वन्य जीव - अभ्यारण्यों में ही मार दिए जाते हैं। वे क्यों मार दिए जाएं?

3n/psv पर जारी

-SCH/PSV-KLS/3N/4.55

डा0 प्रभा ठाकुर (क्रमागत): वे क्यों मर जाएँगे, क्योंकि उनके लिए कोई जवाबदेही नहीं है। कोई अधिकारी इसकी जवाबदेही किसी दूसरे पर डाल देता है और वह किसी अन्य पर डाल देता है। तब कहा जाता है कि इसके लिए कोई नया कानून ले आइए, नया विधेयक ले आइए। सर, नए कानूनों से क्या होगा? आज इतने सारे जो कानून हैं, वे पर्याप्त हैं, लेकिन, ये तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकते जब तक पहले लोगों की जवाबदेही निर्धारित न हो कि वहीं-की-वहीं सजा और वहीं-का-वहीं निस्तारण। अगर ऐसा हो जाए, तो इस तरह की तमाम चीजों में अपने आप कमी आ जाएगी। कौन आगे जाए? कोर्ट तक जाओ, वकील करो, महँगी कानून की लड़ाई लड़ो, लम्बी कानून की लड़ाई लड़ो, कितने वर्षों तक इंतजार करो। इतनी महँगी कानून की लड़ाई, इतने लम्बे समय का इंतजार। इन कानूनों से क्या होगा? महोदय, इसलिए हर विभाग की जवाबदेही सुनिश्चित हो। चाहे वह वन विभाग हो, पर्यावरण विभाग हो या जल विभाग हो, इन सब की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी और जब तक उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकता, क्योंकि जब तक किसी को अपने पेट पर लात नहीं पड़ेगी तब तक उसे किसी दूसरे का दर्द समझ में नहीं आएगा।

इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि अधिकारी अपने अधिकारों के प्रति तो सजग रहें कि ये उनके अधिकार हैं, लेकिन उनके कर्त्तव्य क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, अगर उनके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं, तो फिर कौन जिम्मेदार है? फिर उसके लिए आप कोर्ट में जाएँगे। उसके बाद आप कितने दिनों तक इंतजार करेंगे और कितना पैसा लगाएँगे? इस तरह यह भी एक अच्छा उपाय है, जिससे कई चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है।

महोदय, आज मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि मैंने जैसा देखा है कि काले-काले प्लास्टिक के बड़े-बड़े बैग्स में कचरा भरकर समुद्र में डम्प कर दिया जाता है। आखिर उसके क्या दुष्परिणाम होंगे? क्या किसी रिसर्च से ऐसी कोई प्रक्रिया बन सकती है कि उस कचरे को रिसाइकिल करके उससे कहीं किसी तरह का खाद बनाया जा सके, क्योंकि अगर उसको जलाते हैं, तब धुआँ उत्पन्न होता है और इस पर लोग कहेंगे कि इससे प्रकृति में प्रदूषण फैलेगा। प्लास्टिक की जो थैली है, अगर उसे पानी में डूबोते हैं तो प्लास्टिक पानी में गलता ही नहीं, पता नहीं, सौ वर्षों तक यूँ ही बना रहता है, तो इससे पर्यावरण का क्या हाल होगा? इस दिशा में प्लास्टिक की थैलियों पर रोक एक बहुत आवश्यक कदम है। कई जगह लोग कहते हैं कि बड़ी थैलियों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन छोटी थैलियों पर नहीं। सब्जी वाले के पास प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, खाद प्लास्टिक की थैलियों में आ रहा है और पेस्टिसाइड्स भी प्लास्टिक की थैलियों में आती हैं। सर, अगर प्लास्टिक की थैलियाँ किसी उपजाऊ जमीन में डाल दी जाएँ तो वह जमीन बंजर हो जाती है, इसका इतना बुरा असर है। हम फ्रिज में पानी भी प्लास्टिक की बोतलों में रखते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जब ये प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं थीं, तब भी तो लोग थैला लेकर सब्जी मंडी से सब्जियाँ लाने जाते थे। जब इन पर रोक लग जाएगी, जब प्लास्टिक पर रोक लग जाएगी, तब उनको वही अभ्यास दोबारा हो जाएगा। जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी, तब तक उसका सबस्टिट्यूट कैसे आएगा? वह आ ही नहीं सकता, क्योंकि वह एक आसान-सी सुविधाजनक चीज है। प्लास्टिक के निर्माण पर सख्ती होनी चाहिए। यह नहीं कि थैलियाँ क्यों मिल रही हैं, लोगों को

पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, बल्कि जहाँ इनका निर्माण हो रहा है, वहाँ रोक लगनी चाहिए, ताकि ये निर्मित ही न हों और इससे वे बाजार में ही न आएँ। क्या पहले प्लास्टिक के बिना दुनिया नहीं चल रही थी? जब प्लास्टिक की थैलियाँ ही नहीं थीं, तब क्या लोग बाजार नहीं जाते थे और क्या वे वहाँ से सामान लेकर नहीं आते थे? तब ऐसी कई चीज़ें थीं, जैसे जूट के कट्टे थे, जूट के बैग्स थे और कई तरह के थैले भी लोग अपने घरों से ले जाते थे और सामान ले आते थे। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक भी एक बहुत बड़ी दुश्मन है, इसलिए इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

(3ओ/डी0एस0 पर क्रमशः)

-PSV/DS-SSS/5.00/3o

डा. प्रभा ठाकुर (क्रमागत): जगह-जगह पर जो कचड़े के ढेर हैं और जिन्हें नष्ट करने के लिए पानी में डुबोया जा रहा है, उसका कोई उपाय खोजा जाए।

महोदय, पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी स्वयं पर्यावरण के प्रति बहुत चिंतित थे। उनका यह एक प्रिय विषय था और इसको लेकर वे बहुत ज्यादा concerned रहे। इस विषय में उन्होंने कई बातें कहीं और नीतियाँ बनायीं। गंगा जल को स्वच्छ करने की योजना उन्होंने ही बनायी ताकि गंगा जल साफ हो जाए, लेकिन 500 करोड़ रुपये साफ हो गये और गंगा का जल वहीं का वहीं रह गया। सर, यह जिम्मेदारी किसकी है? इतना-इतना रुपया दिया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। इतनी जगहों पर पौधे लगाने के लिए रुपये दिए जाते हैं, लेकिन पेड़ नजर नहीं आते हैं। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसमें मॉनिटरिंग और जवाबदेही दोनों साथ चले और उसके लिए सज़ा का कोई प्रावधान हो। ऐसा नहीं हो कि सब अधिकारी मिल कर एक-दूसरे को बचाने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक पर आँच आयी, अब दूसरे पर न आये। इस तरह से उनका नेटवर्क इस देश में चलता है और बदनाम कौन होता है, जब देखो तब ले-देकर एक नेता होता है। जैसे "नेता" शब्द नेता नहीं रहा, गाली हो गया। लोग इस तरह से समझने लगते हैं। एक अकेला सांसद क्या करेगा?

एक कलैक्टर के पास जितने स्टाफ होते हैं, एक जिले में संबंधित विभागों के इतने अधिकारी होते हैं, लेकिन हर बात की गाली एक एम.पी. या एम.एल.ए. को पड़ती है। अगर वहाँ उसकी सरकार न हो तो प्रशासन में कई बार उसकी सुनवाई तक नहीं होती है जबकि जिम्मेदार उसे बनाया जाता है। महोदय, जो जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और उनको जिम्मेवार ठहराने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, आज छोटी-छोटी जगहों पर, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ किशनगढ़ और पाली में, जहाँ छपाई और रँगाई के कारखाने हैं, जो कि उस शहर या गाँव के एकदम पास हैं, वहाँ का रंगीन गंदा पानी उस तालाब में जा रहा है, जिसका पानी लोग पीते रहे हैं। इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे कारखाने, जिनसे इतना प्रदूषण होता हो, जिनसे पानी प्रदूषित हो रहा हो या वायु प्रदूषित हो रही हो, उन्हें कम से कम उन बस्तियों, आबादियों या गाँवों से कहीं दूर ले जाने की जरूरत है। इस बात को देखने की जरूरत है।

आज कीटनाशकों को जरूरी समझा गया है। हमारे जो कृषि संबंधी उपज हैं, उनमें कीड़े न लगें, इसके लिए pesticides को जरूरी समझा गया है। अब ये pesticides भी पर्यावरण के लिए ऐसे घातक बन गये हैं कि वे agriculture को प्रदूषित कर देते हैं। आज हालत यह हो गयी है कि चिड़ियों की संख्या कम हो गयी हैं। आप इसका सर्वे करवा लीजिए कि कितने जीव-जन्तु कम होते जा रहे हैं। जब फसल लहलहाती है तो उसे चिड़िया और किस्म-किस्म के जीव-जन्तु खाते हैं और ये pesticides उनके अंदर slow poison की तरह जाते हैं, इसलिए उनकी संख्या कम होती जा रही है। उनसे मनुष्यों को भी कई तरह की बीमारियाँ होती जा रही हैं। जब उनसे चिड़िया और अन्य पक्षी मर जाते हैं तो मनुष्य के अंदर जाकर वे न जाने किस किस्म की बीमारियाँ पैदा करते हैं। ये pesticides प्राकृतिक कैसे हों? पहले यह कहा जाता था कि नीम के खाद और pesticides हों। प्राकृतिक चीजों के ऐसे pesticides बनें, जिनके विषैले दुष्परिणाम न हों और जो मनुष्य या जीव-जन्तुओं के जीवन

को नुकसान न पहुँचाएँ या कई रोगों के कारण न बनें। मुझे उम्मीद है कि हमारे साइंटिस्ट्स इस तरफ भी कुछ कर पाएँगे और वे इधर ध्यान देंगे।

महोदय, प्रदूषित पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या है। मिनरल वाटर, जो दूध से भी महँगा है और जो इस देश में बिक रहा है, क्या किसी ने कभी ऐसा सोचा भी था? 20 साल पहले अगर कोई यह कहता तो लोग हँसते कि मजाक करते हो क्या, कहीं 20 रुपये का एक लीटर शुद्ध पानी मिलेगा?

(3पी/एनबी पर क्रमशः)

NB/3P/5.05

डा. प्रभा ठाकुर (क्रमागत) : शुद्ध पानी जीवन की पहली जरूरत है। आज हम फूड सिक्योरिटी बिल ला रहे हैं, लेकिन फूड सिक्योरिटी तभी होगी, जब पहले पानी की सिक्योरिटी होगी। हवा के बाद स्वच्छ पेयजल ज़िंदगी के लिए पहली जरूरत है, जब तक वह आदमी को नहीं मिलेगा, जब तक drinking water की सिक्योरिटी नहीं होगी, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। आज इस दूषित पेयजल की वजह से कितने किस्म की बीमारियां फैल रही हैं। गांवों में कभी फ्लोराइड वाला पानी मिलता है, अस्वच्छ पानी मिलता है और गांवों के लोग मैला पानी पीने के लिए मजबूर हैं। वे मिनरल वॉटर खरीदने के लिए कहां से पैसा लाएं या कितनी दूर से स्वच्छ पेयजल लाएं?

उपससभाध्यक्ष जी, एक नदी जल लिंक करने की योजना है कि नदियों को जोड़ा जाएगा, जिससे पानी की समस्या हल होगी। जब मैं Ministry of Science & Technology and Ocean Development की Standing Committee की सदस्य थी, तब मुझे जानकारी हुई और अभी कुछ दिनों पहले एक प्रश्न के जवाब में मुझे यह जानकारी मिली कि समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में 10 पैसे प्रति लीटर की लागत आती है। मैं नहीं समझती कि मनुष्य के जीवन के लिए यह कोई बहुत बड़ी लागत है, जहां हमें हज़ारों रुपए दवाइयों पर बरबाद करने पड़ते हैं। नदी जल लिंक में फिर वही स्टेट्स का झगड़ा आएगा कि यह हमारी नदी है, हम

इसमें नहीं जोड़ने देंगे। कुछ वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि नदियों को जोड़ने के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि वह आप्राकृतिक होगा, unnatural होगा। जैसी मुझे जानकारी है कि अंडमान और चेन्नई जैसी जगहों में ऐसे प्लांट्स लगाए गए हैं, जो समुद्री जल को फिल्टर करके पीने योग्य बना रहे हैं। प्रक्रिया वही है। जैसे सूरज से समुद्र तपता है, फिर बादल बनते हैं, फिर मानसून आता है और बारिश होती है। इसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाकर समुद्री जल से भाप बनाते हैं,उससे मीठा और स्वच्छ पानी आता है। हमारी बहुत सी स्टेट्स हैं, जहां पर समुद्री जल है। अगर गुजरात के समुद्री जल को वहीं स्वच्छ किया जाए और पाइपलाइन के जरिए या नहरों के जरिए उसको राजस्थान तक पहुंचाया जाए, तो राजस्थान में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। इसकी लागत सिर्फ 10 पैसे प्रति लीटर आ रही है। अगर आप subsidies दें, तो ऐसी चीजों पर दें, जो जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो बीमारियों से, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। कितनी ही स्टेट्स हैं, जहां पर यह समाधान हो सकता है। इसमें न नदी जल का झगड़ा पड़ेगा, न यह राज्यों का विषय है। मैं समझती हूं कि इस पर भी एक रिसर्च होनी चाहिए कि किस प्रकार से इसको व्यावहारिक बनाकर इस्तेमाल किया जाए। दुबई में लोग इस तरह से पानी पी रहे हैं। आखिर हम लोग उस प्रक्रिया को क्यों नहीं अपना सकते? हम लोग नाक को सीधा पकड़ने के बजाय उल्टा क्यों पकड़ते हैं? कई लोग ऐसे-ऐसे नुस्खे बताते हैं, जो कि संभव नहीं हैं या उनमें बहुत पैसा लगता है। अधिकारी लोग इस तरह की स्कीमें बनाकर भिजवाते रहते हैं। राज्यों को अगर इंसेंटिव दिया जाए कि जो राज्य प्रदूषण को कंट्रोल करने में, कार्बन को कंट्रोल करने में, पेड़ लगाने में और प्लास्टिक की थैलियां नष्ट करने में प्रथम रहेगा, तो उसका नाम प्रथम घोषित किया जाएगा और उसे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार और फंड देगी। इसलिए स्टेट्स को अगर इस तरह के फंड्स दिए जाएंगे, तो मैं समझती हूं कि कुछ अच्छा काम हो सकता है। इसके अलावा जनजागरण बहुत जरूरी है। लोगों में अवेयरनैस कैसे आए, जागरुकता कैसे आए, इस ओर

ध्यान देने की जरूरत है। टी.वी. और दूरदर्शन ऐसा सशक्त माध्यम है कि उसके द्वारा गांव-गांव तक यह जागरण किया जा सकता है ... (व्यवधान)

(3Q/VNK पर आगे)

-NB/VNK-PK/5:10/3q

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): प्रभा ठाकुर जी, चर्चा आगे जारी रहेगी। गैर-सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए जो समय निश्चित किया गया है, उस समय तक चर्चा आगे जारी रहेगी। सोमवार 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित होता है।

The House then adjourned at ten minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 9th August, 2010.